



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145।

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 29, 2012/चैत्र 9, 1934

No. 145।

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 29, 2012/CHAITRA 9, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

महानिदेशक (रक्षोपाय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2012

विषय : थैलिक एनहाइड्राइड (पीएएन) के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच-अंतिम निष्कर्ष ।

सा.का.नि. 263(अ).—डी-22011/08/2011 दिनांक 29 मार्च, 2012 सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और उसके अंतर्गत बने सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं आंकलन) नियम, 1997 के संबंध में ।

1. प्रक्रिया

1. सीमा-शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं आंकलन) नियमावली, 1997 (जिसे एतदपश्चात् “रक्षोपाय नियमावली” कहा गया) के नियम 5 के अन्तर्गत (1) मै. धिरमलाई कैमिकल्स लिमिटेड, रानीपेट, तमिलनाडु (2) मै. आईजी पैट्रोकैमिकल्स लिमि., रायगढ़, महाराष्ट्र और (3) मै. मैसूर पैट्रोकैमिकल्स लिमि., रायचूर, कर्नाटक द्वारा यह आरोप लगाते हुए कि थैलिक एनहाइड्राइड का बढ़ता हुआ आयात भारत में थैलिक एनहाइड्राइड के घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति कर रहा है और या गम्भीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर रहा है इसलिए भारत में थैलिक एनहाइड्राइड के आयात पर रक्षोपाय शुल्क लगाने की मांग करते हुए एक आवेदन-पत्र दायर किया गया है। भारत में थैलिक एनहाइड्राइड के आयात से संबंधित रक्षोपाय जांच शुरू करने का नाटिम 10 अगस्त, 2011 को जारी किया गया था और उसे, उसी दिन भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इस नाटिम की प्रति सभी ज्ञात हितवद्ध पक्षकारों को भी भेजी गई थी:

घरेलू उत्पाद

क. मै. धिरमल कैमिकल्स लिमि., रानीपेट, तमिलनाडु, ख. मै. आई.जी. पैट्रोकैमिकल्स लिमि., रायगढ़, महाराष्ट्र, मै. मैसूर पैट्रोकैमिकल्स लिमि., रायचूर, कर्नाटक

आयातक

क. कोएलजे प्लास्टीसाइजर्स लिमि., कोएलजे हाउस, 63, रामा मार्ग, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली ।
 ख. पीसीएल ऑयल एण्ड सालवेंट्स लिमि., एम-105, द्वितीय तल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली ।
 ग. सिल्लासा प्लास्ट, कोएलजे हाउस, 63, रामा मार्ग, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली ।
 घ. मेकैमो इण्डस्ट्रीज, 170/6, शिव स्मृति, 27वीं रोड, सायन पश्चिम, मुम्बई, महाराष्ट्र ।

ड. माइक्रो इंक्स लिमिटेड 512/513, मिडस, 5वां तल, शहरप्लाजा कॉम्प्लेक्स, नगर, एम.वी.आर.डी., अंधेरी(पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र।

च. हयूबैच कलर प्रा. लिमिटेड सं0 9002-9010, जीआईडीसी एस्टेट, अंकलेश्वर।

छ. सम्मान ट्रेड इम्पेक्स प्रा० लिटो, 1410, मेकर चैम्बर V, नरीमन प्लाइंट, मुंबई, महाराष्ट्र।

ज. ए-वन कैम ट्रेड प्रा० लिमिटेड, 302, शान्ति हाउस, निकट मधुसूदन हाउस, नवरनपुरा टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, आफ सीजी रोड, अहमदाबाद।

झ. संजय कैमिकल्स (इण्डिया) प्रा० लिमिटेड 507 मातृ छाया, 378/380, नरसीनाथ स्ट्रीट, मुंबई, महाराष्ट्र।

ञ. माजदा कलर्स लिमिटेड एनकेएम इण्टरनेशनल, 178, बैकबे रिक्लेमेशन्स, महाराष्ट्र।

ट. लोना इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, आल्या क्षेत्र, 532, सेनापति बापर मार्ग, दादर, मुंबई, महाराष्ट्र।

ठ. आरती इण्डस्ट्रीज लिमिटेड उद्योग क्षेत्र, द्वितीय तल, मुलुळ, गोरेगांव लिंक रोड, मुलुण(पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र।

ड. रचना प्लास्टीसाइजर्स, प्लाट नं0 116 एवं 117, पिपरिया औद्योगिक क्षेत्र, दादरा नागर संघ राज्य क्षेत्र, सिलवासा।

ढ. थेलो कलर्स एण्ड कैमिकल्स (आई) लिमिटेड, नानावटी महाल्या, 18, होमी मोदी स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र।

ण. रमणिकलाल एस. गोसाला एण्ड कम्पनी नेशनल हाउस 608, बी.जे. माई, जैकब सर्कल, मुंबई, महाराष्ट्र।

त. पैट्रोकेम मिडल ईस्ट (इण्डिया) प्रा० लिमिटेड, 201 बिजनेस स्क्वेयर, बी.किंग, अन्धेरी कुर्ला रोड, मुंबई, महाराष्ट्र।

थ. अम्जे कैमिकल्स, 5-ए, ओल्ड नागरदास रोड, 101 आदिनाथ टोवर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, महाराष्ट्र।

द. हैजेल मर्केन्टाइल लिमिटेड, 181, अशोक शापिंग सेण्टर, द्वितीय तल, जी.टी. हास्पिटल कॉम्प्लेक्स, मुंबई, महाराष्ट्र।

निर्यातक

क. ऐक्यून्न ऐट्रोकैमिकल्स 106-3, गुरो-डांग, गुरो-कू, सियोल, दक्षिण कोरिया।

ख. एनजी पैट्रोकैमिकल्स, 23-4, यूडो-डांग, यांगडुन्गयो-गु, सियोल 150-010, दक्षिण कोरिया।

ग. यूनियन पैट्रोकैमिकल्स (यूपीसी ग्रुप) लिन्युआन प्लांट: 3, कुंग-येह द्वितीय रोड, लिन्युआन, काओहसियंग कण्ट्री 832, ताइवान, आरओसी।

घ. ओसीआई कम्पनी लिमिटेड, 50 सोगोन्ग-डोंग जंग-गु सियोल-100-718, दक्षिण कोरिया।

ड. नान या प्लास्टिक्स, सं० 201, तंग हवा नाथ्ज रोड, ताइपेई, ताइवान।

घ. गाडिव पैट्रोकैमिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड हाहिस्टाइट स्ट्रीट पी.ओ.बी. 32 हाइफा, इजरायल-31000.

निर्यातक राष्ट्र:

क. कोरिया गणराज्य, नई दिल्ली स्थित अपने राजदूतावास के जरिए। ताइवान, नई दिल्ली स्थित अपने राजदूतावास के जरिए।

ग. इरान, नई दिल्ली स्थित अपने राजदूतावास के जरिए।

घ. इजरायल, नई दिल्ली स्थित अपने राजदूतावास के जरिए।

2. उसी दिन सभी जात घरेलू उत्पादकों और आयातकों तथा निर्यातकों को प्रश्नावलियों भी भेज दी गई थीं और उनसे 30 दिनों के अन्दर अपने प्रत्युत्तर भेजने को कहा गया।

3. हितबद्ध पक्षकार मानने के रूप में विचार करने के लिए निम्नलिखित पक्षकारों से अनुरोध प्राप्त हुआ था और सभी अनुरोध स्वीकार कर लिए गए:

घरेलू उद्योग

i. इण्डियन कैमिकल काउन्सिल।

निर्यातक राष्ट्र

i. व्यापार रक्षा निदेशक, इण्डोनेशिया

निर्यातक

i. एल जी कैम लिमि. कोरिया

आयातक

i. इण्डियन प्लास्टीसाइजर्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशनii. पॉलिस्टर रेजिन मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशनiii. इण्डियन पेण्ट एसोसिएशन

4. निम्नलिखित पक्षकारों ने अपने उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया:

i. वीस पोरेट एण्ड कम्पनी, गाडिव पैट्रोकैमिकल्स इजरायल की ओर से (21 अगस्त, 2011 से 30 दिन)।ii. इण्डियन प्लास्टीसाइजर्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन - 4 सप्ताह।iii.

पालिएस्टर रेजिन मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन - 4 सप्ताह।iv. लूथरा एण्ड लूथरा

इण्डियन पेन्ट एसोसिएशन की ओर से – 23 सितम्बर, 2011 से 2 सप्ताह। v. ऐकियुन्ग पैट्रोकैमिकल्स कम्पनी लिमि., कोरिया की ओर से डब्ल्यूटीसी – 30 सितम्बर, 2011 तक।

5. निर्धारित अवधि के अन्दर जाँच पूरी करने के लिए समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए उत्तर देने के लिए समय-सीमा बढ़ाने के अनुरोधों को रक्षोपाय नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, जितना समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया था, उतना समय बढ़ाने की अनुमति दे दी गई।

6. आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी का, घरेलू उत्पादकों के संयंत्रों का जरूरी समझी गई सीमा तक स्थल दौरे करके सत्यापन किया गया। सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय पाठ पब्लिक फाइल में रखा गया है।

7. समुचित निर्णय लेने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सभी विचारों को ध्यान में रखा गया। प्राप्त या अर्जित अगोपनीय सूचना पब्लिक फाइल में रखी गई।

8. शीघ्र जाँच करके, 10% यथामूल्य की दर से अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए प्रारम्भिक निष्कर्ष 23 सितम्बर, 2011 को जारी किए गए थे। 17 जनवरी, 2012 की अधिसूचना सं. 1/2012-सीमा शुल्क (एसजी) के तहत 17 जनवरी, 2012 से 10% की दर से अनन्तिम शुल्क 180 दिनों के लिए लगाया गया था।

9. 18 अक्टूबर, 2011 को सार्वजनिक सुनवाई की गई जिसके लिए 5 अक्टूबर, 2011 को नोटिस भेजा गया। सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी इच्छुक पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के उपनियम (6) में दी गई शर्तों के अनुसार मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतीकरण की प्रति सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई। हितबद्ध पक्षकारों को, अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत किए गए विचारों पर प्रत्युत्तर, यदि कोई, देने का अवसर भी प्रदान किया गया। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लिखित रूप से प्रस्तुत या प्रत्युत्तर के रूप में प्रस्तुत विचारों का परीक्षण किया गया और समुचित निर्णय लेते समय उनको ध्यान में रखा गया।

10. हितबद्ध पक्षकारों और अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों के उत्तर या प्रत्युत्तर के रूप में प्रस्तुत विचारों की जांच की गई और समुचित निर्णय लेते समय उनको ध्यान में रखा गया। चूंकि भारी संख्या में ऐसे हितबद्ध पक्षकार हैं जिन्होंने अपने प्रस्तुतीकरण दर्ज कराए हैं इसलिए उनकी अन्तर्वस्तु और उनसे उत्पन्न मुद्दों का, संक्षिप्तता के कारण किसी हितबद्ध पक्षकार के विशेष नाम का उल्लेख किये बिना समुचित स्थानों पर निराकरण किया गया।

2. **संक्षिप्त इतिवृत्त:** सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं अकास्मा) नियमावली, 1997 (जिसे एतदपश्यात् “रक्षोपाय नियमावली” कहा गया है) के नियम 5 के अन्तर्गत (1) मै0 थिरुमलाई फैमिकल्स लिमिटेड, रानीपेट, तमिलनाडु (2) मै0 आईजी पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड रायगढ़, महाराष्ट्र, (3) मै0 मैसूर पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड रायचूर, कर्नाटक और मै0 एसआई ग्रुप इण्डिया लिमिटेड, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र द्वारा यह आरोप लगाते हुए कि थैलिक एनहाइड्राइड का बढ़ता हुआ आयात भारत में थैलिक एनहाइड्राइड के घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति कर रहा है और/या गम्भीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर रहा है, इसलिए भारत में थैलिक एनहाइड्राइड के आयात पर रक्षोपाय शुल्क लगाने की मांग करते हुए दायर आवेदन पर महानिदेशक (रक्षोपाय) ने एक जाँच शुरू की थी। इस बात से सन्तुष्ट होते हुए कि नियम 5 की अपेक्षाओं की जरूरत है इसलिए थैलिक एनहाइड्राइड के आयातों के विरुद्ध 28 नवम्बर, 2008 के जाँच प्रारम्भ नोटिस के तहत, जिसे उसी दिन भारत के राजपत्र, असाधरण में प्रकाशित करा दिया गया था, रक्षोपाय जाँच शुरू की गई। जल्दी, जल्दी जाँच करने के पश्यात् 1 जनवरी, 2009 को प्रारम्भिक निष्कर्ष जारी किए गए। केन्द्रीय सरकार ने महानिदेशक, रक्षोपाय की सिफारिशों के आधार पर 29 जनवरी, 2009 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 9/2009-सीशु के तहत 29 जनवरी, 2009 से 25% की दर से अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क लगाया। महानिदेशक (रक्षोपाय) ने 29.01.2009 से 28.01.2012 तक की तीन वर्षों की अवधि के लिए निर्णायक रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश करते हुए दिनांक 28 मई, 2009 को सा.का.नि. 366(अ) अनन्तिम निष्कर्ष जारी किया। तथापि, केन्द्र सरकार ने 25% की दर से केवल एक वर्ष अर्थात् 29.01.2009 से 30.6.2009 तक के लिए और 15% की दर से 01.07.2009 से 31.12.2009 तक निर्णायक रक्षोपाय शुल्क लगाया।

3. घरेलू उद्योग के विचार

- क. पाटन का पिछली इतिहास है जिसके कारण निर्णायक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई जिसे कैसर्स्म के आयात पर अधिसूचना सं. 148/2000 के तहत उत्तरवर्ती ढंग से लगाया गया।
- ख. इसके अतिरिक्त, महानिदेशक, रक्षोपाय की सिफारिश पर अधिसूचना सं. 9/2009 और 75/2009 के तहत क्रमशः अनन्तिम एवं अन्तिम रक्षोपाय शुल्क लगाया गया।
- ग. महानिदेशक, पाटनरोधी ने संबंधित वस्तु के पाटन के खिलाफ दिनांक 29 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना के तहत पाटनरोधी जाँच शुरू की।

घ. यिहले विभिन्न मामलों में महानिदेशक, रक्षोपाय वे रक्षोपाय जाँच प्रक्रिया शुरू की, उसी वक्त समानान्तर रूप से पाटनरोधी जाँच भी शुरू हुई अथवा कथित उत्पाद अर्थात् एनटीसीएफ एवं कास्टिक सोडा पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया।

इ. दोहरे उपचारों के संबंध में चीन द्वारा उठाए गए मुद्दों पर यूरोपीय संघ के उत्तर में कहा गया कि रक्षोपाय, पाटनरोधी और इम्दादरोधी सभी तीनों मामलों में जाँच शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें पूरी होती हैं।

ज. डीजी, पाटनरोधी और डीजी, रक्षोपाय द्वारा चुनी गई जाँच अवधि क्रमशः जनवरी-दिसंबर, 2010 और जनवरी-जून, 2011 हैं जो एक दूसरे से भिन्न हैं।

छ. उनमें दोहरे उपचार की नहीं, बल्कि अतिरिक्त क्षति के विरुद्ध केवल राहत की मांग की गई है।

ज. इस स्तर पर रक्षोपाय लगाने के संबंध में भारतीय विधि में कोई रोक नहीं है। रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करारों पर विचार किया जाता है जिससे कि यह करार दो वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले 6 माह के लिए शुल्क लगाने की अनुमति देता है।

झ. केवल अप्रैल-मई, 2011 के दौरान ही आयाती एवं क्षति में वृद्धि नहीं हुई बल्कि अन्य समय में भी हुई परन्तु जाँच की अवधि का निर्धारण जाँच प्राधिकारी (यूएस-लाइन पाइप मामला) के स्वविवेक पर होता है।

ट. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम-1975 के अनुसार याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग हैं क्योंकि उनका भारत में पीएम उत्पादन में प्रमुख हिस्सा जैसा कि नीचे की तालिका में दर्शाया गया है:

क्रम सं.	वर्ष	याचिकाकर्ता	अन्य भारतीय उत्पादक	अखिल भारतीय उत्पादक
1	2007-08	86.05%	13.95%	100%
2	2008-09	89.98%	10.02%	100%
3	2009-10	89.37%	10.63%	100%
4	जनवरी-दिसंबर, 2010	87.24%	12.76%	100%
5	चौथी तिमाही(2010-11)	86.49%	13.51%	100%
6	पहली तिमाही(अप्रैल-जून 2011)	86.23%	13.77%	100%

ठ. एशियन ऐन्डस द्वारा उत्पादन केवल कैप्टिव खपत के लिए है और घरेलू बिक्री इसकी कुल बिजनेस का बहुत छोटा सा हिस्सा है।

ड. फिर्मलाई कैमिकल्स लिमिटेड की एक डिवीजन कैमिकल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी ने पीएएन की अल्प मात्रा (इसके उत्पादन से 0.3% से कम और पीएएन के भारतीय आयात की बिक्री से 0.2% से कम) का आयात घरेलू बिक्री के लिए न करके इसका निर्यात करने के लिए किया था।

ढ. आयातों से कोई घरेलू उत्पादक रक्षोपाय कानून के अन्तर्गत घरेलू उद्योग होने से उसका हक नहीं मार देता है।

ण. पीएएन का आयात रक्षोपाय नियमजावली और अर्जेन्टीना फुटवियर एवं ट्रीट ग्लुटेन मामले के निर्णय के आशय के अन्तर्गत बढ़ा है।

त. सम्पूर्ण क्षति अवधि के दौरान आयातों में आकस्मिक, तीव्र एवं अत्यधिक वृद्धि हुई जबकि वर्ष 2009-10 में, उस अवधि में रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के कारण, आयात में कमी आई।

थ. तथापि, जब रक्षोपाय शुल्क प्रभावी होने की तारीख समाप्त हो गई तो आयात फिर तीव्र गति से बढ़ने लगे।

द. सम्पूर्ण अवधि में और अभी हाल ही की अवधि में उत्पादन और खपत की तुलना में आयातों में वृद्धि हुई है।

क. चीन के उत्पादकों द्वारा नए संयंत्रों की स्थापना करना

ख. विचाराधीन उत्पाद की चीन में कम मांग

ग. यूरोप एवं अमेरिका के बाजारों में मन्दी

घ. कोरिया और ताइवान से आयातों के विरुद्ध पाकिस्तान एवं चीन में पाटनरोधी जाँच

ड. विचाराधीन उत्पाद की भारत में बढ़ती मांग

घ. उपर्युक्त तथ्यों के कारण कोरिया और ताइवान के निर्यातकों को अपने उत्पादों के लिए नए बाजारों की खोज करने के लिए मजबूर होना पड़ा और भारत, सर्वाधिक अर्थक्षम पसन्द होने के कारण, इसे लक्ष्य बनाया गया और इस कारण भारत में आयात बढ़ गए।

ध. आयात बढ़ने से घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम हो गया जिससे उनके उत्पादन एवं क्षमता उपयोग पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

न. घरेलू उद्योग की बिक्री में चौथी तिमाही तक वृद्धि हुई परन्तु हाल की अवधि में इसमें गिरावट आई जबकि आयातों में वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग को, देश में उत्पाद के सतत

बढ़ते हुए आयात के कारण, अपने उत्पादन को, घरेलू मांग होने के बावजूद, निर्यात करने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

प. चूँकि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा आयातों की तुलना में कम हो रहा है, इसलिए इसे संग्रहित इन्वेंट्रीज की समस्या का सामना करना पड़ता है।

फ. अपना बाजार बनाए रखने के लिए घरेलू उद्योग को बिक्री की लागत की तुलना में कीमतें कम करनी पड़ी, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। साथ ही, अभी हाल की अवधि में लाभदायकता और परिणामस्वरूप निवेश पर नगद लाभ और प्राप्तियाँ कम होना शुरू हो गई जो रक्षोपाय शुल्क लगाने के पश्चात वास्तव में बढ़ गई।

ब. निम्नलिखित तथ्यों से गम्भीर क्षति की चुनौती सिद्ध होती है:

- I. घरेलू एवं आयातित उत्पाद में कीमत अन्तराल बहुत अधिक है।
- II. विदेशी उत्पादकों की बहुत सारी अप्रयुक्त क्षमताएं हैं। इस याचिका में उल्लिखित सूचना का उल्लेख किया गया और उस पर भरोसा जताया गया। परिणामतः विदेशी उत्पादक यथासम्भव सीमा तक अतिरिक्त बाजारों की तलाश कर रहे हैं।
- III. थैलिक एनहाइड्राइड के लिए चीन के प्रमुख बाजारों को ताइवान और कोरिया के निर्यातान्मुख उत्पादकों के लिए बंद कर दिया गया जबकि भारतीय बाजार काफी मजबूत हैं।
- IV. चीन और पाकिस्तान ने अपने-अपने देशों में कोरिया और ताइवान से होने वाले आयातों पर पाँच वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगा दिया है। इससे थैलिक एनहाइड्राइड का कोरिया और ताइवान से चीन और पाकिस्तान को होने वाले आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन प्रतिबंधों के कारण उत्पादक/निर्यातक अपने उत्पादों के लिए नए बाजारों की तलाश करने लगे और भारत में इसकी बढ़ती हुई मांग के कारण इसके निर्यात की उन्हें बेहतर संभावना प्रतीत हुई जिससे इन देशों से आयात में वृद्धि हुई तथा आयात में और अधिक बढ़ोत्तरी की चुनौती भी उत्पन्न हो गई।

भ. पीएएन की कीमत वही बनी रही अथवा कच्चे माल की लागत में बढ़ोत्तरी के बावजूद कभी-कभर तो गिरावट भी आई जिससे संकेत मिलता है कि पीएएन की आपूर्ति उपभोक्ता को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर की गई। इससे पहले भी घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय शुल्क लगाने के पश्चात कच्चे माल की कीमत में परिवर्तन होने पर कीमतें समान बनाए रखीं।

म. रक्षोपाय शुल्क क्षति तथ्य को निष्क्रिय करने की सीमा तक ही होगा।

य. यह कहा जाता है कि महत्वपूर्ण अन्तिम उत्पाद पर नगण्य प्रभाव है और यह विचार करते हुए कि घरेलू उद्योग का बचाव करना आवश्यक है, इसलिए रक्षोपाय लगाना जनहित में होगा।

र. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि कई रक्षोपाय जॉच में शुल्क की संस्तुति बिना व्यापक समायोजन योजना के कर दी गई।

4 निर्यातक राष्ट्रों के विचार

कोरिया गणराज्य

क. इस मामले में एक साथ दो-दो जॉच की गई अर्थात् पाटनरोधी एवं रक्षोपाय जॉच। अतिव्याप्ति अवधि से समान आर्थिक तथ्यों से अतिव्याप्ति उपचार होंगे, परिणामस्वरूप अधिक संरक्षण मिलेगा।

ख. याचिका में दो महीनों (अप्रैल से मई, 2011) की अवधि को सम्पूर्ण वर्ष 2011 का वार्षिकीकरण कर दिया जिससे आयात मात्रा की प्रवृत्ति अतिशयोक्तिपूर्ण हो गई। दो माह की अवधि, पूरे वर्ष की प्रवृत्ति दर्शाने के लिए बहुत कम है। भारत सरकार को जून से अगस्त, 2011 तक के आंकड़ों को शामिल करके अपने आयात आंकड़ों को अद्यतन कर लेना चाहिए।

ग. इस मामले में अप्रत्याशित विकास नहीं हुआ। इस मामले में क्षति का आभास पहले से ही था और इसकी भविष्यवाणी तब ही कर दी गई थी जब विगत रक्षोपाय अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने घरेलू मांग की तुलना में अपना क्षमता विस्तार बढ़ा लिया था। याचिकाकर्ता को रक्षोपाय उपायों की सहायता से घरेलू बाजार पर केन्द्रित होने के बजाय वर्ष 2009 के दौरान हुए निर्यात निष्पादन पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

घ. सापेक्षतः स्थिर क्षमता उपयोग होता है। याचिकाकर्ताओं ने क्षमता विस्तार के बावजूद न केवल उपयोगिता स्तर बनाए रखा बल्कि उच्चतर उपयोगिता स्तर पर पहुँचने में सफलता भी हासिल की।

ड. क्षति विवरण के अनुसार याचिकाकर्ताओं का निर्यात वाल्युम जो 2007-08 में 75382 मी.टन था, वर्ष 2010 में तेजी से कम होकर 15757 मी.टन रह गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान कराई गई सांख्यिकी दर्शाती है कि उत्पादन एवं क्षमता उपयोग में कमी पर आधारित क्षति का उत्तरदायित्व अन्य तथ्यों जैसे अल्प निर्यात निष्पादन को दिया जा सकता है, नकि पीएन के आयात को।

च. क्षमता विस्तार क्षति का मुख्य कारण है। मैसूर पैट्रो द्वारा अपने संयंत्र को बंद कर दिए जाने के बावजूद, आईजी पैट्रोफैमिकल्स की लगभग 160000 एम.टी. की क्षमता और अन्य याचिकाकर्ताओं की कुल क्षमता विना किसी निर्यात के समस्त घरेलू बाजार की मांग को पूरी तरह से सन्तुष्ट करने में सक्षम है। इससे यह संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ताओं के बीच में क्षति का मामला पहले से ही मौजूद है, जो पहले से ही उपरिक्षमता से लैस हैं और जिन्होंने स्वयं को डीटीए में परिवर्तित करके निर्यात करने की अपनी क्षमता को सीमित कर लिया है।

छ. प्रारम्भिक जाँच के पृष्ठ 16 पर बले ग्राफ में प्राथिकारी आर्थिकसीलीन की लागत में और थैलिक एनहाइड्राइड की कीमत में अभी हाल ही में हुए बदलाव को स्पष्ट करना चाहा है तथापि ग्राफ की वही कवज़ इस बात का साक्ष्य प्रदान करती है कि जून, 2011 से पहले लाभप्रद रूप से अनुकूल स्थिति बनी हुई थी। स्पष्टतः ग्राफ दर्शाता है कि उस अवधि में हानि की तुलना में लाभ अधिक हुआ।

ज. प्रारंभिक निष्कर्ष यह स्पष्ट करने में असफल रहे कि क्षति बढ़े हुए आयातों के कारण हुई, न कि अन्य तथ्यों के प्रभाव के कारण।

इजरायल सरकार

क. प्रारम्भिक निष्कर्ष के आंकड़े न तो आयातों में अत्यधिक वृद्धि प्रदर्शित करते हैं और न ही घरेलू उत्पादन में नाटकीय गिरावट दर्शाते हैं। वर्ष 2011 की प्रथम तिमाही में बिक्री में गिरावट अवश्य आई परन्तु यह गिरावट आयातों की वजह से नहीं हुई बल्कि उत्पाद की खपत में सामान्य गिरावट के कारण हुई।

ख. प्रारम्भिक निष्कर्षों में घरेलू उत्पादकों को कारित “गंभीर क्षति” के संबंध में उल्लिखित तथ्य रक्षोपायों पर डब्ल्यूटीओ करार की अपेक्षाओं के आलोक में नगण्य प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदन में किसी समायोजन योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

ग. प्रारम्भिक निष्कर्षों में आवश्यक जाँच अवधि निर्धारित नहीं कर पाते हैं और रक्षोपाय उपायों को न्यायोचित नहीं ठहरा पाते हैं।

घ. रक्षोपाय शुल्क लगाने से वर्ष 2009 में और उस तारीख के उपरान्त के तात्कालिक समय में बाजार व्यवहार प्रभावित हुआ अतः रक्षोपाय उपायों को पुनः लागू करने के लिए यह आधार नहीं बन सकता।

ड. जाँच आरम्भ किए जाने के नोटिस में इजरायल को भारत को किए जाने वाले पीएएन आयातों का मुख्य स्रोत बताया गया है। तथापि, आयात आंकड़ों को अच्छी तरह से देखने से यह स्पष्ट होता है कि इजरायल से कुल आयात भारत में कुल खपत का केवल 1.5% ही बनता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में,

जहाँ कुल बाजार हिस्से का 80% हिस्सा भारत के स्थानीय उत्पादकों का हो, यह दावा करना मुश्किल है कि क्षति आयात की वजह से हुई।

च. हमें यह नोट करना चाहिए कि पिछले वर्षों के दौरान इजरायल से आयातों में लगातार कमी हुई है।

छ. पीएएन के भारतीय उत्पादकों के समक्ष उपस्थित दिक्कतों का एक मुख्य कारण वैश्विक मंदी और मांग में गिरावट रहा है, न कि प्रतिस्पर्धी आयात। ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग संरक्षात्मक उपाय लगाकर विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा पर विजय हासिल करने के लिए सम्भव व्यापार उपाय की मांग कर रहा है।

ज. अभी हाल ही में भारतीय पीएएन उद्योग ने पाटनरोधी उपाय लगाने का अनुरोध किया है और 29 अप्रैल, 2011 को एक जाँच शुरू की गई थी। एक 'क्षति' के लिए दोहरा उपचार नहीं किया जा सकता है।

झ. आरोपित पाटन से हुई क्षति को आयातों में वृद्धि से हुई, तथाकथित क्षति को अलग नहीं किया जा सकता है। महानिदेशक, रक्षोपाय ने समानान्तर पाटनरोधी जाँच में तथाकथित पाटित आयातों के प्रभावों पर विचार नहीं किया।

अ. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7.5 के अनुसार 31 दिसम्बर, 2009 (विगत रक्षोपाय शुल्क के समापन की तारीख) से दो वर्षों की अवधि के लिए पीएएन के आयात पर अस्थायी तथा अन्तिम रक्षोपाय शुल्क, दोनों एक साथ नहीं लगाए जा सकते हैं।

ट. उपर्युक्त परिस्थितियों के आलोक में हमें विश्वास है कि यह जाँच तुरन्त समाप्त कर दी जाए और कोई भी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

5. नियातकों के विचार

गाडिव पैट्रोकैमिकल्स

- इस मामले में एक ही देश के संबंध में समान उत्पाद पर पाटनरोधी और रक्षोपाय जाँच दोनों एक साथ नहीं की जा सकती हैं।
- यह कि रक्षोपाय आवेदन में आवेदकों ने, एक अतिरिक्त कम्पनी के साथ, एक पाटनरोधी आवेदन, थैलिक एनहाइड्राइड पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग करते हुए, दायर किया है।
- आवेदक द्वारा की गई इस स्वीकृति के मद्देनजर कि "पाटन एवं अल्प कीमत पर किए गए आयात" क्षति कारित कर रहे हैं, माननीय डीजीएस

के मौजूदा जाँच तब तक स्थगित रखनी चाहिए जब तक पाटनरोधी जाँच की जा रही है।

iv. इसके अतिरिक्त, कथित पाटन द्वारा कारित क्षति को बढ़े हुए आयातों द्वारा कारित कथित क्षति से पृथक एवं एकल नहीं किया जा सकता है।

v. घरेलू उद्योग ने पीएएन के आयात पर लगाया गया रक्षोपाय 4 वर्षों के लिए वैध बनाए जाने की घोषणा करने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की है। तथापि माननीय उच्च न्यायालय ने अन्तरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

vi. यह आवेदन दायर करने के तत्काल पश्चात घरेलू उद्योग ने ऊपर वर्णित रिट याचिका वापस ले ली। समान राहत के लिए उच्च न्यायालय जाने के पश्चात उन्हें उसी तरह की राहत पाने के लिए नया आवेदन दायर नहीं करना चाहिए क्योंकि यह न्यायोचित नहीं है।

vii. 31 दिसम्बर, 2009 को रक्षोपाय शुल्क समाप्त होने के पश्चात आयातों में वृद्धि यह सिद्ध करती है कि घरेलू उद्योग स्वयं की एओएस की धारा 2, अनुच्छेद 7 द्वारा यथापेक्षित आयात में समायोजित नहीं करती है।

viii. डीजीएस ने, पिछले रक्षोपाय उपाय लगाने से पहले की अवधि को अनदेखा करते हुए, भूलवश जाँच की अवधि को 2008-09 की चौथी तिमाही से निर्धारित कर लिया, जो वर्ष 2009 के दौरान आरोपित रक्षोपाय शुल्क के प्रभाव के कारण हुई किसी कृत्रिम वृद्धि को निष्क्रिय करने के लिए अधिदेशित थी।

ix. अभी हाल ही की अवधि (2010 और 2010-2011 की चौथी तिमाही) के दौरान आयात का बाजार हिस्सा (16-18%) रक्षोपाय उपाय करने से पहले वर्ष 2008-2009 के दौरान बाजार हिस्से से अत्यधिक कम है जिसके कारण रक्षोपाय उपाय करने पड़े।

x. अर्जन्टीना फुटवियर मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल 'वांछित' परिणाम पाने के लिए जाँच की अवधि में हेरफेर करने से सतर्क करता है।

xi. इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय उपाय समाप्त होने के पश्चात इस वृद्धि को जीएटीटी अनुच्छेद 19 द्वारा यथापेक्षित "अप्रत्याशित विकास" का परिणाम नहीं माना जा सकता है।

xii. आवेदक का कार्य स्पष्ट दर्शाता है कि उन्हें इस तथ्य का पता था कि निशुल्क की समाप्ति के उपरान्त पीएएन के आयात में वृद्धि होने की

संभावना है और इसलिए आयातों में इस कथित वृद्धि को 'अचानक' एवं 'अप्रत्याशित' नहीं कहा जा सकता है।

xiii. इस मामले में आयात वाल्युम स्पष्ट उपरिगामी रुझान नहीं दर्शाता है। जबकि आयात में गिरावट के कई हस्तक्षेपी प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं।

xiv. डीजीएस ने अपने निष्कर्षों का आधार भूलवश, अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू खपत के बजाय घरेलू उत्पादन के संबंध में आयात प्रवृत्तियों को बना लिया। निर्यात में गिरावट से उत्पादन के संबंध में आयात के प्रतिशत को बढ़ा दिया।

xv. प्रारम्भिक निष्कर्ष कथित रूप से यह दर्शाते हैं कि वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक कोरिया और ताइवान से आयात में बढ़ोत्तरी हुई है परन्तु इसजाँच में शामिल किए गए तृतीय देश अर्थात् इजरायल से संबंधित आंकड़े नदारद हैं। वास्तव में तो जाँच अवधि के दौरान निर्यात की मात्रा में कमी आई है।

xvi. यह तथ्य कि उत्पादक, ईओयू से डीटीए में शिफ्ट होने और घरेलू बाजार में अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम था, आयात से हुई किसी गम्भीर क्षति के किसी निष्कर्ष के विपरीत है।

xvii. डीजीएस ने जाँच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में वर्ष 2009-10 और 2010-11 की अवधि के दौरान 11% की महत्वपूर्ण वृद्धि की अनदेखी कर दी। वर्ष 2011-12 की प्रथम तिमाही की घरेलू बिक्री (38,149 मी.टन) वर्ष 2009-2010 की समसामयिक तिमाही के दौरान हुई घरेलू बिक्री (35,530 मी.टन) से 7% अधिक है।

xviii. आवेदक द्वारा दर्शाया गया घरेलू उत्पादन एवं क्षमता उपयोग में बदलाव घरेलू उद्योग के निर्यात में चल रही गिरावट से, न कि आयात से, संबंधित होना चाहिए।

xix. इस मामले के निष्कर्ष, जो बिक्री में वृद्धि, बिक्री कीमत में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि और भारतीय पीएएन उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि निश्चिततः निष्कर्ष के "घरेलू उद्योग की स्थिति में महत्वपूर्ण समग्र हास" से मेल नहीं खाता है।

xx. डीजीएस ने इस तथ्य को नकार दिया कि आवेदक की बिक्री कीमत में पिछले दो वर्षों और खासकर अभी हाल ही के समय (2010-2011 की चौथी तिमाही और 2011-2012 की पहली तिमाही) में वृद्धि हुई।

xxi. डीजीएस ने इस तथ्य को नकार दिया कि गाडिव की भारतीय बाजार में निर्यात कीमत एवं पीएन का भारत को समग्र निर्यात की औसत कीमत घरेलू कीमतों से दक्षिण पूर्व एशिया (भारत सहित) में काफी अधिक थीं और इस कारण आयात कीमतों से घरेलू उद्योग की कीमतें कम नहीं हुईं।

xxii. डीजीएस ने आवेदन के साथ संलग्न आवेदक के वित्तीय विवरण कि अभी हाल की अवधि में उनकीवित्तीय स्थिति अच्छी है और उन्हें आयातों में कथित वृद्धि से कोई क्षति नहीं हुई को, पूरी तरह से नकार दिया।

xxiii. आवेदकों की उत्पादन लागत (आर्थोजाइलीन की लागत में वृद्धि) में वृद्धि और इसका आवेदकों की लाभदायकता पर प्रभाव को आयात से नहीं जोड़ा जा सकता है।

xxiv. मई-जुलाई, 2011 के दौरान आंकड़ों में कमी, एक अस्थायी घटना है और यह आर्थोलाइजीन की कीमतों में बढ़ोत्तरी और अप्रैल-मई, 2011 के दौरान घरेलू खपत में गिरावट के कारण पीएन की घरेलू कीमतों में गिरावट से जोड़ा जाना चाहिए।

xxv. आयात, घरेलू उत्पादकों को अपनी कीमत बढ़ाने से मना नहीं करता है।

xxvi. डीजीएस का यह आकलन कि यदि रक्षोपाय शुल्क आरोपित नहीं किया गया तो घरेलू उद्योग बंद हो जाएगा, पूर्णतया निराधार है क्योंकि आवेदकों का घरेलू बाजार में 75%-80% हिस्सा है और उन्हें उच्च लाभ होता है।

xxvii. ऐसा प्रतीत होता है कि डीजीएस ने यह पूर्व कल्पना कर ली कि विगत रक्षोपाय उपाय 180 दिनों या उससे कम की अवधि के लिए किए गए थे और इसलिए दो वर्षों की अवधि के समयान्तराल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। डीजीएस ने उल्लेख किया कि निर्णायक रक्षोपाय शुल्क 29.01.09 से 31.12.09 तक की एक वर्ष की अवधि के लिए लगाया गया जो 180 दिनों से अधिक है। इसलिए भारत इस उत्पाद पर 31.12.2011 से पहले कोई अन्य रक्षोपाय साधन नहीं लगा सकता है।

xxviii. रक्षोपाय साधन एक आपातकालीन उपाय है जिसका प्रयोग आपातकाल की असाधारण परिस्थितियों में किया जा सकता है न कि भारत के किसी व्यापार भागीदार द्वारा “अनैतिक व्यापार” की प्रतिक्रिया के रूप में। यहाँ इस आपातकालीन उपाय का प्रयोग वर्ष 2009 में पहले ही किया जा चुका है और भारतीय पीएन उद्योग द्वारा इसे मौजूदा हालात में फिर अपनाना न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

6. आयातक/उपयोक्ता उद्योग के विचार

भारतीय पेण्ट्स एसोसिएशन

- i. प्रारम्भिक निष्कर्ष प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत हैं। प्रारम्भिक निष्कर्षों को केवल तीन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतीकरण के आधार पर ले लिए गए और हमको मिलकार पाँच हितबद्ध पक्षकारों की अनदेखी कर दी गई। किसी अर्ध न्यायिक निकाय जिसमें डीजी रक्षोपाय भी शामिल हैं, द्वारा इन अधिकारों का प्रयोग प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप रहा है।
- ii. डीजी रक्षोपाय द्वारा प्रारंभिक निष्कर्ष में उपलब्ध कराए गए आयात आंकड़े से भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों/प्रतिवादियों को याचिका के अनुबंध 2 में दिए गए अप्रैल-जून, 2011 के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए ह। इसके अतिरिक्त, अग्रिम लाइसेस स्कीम के अन्तर्गत किए गए आयातों को समग्र आयातों से अलग रखना चाहिए।
- iii. पीएएन के आयात के विरुद्ध पाटनरोधी जॉच में डीजीएडी द्वारा जारी जॉच शुरुआत अधिसूचना के अनुसार तीन याचिकाकर्ताओं में से दो ने जनवरी-दिसम्बर, 2010 के दौरान कोरिया गणराज्य से पीएएन का आयात किया था। अतः मै0 आईजी पैट्रोकैमिकल्स और मै0 थिरुमलाई पैट्रोकैमिकल्स नामक दो कम्पनियाँ पीएएन का आयातक होने के कारण घरेलू उद्योग का भाग नहीं बन सकती। इसके अतिरिक्त, जब जॉच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग स्वयं घरेलू बाजार में खपत के लिए इन वस्तुओं का आयात कर रहा है तो घरेलू उद्योग को क्षति का कोई दावा नहीं बनता है क्योंकि घरेलू उद्योग को क्षति थोपी हुई लगती है, क्योंकि उनका आयातों में योगदान है।
- iv. डीजी रक्षोपाय ने प्रारम्भिक निष्कर्षों में यह परिणाम निकाला कि उत्पादन में गिरावट आई है। तथापि, वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 2010-11 में उत्पादन में घृद्धि हुई है।
- v. डीजी, रक्षोपाय ने प्रारम्भिक निष्कर्षों के पृष्ठ 13 के तहत यह निष्कर्ष निकाला कि क्षमता उपयोग में अत्यधिक कमी आई है क्योंकि आवेदकों का औसत बाजार हिस्सा जो वर्ष 2009-10 में 85% था वर्ष 2010-11 के दौरान घटकर 74% रह गया। यह निष्कर्ष उनके प्रारम्भिक निष्कर्षों के पृष्ठ 5 पर उल्लिखित बाजार हिस्से के आंकड़ों से मेल नहीं खाता है।

- vi. यूएसए एवं चीन के बाजारों में विकास पूर्वापेक्षित था। डीजी रक्षोपाय ने पीएएन पर विगत रक्षोपाय जॉच में यथात्त्वाशित अप्रत्याशित विकास का ही उल्लेख किया है। इसलिए इस जॉच के संबंध में ये विकास अप्रत्याशित नहीं थे क्योंकि ये तीन साल पहले घटि हो चुके थे।
- vii. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई क्योंकि सभी प्रमुख आर्थिक पैरामीटरों अर्थात् उत्पादन, प्रतिष्ठापित क्षमता, घरेलू बिक्री, लाभदायकता, बाजार विस्तार आदि में सकारात्मक रुख है।
- viii. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा बढ़ा जबकि आयातों का बाजार हिस्सा उसी स्तर पर बना रहा जिस स्तर पर यह 2007-08 में था।
- ix. घरेलू उद्योग पाटनरोधी और रक्षोपाय जॉच के रूप में दोहरे संरक्षण की मांग कर रहा है। पाटनरोधी जॉच के दौरान इन देशों से आयात का वाल्युम वही रहा जो रक्षोपाय जॉच के दौरान आयात वाल्युम था जिससे यह अभिप्रेत होता है कि समान घरेलू उद्योग को एक ही समय में दो अलग-अलग तरह की क्षति कारित करने के लिए एक ही आयात वाल्युम की दो बार जॉच की जा रही है।
- x. इस मामले में कोई आकस्मिक लिंक नहीं है।

इण्डियन प्लास्टीसाइजर्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईपीएमए) और पालिएस्टर रेजिन मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (पीआरएमए)

- i. डीजी रक्षोपाय ने हितबद्ध पक्षकारों को टिप्पणी करने का मौका न देकर गलती की है और तद्वारा न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों और जॉच को शासित करने वाले सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है। हमने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2011 के पत्र के तहत हमें एक हितबद्ध माने जाने का अनुरोध किया है और उत्तर प्रस्तुत करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांग जो दे दिया गया। तथापि, इसके बावजूद 23 सितम्बर, 2011 को प्रारम्भिक निष्कर्ष जारी कर दिए गए।
- ii. इस मामले में पीओआई आउटडेट है न कि अर्वाचीन। इस मामले में पीओआई जनवरी, 2009 से शुरू होती है और मई, 2011 में समाप्त होती है। अतः पीओआई में उन अंकड़ों को शामिल किया गया है जो 28 महीने पुराने हैं और उन्हें अर्वाचीन नहीं माना जा सकता है। दो वर्षों से

अधिक का समय आयातों में अचानक, तीव्र एवं अत्यधिक बढ़ोत्तरी का कारण नहीं हो सकता।

iii. याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गएआंकड़े आयातों में वृद्धि के कारण हुई क्षति का यथार्थ आकलन प्रदान नहीं करते हैं। क्षति का एवं क्षति की चुनौती का आकलन करने के लिए किसी विशिष्ट तिमाही में किए गए आयातों का वार्षिक रूप में विश्लेषण करना अनुचित है और केवल 2 महीनों के आयातों का वार्षिकीकरण करना मात्र प्रकल्पना प्रतीत होता है और यह मामला शुरू करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।

iv. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आयात एवं उत्पादन जैसे अन्य आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और वे समानान्तर पाठनरोधी याचिका में दायर याचिका में प्रदत्तआंकड़ों से असंगत हैं। उपयुक्त एवं न्यायोचित स्पष्टीकरण के अभाव में डाटा को अविश्वसनीय बताकर डिसमिस किया जा सकता है।

v. याचिकाकर्ताओं की घरेलू बिक्री सतत रूप से बढ़ी है जबकि आयातों का बाजार हिस्सा वर्ष 2010-11 की पहली तिमाही में 37% की तुलना में अप्रैल-मई, 2011 में घटकर 26% रह गया।

vi. क्षमता उपयोग अधिक कमी नहीं दर्शाता है और औसत क्षमता उपयोग 77% रहा जबकि अन्य तथ्यों द्वे याचिकाकर्ताओं के उत्पादन और क्षमता उपयोग को प्रभावित किया है।

vii. याचिकाकर्ताओं का उत्पादन वर्ष 08-09 की चौथी तिमाही की तुलना में वर्ष 11-12 की चौथी तिमाही में 8% बढ़ा जबकि उसी अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं की बिक्री में 23% की बढ़ोत्तरी हुई।

viii. मै0 आईजी पैट्रोकैमिकल्स और मैसर्स थिरुमलाई पैट्रोकैमिकल्स के तुलन-पत्रों का अध्ययन वित्त वर्ष 2009-10 और 2010-11 में अत्यधिक लाभ दर्शाता है। वास्तव में वित्त वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही में आईजी पैट्रो का प्रचालनात्मक फायदा 9.30 करोड़ रुपये और थिरुमलाई का 9.76 करोड़ रुपये था। मै0 थिरुमलाई को पिछले 10 वर्षों में वर्ष 2008-09 के दौरान विश्व आर्थिक मन्दी के कारण घाटा हुआ।

ix. उपयोक्ता उद्योग द्वारा बहुत सारे आयात अपनी निर्यात वचनबद्धताओं को पूरा करने के उद्देश्य से अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अन्तर्गत शुल्क मुक्त ढंग से किए जाते हैं। इन आयातों को रक्षोपाय उद्देश्यों के लिए नहीं गिना जाता है।

- x. घरेलू उद्योग को पहले ही काफ़ि उच्चतर स्तर का संरक्षण मिला है, सीमा शुल्क 30% की दर से पहले ही काफ़ि अधिक है जिसे अभी ज्ञाल ही में 7.5% कम किया गया है। अतः घरेलू उद्योग ने अनुचित व्यापार उपचारी संरक्षण की मांग की है।
- xi. याचिकाकर्ता ने इस सबध में कोई जानकारी नहीं दी है कि क्षा इस उत्पद की पहली याचिका के साथ प्रस्तुत समायोजन योजना के रूप में उनके द्वारा की गई वचनबद्धता का पालन किया गया। अंगीकार किया गया या याचिकाकर्ता को वही सथ्य अभी भी क्षति पहुँचा रहे हैं।
- xii. नामित प्राधिकारी से यह अपेक्षा ती जाती है कि वह याचिकाकर्ताओं को अधिदेश दे कि वे रक्षोपाय शुल्क लगाने के उद्देश्य से विस्तृत समायोजन प्लान प्रस्तुत करें ऐसा न करना रक्षोपाय संबन्धी डब्ल्यूटीओ करार का उल्लंघन है।
- xiii. इस मामले में संवेदनशील परिस्थितियों का अभाव है। संबंधित वस्तु की आयात कीमतों में वृद्धि घरेलू कीमतों में वृद्धि की तुलना में अधिक है। स्पष्टतः, याचिकाकर्ता को हुई क्षति आत्मकृत है और याचिकाकर्ता द्वारा दावाकृत गम्भीर क्षति के लिए आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- xiv. समानान्तर पाटनरोधी जांच के लिए पीओआई जनवरी, 2010 से दिसम्बर, 2010 है जबकि वर्तमान रक्षोपाय जांच के लिए पीओआई 2008-09 की चौथी तिमाही से मई, 2011 तक है। अतः समानान्तर पाटनरोधी जांच के अन्तर्गत पीओआई रक्षोपाय जांच के लिए पीओआई के अन्तर्गत शामिल हैं जोकि अनुचित है।
- xv. इस मामले में याचिकाकर्ता को हुई क्षति के लिए स्पष्टतया अन्य तथ्यों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, न कि आयातों में वृद्धि को। अतः बढ़े हुए आयातों और गम्भीरक्षति के बीच कोई आकस्मिक संबंध स्थज्ञापित नहीं होता है।
- xvi. इस मामले में रक्षोपाय शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध होगा। रक्षोपाय शुल्क लगाने से संबंधित वस्तु की कीमतों में घट-बढ़ होगी और इसका प्लास्टीसाइजर्स विनिर्माताओं तथा उन पर निर्भर अन्य उद्योगों की लागत पर प्रत्यक्ष विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यह अन्तिम प्रयोगकर्ता उद्योग को

पूर्णतया अन-अर्थक्षम बना देगी और इससे उनको बहुत अधिक क्षति होगी जिससे वे बन्द भी हो सकती हैं।

केजेएल प्लास्टीसाइजर्स लिमिटेड

- i. याचिकाकर्ताओं अर्थात् मै0 आईजी पैट्रोकैमिकल्स एवं मैसर्स थिरुमलाई पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड के अत्याधुनिक संयंत्र हैं और पूरे विश्व में कहीं भी इससे अधिक तकनीकी विकास नहीं हुआ है जिसके लिए घरेलू उद्योग क्षति का दावा कर रहे हैं।
- ii. देश में कच्चा माल बहुतायत में उपलब्ध है और प्लांट को चलाने के लिए किसी तरह की ऊर्जा की जरूरत नहीं है क्योंकि यह उष्माउन्योचक उद्योग है। इसके अतिरिक्त डीआई अतिरिक्त माप का सृजन करते हैं जिससे वे न केवल अपने प्लांट के लिए ऊर्जा बनाते हैं बल्कि वे इसकी बिक्री भी करते हैं। यह उनके लिए लाभदायक है।
- iii. घरेलू उद्योग का पर्याप्त निर्यात है और यह दर्शाता है कि वे विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा के लिए योग्य हैं।
- iv. घरेलू उद्योग को उनके तुलनपत्र के अनुसार विगत दस वर्षों में, केवल 2008-09 को छोड़कर जब विश्व्यापी मन्दी आई थी, हमेशा ही मुनाफा हुआ है।
- v. घरेलू उद्योग द्वारा उच्चतर आयात किए जाते हैं। वे अवास्तविक कीमतें दे रहे हैं जो प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से उच्चतर हैं इस प्रकार वे स्थानीय उपभोक्ता को सामग्री आयात करने के लिए दबाव दे रहे हैं ताकि वे यह दिखा सकें कि आयात में वृद्धि हो रही है।
- vi. इस अवधि के दौरान अधिकांश आयात शुल्क मुक्त लाइसेंस धारकों द्वारा किए गए जिसे उनके आयात आंकड़ों से अलग कर दिया जाना चाहिए।
- vii. आईजी पैट्रोकैमिकल्स अपना विस्तार कर रहा है, जिसके बाद उनका विश्व का सबसे बड़ा प्लांट हो जाएगा औंश थिरुमलाई पैट्रोकैमिकल्स गुजरात में एक अन्य प्लांट लगा रहा है। यदि उन्हें क्षति हो रही हैं तो इस विस्तार की क्या जरूरत है।
- viii. प्लास्टीसाइजर्स उद्योग, जो पीएन का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, को अगर पीएन पर रक्षोपाय शुल्क लगाया गया तो, नुकसान होने की संभावना है क्योंकि इस उद्योग में अच्छे समय में भी ज्यादा मार्जिन नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त, प्लास्टीसाइजर्स को विश्व स्तरीय एकीकृत संयंत्रों से प्रतिस्पर्धा करनी होती है जिसमें उनके अपने खुद के आक्सो-अल्कोहल या थैलिक एनहाइड्राइड या दोनों ही होते हैं। यदि पीएएन पर कोई भी रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है तो यह विदेशी उत्पादकों के लिए वरदान साबित होगा क्योंकि उनको पीएएन के बजाय प्लास्टीसाइजर्स के लिए बाजार उपलब्ध हो जाएगा। इससे प्लास्टीसाइजर्स का भारी मात्रा में आयात होने लगेगा और यह प्लास्टीसाइजर्स के घरेलू विनिर्माताओं के हित में नहीं होगा।

ix. थैलिक प्लास्टीसाइजर्स उद्योग कई एफटीए के अध्यधीन है जिनसे मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैण्ड से शुल्क के रियायती दरों पर डीओपी के आयात की अनुमति है।

7 घरेलू उद्योग द्वारा प्रत्युत्तर

I. ताइवान सरकार

- लगाए गए रक्षोपाय शुल्क की अवधि समाप्त होते ही आयात बढ़ गए जिससे घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा बढ़ने लगा।
- भारत में घरेलू उद्योग की, भारत में संपूर्ण घरेलू मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।

II. कोरिया सरकार

- डीजीसीआईएस आंकड़े, चीन और पाकिस्तान में मांग कम होने, जो एक अप्रत्याशित घटना थी, भारत को कोरिया और ताइवान से पीएएन के निर्यातों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाते हैं, जिससे आयातों में वृद्धि होने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति या गम्भीर क्षति का खतरा उत्पन्न हो गया।
- घरेलू उत्पादकों की परस्पर प्रतिस्पर्धा क्षति का कारण नहीं है क्योंकि घरेलू उत्पादक सम्पूर्ण अवधि में प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं और मौजूदा अवधि में गिरावट आन्तरिक प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं हो सकती है।
- घरेलू उद्योग की क्षमता जन-दिस. 2010 के दौरान स्थिर बनीरही जबकि घरेलू उद्योग के उत्पादन में जन., 11 से मार्च, 2011 और तत्पश्चात् वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही में कमी आई।
- आयातों की पत्तन पर उत्तराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम रही। आयातों की वजह से घरेलू उद्योग को अलाभकर कीमतें निर्धारित करनी पड़ी।

III. इंजिरायल की सरकार

- i. रक्षोपाय मामले में अलग-अलग देशों से आयात की पद्धति का कोई लेना-देना नहीं है।
- ii. घरेलू उद्योग लम्बे समय तक इन्वेन्ट्रीज को न तो रोक सकता है और न ही उत्पादन को कभी-कभार कम कर सकता है। इसे कीमत घटाकर न्यूनतम कीमत वाले आयातों का सामना करना पड़ा जिससे इसे अत्यधिक क्षति हुई।
- iii. हालांकि आयात बढ़ने का एक कारण वैशिक मन्दी भी है परन्तु भारतीय बाजार मंदी से पीड़ित नहीं है। अतः भारतीय उत्पादकों पर वैशिक मंदी का कोई असर नहीं होना चाहिये।
- iv. आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि न केवल घर्ष 2010 में हुई बल्कि यह अगले 6 माह तक बढ़ते रहे। समापन का प्रभाव इतने लम्बे समय तक नहीं हो सकता है।
- v. समायोजन प्लान का अधिदेश न तो डब्ल्यूटीओ करार में है और न ही भारतीय विधि में। याचिकाकर्ताओं ने कोरिया-डेयरी मामले का उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया जिसमें पैनल ने इस तरफ को नामंजूर कर दिया कि अनुच्छेद 5.1 समायोजन योजनाओं पर धिचार करने का कोई दायित्व आरोपित करता है।
- vi. घरेलू उद्योग एक समाये जन योजना पर काम कर रहा है और वह उचित समय पर उपलब्ध कराया जाएगा।

IV. गाडिव पैट्रोकैमिकल्स इण्डस्ट्री लिमिटेड

- i. आवेदकों ने चुना कि उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिका को वापस ले लिया जाए और रक्षोपाय शुल्क बढ़ाने का अनुरोध करने से बचा जाए। इसके बताय, पाटनरोधी याचिका लम्बित होते हुए रक्षोपाय शुल्क के लिए नया आधेदन दे दिया।

- ii. आयातों का विश्लेषण करते समय डीजी को चाहिए थंजा कि वह यह मूल्यांकन करें कि आयातों में घटने की प्रवृत्ति अस्थायी है या यह दीर्घावधि की प्रवृत्ति दर्शाता है जैसाकि अजेन्टीना-फुटवियर (ईसी) मामले में किया गया।
- iii. ईओयू की डीटीओ में शिफिटिंग की इस जाँच से कोई संगतता नहीं है। यह शिफिटिंग एक दीर्घावधि प्रक्रिया है और इसने घरेलू उद्योग को कोई क्षति कारित नहीं की है।
- iv. याचिकाकार्ता आर्थोजाइलीन (कच्चा माल) की कीमतों में बढ़ोत्तरी से अपनी कीमतों की बढ़ोत्तरी करने से अक्षम रहे क्योंकि सस्ते आयात मौजूद थे।
- v. वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए वित्तीय आंकड़े मेवल थैलिक एनहाइड्राइड के आंकड़े न होकर अमुक याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित सम्पत्ति उत्पादों के समेकित आंकड़े हैं।
- vi. अभी हाल ही की अवधि में डीओपी में अधिक वृद्धि होने के कारण डीओपी सेगमेंट में पीएएन की मांग बढ़ी है।

V. भारतीय पेण्ट एसोसिएशन

- i. 29.03.1995 और 21.11.2008 की अवधि के दौरान डब्ल्यूटीओ को स्पोर्ट किए गए 168 रक्षोपाय जाँच शुरुआत में से केवल 15 मामलों में रक्षोपाय जाँच शुरु होने के 30 दिन के अन्दर अनन्तिम रक्षोपाय साधनों की संस्तुति की गई/आरोपित किए गए।
- ii. नाजुक हालात में अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क लगाने में जरा सी भी देरी अपूरणीय क्षति कारित कर सकता है। थैलिक एनहाइड्राइड, एल्यूमिनियम एफआरपी एवं फ्वायल डायमिथोएट टेक्निकल, सोडा ऐश के मामलों में प्रत्युत्तरों की प्राप्ति के बिना अन्तरिम रक्षोपाय शुल्क लागू कर दिया गया।
- iii. विगत में तृतीय देशों ने हितबद्ध पक्षकारों से जानकारी प्राप्त किए बिना रक्षोपाय शुल्क लगा दिया।
- iv. याचिका में घरेलू उद्योग ने आईबीआईएस से प्राप्त आंकड़ों पर विचार किया है जबकि महानिदेशक (रक्षोपाय) ने प्रारम्भिक निष्कर्षों में डीजीसीआईएण्डएस तथा मूल्यांकन निदेशालय से प्राप्त आंकड़ों पर विचार किया है और समस्त स्रोत बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाते हैं।

- v. याचिकाकर्ताओं द्वारा छोड़े गए आंकड़े केवल लिपिकीय त्रुटि है और इस उद्देश्य से कोई पूर्व अवधारणा नहीं बनाई गई।
- vi. पाटनरोधी विधि और रक्षोपाय विधि में 'घरेलू उद्योग' की परिभाषा अलिंग-अलग हैं। रक्षोपाय विधि में "घरेलू उद्योग" के लिए विशिष्ट परिभाषा का प्रावधान है इसलिए अन्य विधि से परिभाषा को ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है।
- vii. अग्रिम लाइसेंस से किए गए आयातों का घरेलू उद्योग पर प्रभाव पड़ रहा है और इसलिए उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है।
- viii. विषेशी पक्षकारों ने तुलना के लिए अवधि का अपनी जरूरत के अनुसार सुविधापूर्वक चयन किया है। वर्तमान जांच में जांच की अवधि मई, 2011 तक है और इसलिए हर प्रवृत्ति की जांच की अवधि की संभावित तक का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- ix. आवेदकों का वर्ष 2009-10 में औसत बाजार हिस्सा 85% था जो वर्ष 2010-11 के दौरान घटकर 74% रह गया अर्थात् इसमें 11% की गिरावट आई।
- x. चीन में उत्पादक थैलिक एनहाइड्रोइड का उत्पादन करने के लिए नए संयंत्र स्थापित कर रहे हैं जिससे चीन में उत्पाद की आपूर्ति बढ़ गई है और तदद्वारा लृततीय देशों के विदेशी उत्पादकों के चीन को निर्यात के बाजार अवसरों में कमी आई है।
- xi. पूर्व जांच के समय-समान तथ्य पर विचार करने का आशय यह नहीं है कि वह तथ्य अब नहीं रह सकता है या अब संगत नहीं हो सकता है और प्राधिकारियों को उन्हीं तथ्यों के आधार पर रक्षोपाय शुल्क लगाने से कोई नहीं रोकता है।
- xii. याचिकाकर्ताओं ने विगत वर्ष के आयातों और अन्य क्षति प्राचलों, जो वार्षिक आधार पर नहीं हैं, के साथजू तुलना करने के लिए तीन माह के आंकड़ों का वार्षिक आंकड़ों के रूप में दर्शा दिया।
- xiii. घरेलू उद्योग ने कभी भी 85% बाजार हिस्सा होने का दावा नहीं किया। भारतीय उत्पादकों का एमग्र रूप से बाजार हिस्सा 87% रहा जो अभी हाल की अवधि में कम होकर 77% रह गया।

xiv. दीर्घावधि के आंकड़ों का विश्लेषण करने का एकमात्र उद्देश्य है हस्तेक्षणकारी प्रवृत्तियों की जाच करना, न कि एण्ड टू एण्ड बिन्दु तुलना करना।

xv. विपक्षी पक्षकार ने अपनी प्रस्तुतियों के पृष्ठ 10 पर मैसूर प्लांट के बंद होने के कारणों का उल्लेख किया है जोकि वार्षिक रिपोर्ट से एक सारांश है।

xvi. कैटालिस्ट में किसी परिवर्तन से संयंत्र अनिश्चित कात की अवधि के लिए बद नहीं हो सकता है बल्कि ऐसा भण्डारों के एकत्रण के कारण हुआ।

xvii. विरोधी पक्षकार ने अपने तर्क को बल देने के लिए कोई बैक-अप जानकारीया आईबीआईएस आंकड़े प्रदान नहीं किए हैं। डीजी को दी गई जानकारी में केवल आयातों में वृद्धि दर्शायी गई है।

xviii. एसआई समूह, जिसे रक्षोपाय जांच में शामिल नहीं किया गया है, का सकल घरेलू उत्पादन में केवल 4% का हिस्सा है जिससे घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

xix. हालांकि डीजी द्वारा अत्यधिक हाल पर विचार किया जाना अपेक्षित होता है, स्पष्टतः डीजी को जांच के प्रारम्भ के पश्चात् के आंकड़ों को शामिल करना अपेक्षित नहीं होता है।

xx. जांच की अवधि और आवेदक समान नहीं हैं इसलिए दो जांचों में उपलब्ध कराए गए आंकड़े अलग-अलग होने चाहिए। तथापि अलग-अलग कम्पनियों के सबध में आंकड़ों में अन्तर नहीं होता है।

xxi. वार्षिक प्रतिवेदनों में दर्शाए गए आंकड़े पूर्णतया असंगत हैं। केवल सम्बिधित उत्पाद से हुआ फायदा ही संगत है।

xxii. समस्त मौजूदा अवधि में सीमा शुल्क 7.5% रहा। अतः यह कहना असंगत एवं आधारहीन है कि सीमाशुल्क में कमी करने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई।

VI मैओ केएलजे प्लास्टीसाइजर्स

i. विश्वस्तरीय संयंत्र होने, कच्चे माल की उपलब्धता तक आसान पहुँच और ऊर्जा लागत, परिवर्तन लागत अत्यधिक अनुकूलतम होने के बावजूद घरेलू उद्योग अपनी लागत वसूल करने में अक्षम है।

- ii. यह स्थापित नहीं किया गया है कि सभी आयात शुल्क मुक्त थे। यदि सारे आयात शुल्क मुक्त थे तो रक्षोपाय शुल्क लगाने के पश्चात इसके वाल्युम में गिरावट नहीं आनी चाहिए।
- iii. रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित न करने से विस्तार योजना जोखिम में पड़ जाएगी क्योंकि इससे आयात में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी।

8. निर्यातकों का उत्तर गाड़िय पैट्रोकैमिकल्स

- i. वर्तमान प्रस्तुति में आवेदक इस महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख करने में असफल रहा कि उन्होंने बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट्रायिका दायर की है।
- ii. याचिका पर आवेदक की चुप्पी और वर्तमान याचिका दायर करने के तुरन्त पश्चात् याचिका को वापस लेने से फोरम शॉपिंग बनता है और डीजीएसजी द्वारा इसे गम्भीरता से लेना चाहिए।
- iii. डीजीएसजी ने अपने निर्णय, उदाहरणार्थ कास्टिक सोडा में यह पाया कि पाटन शुल्क का अधिरोपण करने के पश्चात् अतिरिक्त रक्षोपाय शुल्क लगाने पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब आयात पर हुए पाटन शुल्क का प्रभाव घरेलू उद्योग पर स्पष्ट परीक्षण कर लिया गया हो।
- iv. रक्षोपाय शुल्क की अवधि पाटनरोधी जाँच को अतिव्याप्त कर रही है जो 2007-08, 2008-2009, 2009-2010, जनवरी-दिसम्बर, 2010 (क्षति के संबंध में) और जनवरी-दिसम्बर, 2010 (पाटन के संबंध में) है।
- iv. रक्षोपाय आवेदन और पाटन याचिका में बताई गई क्षति अभिन्न हैं अर्थात् कीमतों में गिरावट, लाभदायकता में कमी, बाजार हिस्से में गिरावट, क्षमता उपयोग में ह्रास।
- v. दोनों जाँचों विश्लेषित क्षति एवं अवधि समरूप हैं और इससे दोहरा शुल्क लगाने का चांस बन सकता है।
- vi. डब्ल्यूटीओ पैनल और अपीलीय निकाय ने परिरक्षित आंडुओ(पीच्स) के आयात पर अर्जन्टीना निर्णायक रक्षोपाय उपाय एवं यूनाइटेड स्टेट्स – कुछ इस्पात उत्पादों के आयातों पर निर्णायक रक्षोपाय शुल्क के

मामलों में यह पाया कि आयातों में दृष्टि सिद्ध करने के लिए कई वर्षों का व्यापक विश्लेषण किया जाना चाहिए और यह विश्लेषण हाल के विगत तक सीमित नहीं होना चाहिए।

- vii. यदि किसी विशिष्ट तिमाही (या माह) में आयात की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है तब भी यह नहीं कहा जा सकता है कि पूरे वर्ष भर आयात अनिवार्यतः उच्च ही बने रहेंगे।
- viii. आयात और खपत के संबंध में आयातों की वास्तविक वार्षिक मात्रा, घरेलू उत्पाद द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसरण में रक्षोपाय शुल्क लगाने से पहले के वर्षों की तुलना में आयातों में कमी प्रदर्शित हुई है।
- ix. समायोजन योजना की प्रस्तुति से बचने के लिए आवेदकों ने तर्क दिया कि उन्होंने केवल एक वर्ष के लिए रक्षोपाय शुल्क का अनुरोध किया था। तथापि उनकी लिखित आत्मनिवेदन के अनुसार वे 'यथासंभव दीर्घतम अवधि' के लिए रक्षोपाय शुल्क की मांग कर रहे हैं।
- x. रक्षोपाय शुल्क अवधि की स्थिति काल की परवाह किए बिना आवेदकों को कोरिया – कुछ निश्चित डेयरी उत्पादों के आयातों पर निर्णायक रक्षोपाय और चिली – प्राइस बैण्ड प्रणाली एवं कुछ कुछ कृषि उत्पादों के संबंध में रक्षोपाय के मामलों में दिए गए निर्णय के अनुसार समायोजन प्लान प्रस्तुत करना चाहिए था।
- xi. आवेदकों द्वारा अपने विगत रक्षोपाय आवेदन में प्रस्तुत समायोजन प्लान पूर्णतया काल्पनिक पाया गया। जब तक समायोजन प्लान प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब तक कोई अनन्तिम शुल्क नहीं लगाया जा सकता।
- xii. माननीय डीजीएस के निर्णयानुसार जाँच की अवधि वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही और उसके पश्चात है, न कि सितम्बर, 2009 तैसाकि आवेदकों ने अपने निवेदन की धारा 27 में तर्क दिया है।
- xiii. घरेलू बिक्रियों के संबंध में आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि प्रत्येक वर्ष की पहली तिमाही में बिक्री शेष तिमाहियों के दौरान हुई बिक्री से अपेक्षाकृत अधिक हैं और इससे घरेलू बिक्री में गिरावट आने के निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता है।
- xiv. आवेदकों ने स्वीकार किया कि वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही में पीएएन की घरेलू मांग में कमी इसके अनुप्रवाही उत्पाद आक्टायत

थैलेट के उत्पादन में भारत में कमी के कारण आई और घटती मांग से क्षति हुई।

xv. प्रारम्भिक निष्कर्षों में वर्ष 2010-2011 की पहली तिमाही में घरेलू मांग में कमी की प्रवृत्ति स्पष्ट है। वर्ष 2010-2011 की दूसरी तिमाही में घरेलू खपत घटकर 59,618 मी.टन (पहली तिमाही में 63432 मी.टन), और फिर तीसरी तिमाही में घटकर 57023 मी.टन और फिर चौथी तिमाही में घटकर 56210 मी.टन रह गई। वर्ष 2011-2012 की पहली तिमाही (अप्रैल-मई) में गिरावट की यह स्थिति और भी खराब हो गई क्योंकि खपत कम होकर 26646 मी.टन रह गई।

xvi. आवेदकों ने 'अभी अधुनातम अवधि' (अप्रैल-मई, 2011) में अर्थात ठीक उसी अवधि में जब आर्थोजाइलीन की कीमतों में कथित वृद्धि और उसकी मांग में तीव्र कमी दर्शाई है, में घरेलू मांग और लाभदायकता में कमी के कारण अतिरिक्त क्षति का दावा किया है।

xvii. आवेदक आईजीआई पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2009-2010 में उल्लेख किया है कि वर्ष 2009-2010 की तीसरी तिमाही में उत्पादन 'कैटालिस्ट परिवर्तन के कारण इसके एक प्लांट में उत्पादन बंद होने' और आग कारण व्यून रहा। रक्षोपाय शुल्क लगे होने के बावजूद यह गिरावट तब आई जब आयात व्यूनतर थे, इससे यह सिद्ध होता है कि घरेलू उत्पादन में कमी होने और आयातों में कोई संबंध नहीं है।

xviii. जापान से निश्चित हाट रोल्ड इस्पात उत्पादों पर यूएस-पाटनरोधी उपायों के संबंध में अपीलीय निकाय के निर्णय के अनुसार आयातों के क्षतिकारी प्रभाव को स्थानीय उद्योग पर प्रभाव डालनेवाले अन्य सभ्जी तथ्यों से पृथक एवं विभेदकारी रखा जाना चाहिए।

xix. उपर्युक्त के मद्देनजर माननीय डीजीएस को रक्षोपाय शुल्क लगाने के आवेदन को अस्वीकार कर देना चाहिए या कम से कम वर्तमान जांच बंद कर देनी चाहिए और अनन्तिम शुल्क हटाने की सिफारिश करनी चाहिए।

9. आयातकों/उपभोक्ता उद्योग का प्रत्युत्तर

इंडियन पेण्ट्स एसोसिएशन

i. घरेलू उद्योग का यह तर्क कि यूरोप और अमेरिका की लक्षित बाजारों में मन्दी आने और चीन में मांग कम होने से उनके उत्पादों का भारत की ओर विषयन होने से पूरे विश्व में बेशी उत्पादन हुआ है, उनकी

2011-2012 की पहली तिमाही की वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार गलत है।

ii. रक्षोपाय एवं पाटनरोधी जाँच में क्षति अवधि अतिव्याप्त है जिससे रक्षोपाय करार और नियमावली का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि क्षति का 'पृथक्करण' न करने से उनका लिंक टूट जाएगा और 'दोहरा संरक्षण' मिलेगा। उसके लिए न तो घरेलू उद्योग ने और न ही डीजी रक्षोपाय ने कोई स्पष्टीकरण दिया है।

iii. घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत एनटीसीएफ एवं कास्टिक सोडा मामले में दोनों की जाँच अवधि में पीओआई अलग-अलग थीं जिससे प्राधिकारी यह पता लगाने में सक्षम हो गया कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति पाटनरोधी जाँच में 'न्यून कीमत के आयातों' और रक्षोपाय जाँच में आयातों में 'वृद्धि' के कारण हुई।

iv. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग द्वारा बताए गए दोनों मामलों में, जब अन्य जाँच शुरू की गई थी, पाटनरोधी या रक्षोपाय शुल्क पहले से ही मौजूद था।

v. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि वर्तमान रक्षोपाय जाँच की पीओआई जनवरी-जून, 2011 है। तथापि, डीजी, रक्षोपाय ने प्रारंभिक निष्कर्षों के पेज 11 के पैरा (ग) के तहत यह निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान रक्षोपाय की जाँच की पीओआई जनवरी, 2009 तथा उसके पश्चात है।

vi. डीजी, रक्षोपाय ने प्रारंभिक निष्कर्ष में यह उल्लेख किया कि वर्ष 2010-11 के आयात आंकड़े 61,965 मीट्रिक टन हैं जबकि वर्ष 2011-12 के लिए आयात (वार्षिक रूप से) 55,128 मीट्रिक टन हुए जिससे 13 प्रतिशत की गिरावट परिलक्षित होती है।

vii. प्रतिवादियों को जून, 2011 के आयात आंकड़े उपलब्ध न होने से प्राकृतिक व्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है।

viii. जब याचिकाकर्ता कंपनियां अपनी वार्षिक रिपोर्टों में 'पाटन' पर क्षति का उल्लेख कर रही हैं जबकि डीजी, रक्षोपाय के समक्ष उन्होंने दावा किया कि यह क्षति 'आयातों में वृद्धि' के कारण हुई, डीजी, रक्षोपाय, डीजीएडी से इसका संदर्भ ग्रहण कर सकता है।

ix. ईयू और चीन के बीच हुई वार्ता जिस पर घरेलू उद्योग विश्वास कर रहा है और डीजी, रक्षोपाय ने, रक्षोपाय जाँच प्रारंभ करने पर किसी प्रतिबंध का

प्रावधान नहीं किया है तथापि इससे क्षति को पृथक किए बिना एकसाथ दो शुल्क लगाने का प्रावधान नहीं बनता है।

- x. पाटनरोधी जाँच प्रारंभ किए जाने की अधिसूचना के अनुसार थिरुमलाई केमिकल्स और आईजी पेट्रोकेमिकल्स जो थैलिक एनहाइड्राइड के आयातक हैं को, सेंचुरी प्लाईबोर्ड(आई) लिमिटेड और अन्य बनाम अपर सचिव एवं नामित प्राधिकारी एवं अन्य के मामले में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए अभी हाल ही के निर्णय के मद्देनजर, जिसमें यह कहा गया है कि जो कंपनी पीयूसी का आयात करती है, घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं बन सकती, घरेलू उद्योग की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- xi. वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 2010-11 में खपत की अपक्षा आयातों में 1% की वृद्धि हुई है। आयातों के स्थाई स्तर को ध्यान में रखते हुए इसने घरेलू उद्योग की बिक्री को समग्र मांग से विस्थापित नहीं किया है।
- xii. भारत में थैलिक एनहाइड्राइड के बाजार में विस्तार हुआ है क्योंकि वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 2010-11 में कुल मांग में 38% की बढ़ोतरी हुई और इसी तरह प्रतिष्ठापित क्षमता जो 2007-08 में 232000 मी.टन थी वर्ष 2010-11 में बढ़कर 268000 मी.टन हो गई।
- xiii. घरेलू बिक्री में समग्र वृद्धि वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 2010-11 में 50% की रहीं जो उसी अवधि के लिए आयातों में वृद्धि और मांग में वृद्धि से अधिक है।
- xiv. घरेलू बिक्री कीमत जो वर्ष 2007-08 में आईएनआर 61 रुपये प्रतिकिग्रा. थी बढ़कर 2010-11 में आईएनआर 66 रुपये प्रतिकिग्रा. हो गई, इसमें वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 2010-11 में 8% की वृद्धि हुई और इससे कीमत में कमी या ह्रास का दावा नहीं बनता है।
- xv. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आर्थो-जाइलिन की कीमत में जितनी वृद्धि हुई उतनी वृद्धि थैलिक एनहाइड्राइड की कीमत में नहीं हुई जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई जबकि वित्त वर्ष 2012 के वित्तीय परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि कच्चे माल की कीमत में उतार-चढ़ाव का घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और यह कि घरेलू उद्योग के लिए नियंत निरोधक नहीं है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग अपनी घरेलू बिक्री कीमत को बढ़ाने में सक्षम रहा।

xvi. थिरुमलाई केमिकल्स को इसकी मलेशिया और सिंगापुर में स्थित अनुषंगी कंपनियों के प्रचालन के कारण भारी हानि हुई जैसाकि कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया गया है और यह हानि थैलिक एनहाइड्राइड के बढ़े हुए आयातों के कारण नहीं थी।

xvii. इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2007-08 में 64% था वर्ष 2010-11 में बढ़कर 70% हो गया।

xviii. आईपीए के द्वारा अपने विगत के आत्म-निवेदनों में यथातल्लिखित आयात आंकड़ों में विसंगति का ना तो घरेलू उद्योग ने और ना ही डीजीरक्षोपाय ने कोई स्पष्टीकरण दिया है।

xix. पीएनजे का सकल उल्लंघन जांच के आयोजन में हुई कमियों और घरेलू उद्योग की याचिका में कमी के मद्देनजर यह जांच समाप्त कर दी जानी चाहिए।

10. इंडियन प्लास्टिसायर्जर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन(आईपीएमए) और पोलिएस्टर रेजिन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन(पीआरएमए)।

- वर्तमान जांच से पहले घरेलू उद्योग ने पाटन के संबंध में ना तो कोई उल्लेख किया और ना ही कोई आरोप लगाया।
- इसके अतिरिक्त भारत में आयातों में अचानक वृद्धि के संबंध में रक्षोपाय शुल्क समग्र रूप से लगाया गया न कि विशिष्ट देशों पर।
- समानांतर पाटनरोधी जांच की जांच अवधि में ही वर्तमान जांच की अवधि शामिल है।
- समान याचिकाकर्ताओं ने अधिकांश स्रोतों जैसे कोरिया, ताइवान और इज़्राइल से होने वाली क्षति के लिए पाटन का दावा किया है।
- माननीय महानिदेशक, रक्षोपाय को वर्तमान मामले में कार्यवाही करने के बजाय यह मामला माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेज देना चाहिए।
- चूंकि, दिसंबर, 2010 की उत्तरवर्ती अवधि में आयातों में काफी गिरावट होने के कारण याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई अतिरिक्त क्षति हुई ही नहीं है।
- याचिकाकर्ताओं ने यह तथ्य छिपाया है कि उन्होंने रक्षोपाय शुल्क पर तीन वर्षों की अवधि के लिए अंतरिम राहत की मांग करते हुए बंबई उच्च न्यायालय में दस्तक दी है।
- जांच की अवधि में 28 माह पुराने आंकड़ों को शामिल किया गया है जिससे क्षति विश्लेषण में विकृति की गई है और इसमें हाल की प्रवृत्ति को नहीं दर्शाया गया है।

ix. याचिकाकर्ताओं ने गुमराह करने के लिए उत्पादकों को अपनी इच्छानुसार शामिल किया है और हटाया (मैसर्स एसआई ग्रुप को हटा दिया गया) है जिससे उनके क्षति दावे को अनावश्यक लाभ हुआ है।

x. याचिकाकर्ताओं ने मैसर्स एशियन पेंट्स लिंग को छोड़ दिया जिसका नॉन-केप्टिव उद्देश्यों के लिए संबंधित वस्तु का 10,496 मी.टन अर्थात् 44% विनिर्माण है। इसके बावजूद कि एशियन पेंट्स प्राथमिकतः लुभावने ढंग से खपत कर रहा है, उनके बाजार संबंधी विचार स्वतंत्र हैं।

xi. मैसर्स आईजी पेट्रोकेमिकल्स एवं थिरमलाई केमिकल्स लिंग द्वारा आयात की गई मात्रा बहुत अधिक है और उनके द्वारा दावा की गई क्षति बिना किसी औचित्य के स्व-निर्धारित है।

xii. वर्तमान याचिकाकर्ताओं की घरेलू बिक्री में सतत वृद्धि हुई है जबकि आयातों के बाजार हिस्से में जो वर्ष 2010-11 में 37% था, कभी होकर अप्रैल-मई, 2011 में 26% हो गया।

xiii. वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में विस्तार से औसत क्षमता उपयोग 77% रहा जबकि अन्य तथ्यों ने याचिकाकर्ताओं के उत्पादन और क्षमता उपयोग को प्रभावित किया है।

xiv. याचिकाकर्ताओं का उत्पादन वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही की तुलना में वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही में 8% बढ़ा है जबकि याचिकाकर्ताओं की बिक्री में 23% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं के उत्पादन के अनुपात में घरेलू बिक्री जो वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही में 66% थी, बढ़कर वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही में 75% हो गई। इसलिए क्षति, यदि कोई निर्यात बाजार में घाटे के कारण हुई है न कि अन्य किसी कारण से।

xv. मैसर्स आईजी पेट्रोकेमिकल्स और मैसर्स थिरमलाई केमिकल्स के तुलन-पत्र में वित्त वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान मुनाफा दर्शाया गया है। वस्तुतः वित्त वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही में आईजी पेट्रो का प्रचालन मुनाफा 9.30 करोड़ रु० और थिरमलाई का 9.76 करोड़ रु० था।

xvi. भारत से थैलिक एनहाइड्राइड का चीन को निर्यात करने पर पाटनशुल्क है। अतः लाभ में कभी अन्य तथ्यों के कारण आई है न कि भारत को होने वाले आयात से।

xvii. याचिकाकर्ताओं की वार्षिक रिपोर्टों में यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता घरेलू कच्चे माल का उपयोग करते हैं जो भारी मात्रा में उपलब्ध है और जिससे लाभदायक बिक्री सुनिश्चित होती है।

xviii. चूंकि अग्रिम लाइसेंस के अधीन किए गए आयातों का उपयोग औद्योगिक उपयोगकर्ताओं द्वारा निर्यात उद्देश्यों के लिए किया जाता है, इसलिए उक्त आयातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकती है।

ix. सरकार की नीति में परिवर्तन की वजह से उद्योग प्रभावित हुए हैं न कि आयातों में वृद्धि से।

xx. सीमाशुल्क 30% की दर से घटाकर 7.5% करने के पश्चात् घरेलू उद्योग ने अनावश्यक व्यापार उपचारी संरक्षण की मांग की है।

xxi. डीजीएसडी ने कोरिया, इज़ाइल और ताइवान से थैलिक एनहाइड्राइड के आयातों के संबंध में समानांतर पाटन-रोधी जांच में आरोपित पाटित आयात जांच के प्रभाव पर विचार नहीं किया है।

xxii. रक्षोपाय शुल्क लगाने से थैलिक एनहाइड्राइड की कीमत में उतार-चढ़ाव होगा और इसका प्लास्टिसाइजर मैन्युफैक्चरर्स एवं अन्य आश्रित उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जिससे वे अन-अर्थक्षम हो जाएंगी और उनके संयंत्र बंद हो जाएंगे।

xxiii. सीमाशुल्क में 2.5% की दर से टैरिफ संरक्षण और घरेलू उद्योग को आर्थोजाइलिन की प्रचुर घरेलू आपूर्ति कच्चे माल की लागत और आपूर्ति के रूप में स्पष्टतया सुस्थापित है।

xxiv. याचिकाकर्ताओं ने इस जांच के प्रारंभ के पश्चात् कीमतें बढ़ा दी हैं और लगातार बढ़ाते रहे हैं जिससे अंतिम उपयोक्ता को नुकसान हुआ है।

xxv. गंभीर क्षति को रोकने या उसका उपचार करने और समायोजन को सुलभ बनाने के उद्देश्य और साधनों के बीच संगत संयोजन बनाने के लिए रक्षोपाय नियमावली के नियम 5(2) के अन्तर्गत समायोजन प्लान का प्रावधान एक अधिदेशित अपेक्षा है।

xxvi. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग बनाम शुक्ला और बंधुओं के मामले में निर्णय के अनुसार डीजीएसजी अधिसूचना जारी करने और बढ़ाए हुए समय के समाप्त होने से पहले इस मुद्दे पर एसोसिएशन के आत्मनिवेदन को स्वीकार करने के लिए उत्तरदायी है।

xxvii. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़े पाटनरोधी याचिका में दायर आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं जिस संबंध में विगत रक्षोपाय जांच निष्कर्षों और वर्तमान मामले में प्रारंभिक निष्कर्षों को डीजीएसजी द्वारा जारी कर दिया गया है। पर्याप्त और व्यायोचित स्पष्टीकरण के अभाव में इन आंकड़ों को अविश्वसनीय मानते हुए खारिज कर दिया जाना चाहिए।

xxviii. डीजीएसजी यह प्रकट करने में असफल रहा कि विकासशील देशों से आयातों को किस तरह जाँचा गया। याचिकाकर्ताओं को कथित क्षति, यदि कोई, कोरिया गणराज्य, ताइवान और इज़ाइल से हुई है जिसके लिए एक पाटनरोधी याचिका अलग से दायर की गई है। आयात विश्लेषण में भी इन्हीं देशों अर्थात् कोरिया गणराज्य और ताइवान पर प्रकाश डाला गया है।

11. महानिदेशक के निष्कर्ष

मैंने मामले के रिकॉर्ड, घरेलू उत्पादकों, उपयोगकर्ताओं/आयातकों, निर्यातकों और निर्यातक राष्ट्रों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए आत्म-निवेदनों और उनसे उत्पन्न मुद्दों का निम्नलिखित में उपयुक्त स्थानों पर निस्तारण किया गया है:

क) जांचाधीन उत्पाद: जांचाधीन उत्पाद थैलिक एनहाइड्राइड(पीएएन) है जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (सीटीए) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 29173500 के अंतर्गत आता है। थैलिक एनहाइड्राइड थैलिक एसिड का प्रमुख वाणिज्यिक रूप है। यह सफेद क्रिश्टलाइन ठोस है, इसका उपयोग सिंथेटिक रेजिन बनाने में किया जाता है जो पेंट उद्योग में बाइंडर का काम करता है। थैलिक एनहाइड्राइड का प्राथमिक प्रयोग बिनाइल क्लोराइड से प्लास्टिक का उत्पादन करने में रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में किया जाता है। थैलेट ईस्टर्स, जो प्लास्टिसाइजर्स के रूप में काम करते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड से व्युत्पादित किए जाते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड का पोलिएटर रेजिन के उत्पादन में महत्वपूर्ण उपयोग होता है और पेंट में उपयोग किए जाने वाले एल्काइड रेजिनों तथा लिक्स, कुछ रंगों, कीटरोधकों और पोलियूरीथेंस के लिए पोलिएस्टर पोलिओल के उत्पादन में इसका अल्प उपयोग होता है। थैलिक एनहाइड्राइड का रासायनिक फार्मूला है सी४एच४ओ३। इसका उत्पादन आर्थोलाइजिन का हवा के साथ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करके या नैण्थालिन का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करके किया जाता है। घरेलू उत्पादक ओएक्स रूट का प्रयोग करते हैं। यह ओएक्स को एक रिएक्टर के जरिए, जोकि मिट्टी या केटालिस्ट के साथ कोट किए गए पोर्सिलिन रिंग्स का एक एरेजमेंट होता है, पास करके बनाया जाता है। ओएक्स की आक्सीकरण प्रक्रिया के पश्चात् रिएक्टर में पालिश करने और फलेक बनाने से थैलिक एनहाइड्राइड का सफेद या पीले क्रिस्टल के रूप में उत्पादन होता है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने जांच के अधीन उत्पाद के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है। इसलिए यह संयुष्ट है कि जांचाधीन उत्पाद “थैलिक एनहाइड्राइड” जो सीमाशुल्क अधिनियम की अनुसूची I के शीर्ष संख्या 2917.3500 के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त, आयातित थैलिक एनहाइड्राइड और घरेलू रूप से उत्पादिक थैलिक एनहाइड्राइड की उत्पादन प्रक्रिया, उसके गुण-धर्म और अंतिम उपयोग के बीच किसी भिन्नता का मुद्दा इस जांच की अवधि के दौरान किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा नहीं उठाया गया है। इसलिए, यह धारित किया जाता है कि घरेलू रूप से उत्पादित थैलिक एनहाइड्राइड जांचाधीन आयातित उत्पाद के बारे में समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी दायरे के अंतर्गत आता है और घरेलू रूप से उत्पादित थैलिक एनहाइड्राइड रक्षोपाय शुल्क नियमावली 1997 के नियम 2 (ड.) के आशय के अंतर्गत आयातित थैलिक एनहाइड्राइड वस्तु के समान है।

ख) घरेलू उद्योग: भारत में 5 घरेलू उत्पादक हैं जो थैलिक एनहाइड्राइड का विनिर्माण करते हैं। तीन घरेलू उत्पादकों अर्थात् 1) थिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड, रानीपेट, तमिलनाडु 2) आईजी पेट्रोकेमिकल्स लिंग, तलोजा, महाराष्ट्र, 3) मैसूर पेट्रोकेमिकल्स लिंग रायचूर, कर्नाटक ने संयुक्त रूप से यह याचिका तायर की है। दो उत्पादकों अर्थात् मैसर्स एसियन पेट्रस लिंग और मैसर्स एसआई ग्रुप इंडिया लिंग इस याचिका में शामिल नहीं हैं। इन तीन आवेदकों का हिस्सा वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही से वर्ष 2011-12 की दूसरी तिमाही की अवधि के दौरान 86% से 87% तक घटता-बढ़ता रहा। इस प्रकार, आवेदक उत्पादकों का सामूहिक आक्टपुट भारत में थैलिक एनहाइड्राइड के कुल उत्पादन का काफी बड़ा हिस्सा बनता है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आवेदक के विरुद्ध घरेलू उद्योग होने का कोई दावा नहीं किया गया है। अतः यह धारित किया जाता है कि तीनों आवेदक घरेलू उत्पादक हैं और वे रक्षोपाय शुल्क नियमावली, 1997 की धारा 8 ख (6)(ख)(iii) के अन्तर्गत यथाअपेक्षित एवं यथापरिभाषित आशय के अन्तर्गत घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ग) जांच की अवधि (पीओआई): सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975, सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं आंकलन) नियमावली, 1997, गाट के साथ रक्षोपाय संबंधी करार और उनके संगत अनुच्छेद XIX में विशेषरूप से यह परिभाषित नहीं किया गया है कि जांच की अवधि क्या होनी चाहिए। रक्षोपाय संबंधी विभिन्न मामला विधियों से यह स्पष्ट है कि रक्षोपाय संबंधी घरेलू कानूनों और गाट के साथजे रक्षोपाय करार एवं अनुच्छेद XIX में जांच की अवधि के संबंध में विशिष्ट दिशानिर्देशों का प्रावधान नहीं है सिवाय इस तथ्य के कि संगत जांच अवधि काफी लंबी होनी चाहिए जिससे संवर्द्धित आयात और गंभीर क्षति के संबंध में निष्कर्ष निकला जा सके। जांच शुरुआत करने के नाटिस और प्रारंभिक निष्कर्षों में मई, 2011 तक के आयात आंकड़ों पर विचार किया गया था। अब आयात आंकड़ों को सितंबर, 2011 तक अद्यतन कर दिया गया है। चूंकि प्रारंभिक निष्कर्ष 23 सितंबर, 2011 को जारी किए गए थे इसलिए जांच की अवधि को माह सितंबर, 2011 तक सीमित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अस्थाई उतार-चढ़ावों और मौसमी प्रभावों, यदि कोई, का समान रूप से आंकलन करने के लिए तर्कसंगत रूप से दीर्घ अवधि पर विचार किया गया।

घ) आंकड़ों के स्रोत जून, 2011 तक के आयात आंकड़े डीजीसीआईएस से लिए गए हैं। जुलाई, 2011 से सितंबर, 2011 तक के आयात आंकड़े आईबीआईएस से लिए गए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही के संबंध में विभिन्न आर्थिक प्राचलों के आंकड़ों का इस निदेशालय द्वारा यथासंभव सीमा तक सत्यापन कर लिया गया है और क्षति विश्लेषण के लिए सत्यापित आंकड़ों पर ही विचार किया गया है। विभिन्न आर्थिक

प्राचलनों के संबंध में वर्ष 2011-12 की दूसरी तिमाही के लिए आंकड़ों को आवेदक द्वारा यथा-प्रस्तुत के रूप में ग्रहण किया गया है।

५.) संवर्द्धित आयात: भारत में थैलिक एनहाइड्राइड का कई देशों से और प्राथमिकतः कोरिया गणराज्य, इज़राइल, ईरान और ताइवान से आयात किया जाता है। थैलिक एनहाइड्राइड के आयातों में समग्र रूप से तथा घरेलू उत्पादन की तुलना में बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाई गई है जिससे क्षति या क्षति की स्थिति उत्पन्न हो गई। वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही से वर्ष 2011-12 की दूसरी तिमाही के दौरान थैलिक एनहाइड्राइड की मात्रा निम्नलिखित है:

वित्तीय वर्ष	तिमाही	कुल आयात (मी.टन)	घरेलू (मी.टन)	उत्पादन (मी.टन)
2008-09	चौथी तिमाही	6103		49607
2009-10	पहली तिमाही	7240		47985
	दूसरी तिमाही	5163		58259
	तीसरी तिमाही	8526		40437
	चौथी तिमाही	7169		52853
2010-11	पहली तिमाही	23615		55503
	दूसरी तिमाही	8611		58168
	तीसरी तिमाही	18082		52319
	चौथी तिमाही	10933		51271
2011-12	पहली तिमाही	9752		50124
	दूसरी तिमाही	10436		51220

आयातों में समग्र एवं संगत रूप से वृद्धि हुई है वर्ष 2009-10 की पहली और दूसरी तिमाही में आयात 12403 मी.टन से बढ़कर वर्ष 2011-12 की पहली और दूसरी तिमाही में 20,188 मी.टन हो गए जिससे समग्र रूप में 63%- की बढ़ोत्तरी हुई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही में 9752 मी.टन आयात हुआ जो वर्ष 2011-12 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 10,436 मी.टन हो गा अर्थात् इसमें 7% की बढ़ोत्तरी हुई है। संगत रूप से, यद्यपि वर्ष 2010-11 की पहली तिमाही से दूसरी तिमाही तक की तुलना में वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही से दूसरी तिमाही तक घरेलू उत्पादन की तुलना में आयातों के हिस्से में कमी आई है परन्तु हाल ही की

अवधि में वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही के 19.45 से बढ़कर वर्ष 2011-12 की दूसरी तिमाही में 20.37 हो गया।

इस प्रकार, देखा जा सकता है कि उत्पादन की तुलना में आयातों की जाता में वृद्धि समग्र और संगत दोनों रूपों में हुई। यह धारित किया जाता है कि थैलिक एनहाइड्राइड के आयात समग्र एवं संगत रूप से बढ़े और आयातों में वृद्धि की प्रवृत्ति बढ़ती रही जो अधिनियम की धारा 8 ख के आशय के अंतर्गत “संवर्द्धित आयात” बनने के लिए पर्याप्त है।

च) अप्रत्याशित विकास: वर्ष 2009 के पश्चात् यूरोप और अमेरिका की लक्ष्य बाजारों में कमी और अभी हाल ही में स्पेन, इटली, पुर्तगाल, मिस्र और आयरलैंड में संकट के कारण परिवृश्य खराब हुए जिसके परिणामस्वरूप उत्पलब्ध क्षमता की तुलना में बेसी उत्पादन इसलिए हुआ कि संयंत्रों को प्रभावी उत्पादन के लिए अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप लक्ष्य हासिल करने हेतु पर्याप्त रन-रेट पर कार्य करना पड़ा अतः फर्मों को दरों में कटौती कर पाना भुक्तिकल हो गया। इसके कारण उद्योग में भारी बेसी उत्पादन हुआ जिन्हें वैश्विक आर्थिक मंदी के मध्य भारत के विकास की प्रत्याशाओं को देखते हुए भारत में सरणीकृत किया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान में कोरिया और ताइवान से होने वाले आयातों पर अपने-अपने देशों में 5 वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया है इससे कोरिया और ताइवान से थैलिक एनहाइड्राइड का चीन और पाकिस्तान को होने वाला आयात प्रतिबंधित हो गया। इस प्रतिबंध के कारण कोरिया और ताइवान के निर्यातोन्मुख उत्पादन और निर्यातक नई और मौजूदा बाजारों की तलाश करने लगे। भारत में थैलिक एनहाइड्राइड की बढ़ती मांग और अच्छे बाजार अवसरों ने कोरिया और ताइवान के उत्पादक सह निर्यातकों को अपना माल भारत निर्यात करने के लिए आकर्षित किया जिससे आयात में अनावश्यक वृद्धि हुई।

कोरिया से निर्यात

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12(पहली तिमाही)	2011-12(दूसरी तिमाही)
कोरिया से भारत को निर्यात(मी.टन)	14274	11167	30306	2763	5,749
कुल पीए निर्यात(मी.टन)	37465	28098	61241	9752	10436
कुल पीए निर्यातों का % के रूप में	38%	40%	49%	28%	55%

ताइवान से निर्यात

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12(पहली तिमाही)	2011-12(दूसरी तिमाही)
ताइवान से भारत को निर्यात(मी.टन)	4555	2099	12725	2581	1,813
कुल पीए निर्यात(मी.टन)	37465	28098	61241	9752	10436
कुल पीए निर्यातों का % के रूप में	12%	7%	21%	26%	17%

(स्रोत: जून, 2011 तक के आंकड़े डीजीसीआईएस से और शेष याचिका से लिए गए हैं)

परिणामस्वरूप ये देखा जा सकता है कि कोरिया से भारत को थैलिक एनहाइड्राइड के निर्यात जो वर्ष 2008-09 में 14274 मी.टन थे वर्ष 2011-12 में बढ़कर 30306 मी.टन हो गए। यह वर्ष 2010-11 में भारत को हुए थैलिक एनहाइड्राइड के कुल निर्यात का 49% बनता है जो 2011-12 की पहली तिमाही में घटकर 28% हो गया परन्तु 2011-12 की दूसरी तिमाही में तेजी से बढ़कर 55% हो गया। इसी तरह, थैलिक एनहाइड्राइड का ताइवान से निर्यात जो वर्ष 2008-09 में 4555 मी.टन था वर्ष 2010-11 में बढ़कर 12725 मी.टन हो गया। यह वर्ष 2010-11 में भारत को हुए थैलिक एनहाइड्राइड के कुल निर्यात का 21% है जो 2011-12 की पहली तिमाही में बढ़कर 26% हो गया और तत्पश्चात् 2011-12 की दूसरी तिमाही में थोड़ा सा घटकर 17% हो गया। इससे यह प्रदर्शित होता है कि कोरिया और ताइवान से थैलिक एनहाइड्राइड का बढ़ता हुआ आयात प्रत्याशित विकास है इस बढ़ते हुए आयात से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई और गंभीर क्षति की स्थिति उत्पन्न हो गई।

छ) गंभीर क्षति और गंभीर क्षति की स्थिति: “गंभीर क्षति” का आशय ऐसी क्षति से है जो घरेलू उद्योग के लिए समग्र रूप से हानिकर हो और “गंभीर क्षति की स्थिति” का आशय गंभीर क्षति के स्पष्ट एवं आसन्न खतरे से है।

(i) रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.2(क) और सीमाशुल्क टैरिफ़ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं आंकलन) नियमावली, 1997 के नियम 8 के अनुबंध में तकनीकी रूप से यह अपेक्षित है कि गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की स्थिति का निर्धारण करने के लिए कुछ सूचीबद्ध तथ्यों और

अन्य संगत तथ्यों का मूल्यांकन किया जाए। तथापि, ये उपबंध यह स्पष्ट नहीं करते हैं कि इस मूल्यांकन में क्या प्रदर्शित किया जाए। इस तरह का कोई भी मूल्यांकन अलग-अलग मामलों में अलग-अलग उद्योगों के मामले में खास तथ्यों और संबंधित उद्योग की स्थिति के आधार पर अलग-अलग होगा। प्रत्येक सूचीबद्ध तथ्य के मूल्यांकन को अनिवार्यतः यह स्पष्ट नहीं करना चाहिए कि ऐसा प्रत्येक तथ्य “गिरावट” है। उदाहरणार्थ एक मामले में बिक्री, रोजगार और उत्पदकता में महत्वपूर्ण गिरावट आ सकती है जो उद्योग की स्थिति में “महत्वपूर्ण समग्र हानि” प्रदर्शित करेगा और इसलिए इससे गंभीर क्षति का निष्कर्ष न्यायोचित ठहरेगा। दूसरे मामले में हो सकता है कि कोई तथ्य पतनशील न हो परन्तु समग्र स्थिति यह प्रदर्शित करे कि उद्योग को “महत्वपूर्ण समग्र हानि” हो रही है। इस प्रकार, सभी सूचीबद्ध तथ्यों और किसी अन्य संगत तथ्यों का तकनीकी परीक्षण करने के अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि घरेलू उद्योग की स्थिति से जुड़े सभी संगत तथ्यों के आलोक में घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन किया जाए।²

ii) तद्वारा, गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की स्थिति का विश्लेषण करते समय नियमावली में उललिखित सभी तथ्यों तथा गंभीर क्षति या गंभीर क्षति का निर्धारण करने के लिए संगत अन्य सभी तथ्यों पर विचार किया गया। किसी एक तथ्य को विशेष रूप से झुकावशील नहीं माना गया। संगत बिजनेस प्रक्रिया के संदर्भ में सभी संगत तथ्यों और प्रतिस्पर्धा की स्थितियों, 'सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8(ख) (6) (घ)

जो प्रभावित उद्योग से संगत हैं, पर विचार किया गया। गंभीर क्षति या गंभीर क्षति जो निर्धारण घरेलू उद्योग की स्थिति से संबंध रखने वाले सभी संगत तथ्यों के आलोक में घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति के मूल्यांकन पर आधारित है।

ज) क्षति: यह पाया गया कि थैलिक एनहाइड्राइड के बढ़ते हुए आयातों से थैलिक एनहाइड्राइड के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है और गंभीर क्षति की स्थिति उत्पन्न हुई है, जैसाकि निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है:

i) बाजार हिस्सा: उत्पादन की तुलना में घरेलू बाजार में आयातों का हिस्सा जो वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही में 11% था, वर्ष 2011-12 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 17% हो गया। इसी तरह खपत की तुलना में घरेलू बाजार में आयात का हिस्सा जो वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही में 16% था बढ़कर वर्ष 2011-12 की दूसरी तिमाही में 19% हो गया। घरेलू बाजार में आयातों का हिस्सा जो वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही में 11% था वर्ष 2011-12 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 17% हो गया। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू खपत में घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा तेजी से कम हुआ है। आवेदकों का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2009-10 की पहली-दूसरी तिमाही में 86% था, वर्ष 2011-12 की पहली-दूसरी तिमाही में घटकर 80% रह गया अर्थात् इसमें 6% की गिरावट आई। घरेलू उद्योग की खपत और उत्पादन तथा आयातों की बाजार हिस्से में वृद्धि को दर्शाने वाली विस्तृत तालिका निम्नलिखित है:

	2008-09	2009-10				2010-11				2011-12	
तिमाही	चौथी तिमाही	पहलीतिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहलीनिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहलीतिमाही	दूसरी तिमाही
आयात (मी.टन)	6103	7240	5163	8526	7169	23615	8611	18082	10933	9752	10436
घरेलू उत्पादन (मी.टन)	49607	47985	58259	40437	52853	55503	58168	52319	51271	50124	51220
कुल उत्पाद्य मात्रा (मी.टन)	55710	55225	63422	48963	60022	79118	66779	70401	62204	59876	61656
आयातों का हिस्सा (%)	11	13	8	17	12	30	13	26	18	16	17
घरेलू उत्पादन का % हिस्सा	89	87	92	83	88	70	87	74	82	84	83
उद्योग द्वारा घरेलू बिक्री (मी.टन)	32613	35530	41289	39427	40696	39817	51007	38941	44553	38149	44670
भारत में खपत (मी.टन)	38716	42770	46452	47953	47865	63432	59618	57023	55486	47901	55106
आयातों का बाजार हिस्सा(%)	16	17	11	18	15	37	14	32	20	20	19
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा(%)	84	83	89	82	85	63	86	68	80	80	81

² अर्जेन्टीना फुटवियर मामले के संबंध में डब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय की रिपोर्ट के पैरा 139 पर आधारित।

ii) **उत्पादन:** घरेलू उद्योग के संबंध में उत्पादन संबंधी आंकड़े ऊपर दर्शाए गए हैं। **घरेलू उत्पादन** वर्ष (2009-10) की दूसरी तिमाही में 58259 मी.टन थे, घटकर वर्ष (2010-11) की दूसरी तिमाही में 58168 मी.टन और अन्ततः वर्ष (2011-12) की दूसरी तिमाही में घटकर 51220 मी.टन रह गए। वार्षिकीकृत आधार पर उत्पादन में वर्ष 2010-11 के स्तर से वर्ष 2011-12 में कमी आई है।

iii) **क्षमता उपयोग:** अभी हाल ही की अवधि में घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में अत्यधिक गिरावट हुई है अर्थात् यह वर्ष 2010-11 की दूसरी तिमाही में 87% से घटकर वर्ष 2011-12 की दूसरी तिमाही में 76% रह गई। मैसूर पेट्रोकैमिकल्स का संयंत्र भारी मात्रा में भंडार इकट्ठा हो जाने के कारण 20.6.2011 से अनिश्चित काल के लिए बंद पड़ा हुआ है। घरेलू उद्योग से संबंधित क्षमता उपयोग के आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं:-

वर्ष	तिमाही	उत्पादन(मी.टन)	प्रतिष्ठापितक्षमता(मी.टन)	क्षमता उपयोग(%)	वस्तुसूची (मी.टन)
2008-09	चौथी तिमाही	49607	59528	83	5365
2009-10	पहली तिमाही	47985	67028	72	1604
	दूसरी तिमाही	58259	67028	87	6101
	तीसरी तिमाही	40437	67028	60	487
	चौथी तिमाही	52853	67028	79	4530
2010-11	पहली तिमाही	55503	67028	83	4468
	दूसरी तिमाही	58168	67028	87	2484
	तीसरी	52319	67028	78	9232

	तिमाही				
	चौथी तिमाही	51271	67028	76	5718
2011-12	पहली तिमाही	50124	67028	75	8131
	दूसरी तिमाही	51220	67028	76	8405

iv) इन्वेंटरीज़: चूंकि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम हो रहा है और आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ रहा है, इसलिए घरेलू उद्योग अपनी बिक्री की मात्रा बढ़ाने में अक्षम रहा और इसे संग्रहित इन्वेंटरीज़ की समस्या का सामना करना पड़ा। संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान इन्वेंटरीज़ के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि इन्वेंटरी जो वर्ष 2009-10 में 4530 मी.टन थी, 2010-11 में बढ़कर 5718 मी.टन और (2011-12) की पहली तिमाही में 8131 मी.टन और (2011-12) की दूसरी तिमाही में 8405 मी.टन हो गई। इस तरह यह 2009-10 के स्तर से वर्ष 2011-12 में लगभग दोगुनी हो गई जिससे घरेलू उद्योग की नाजुक स्थिति प्रदर्शित होती है। इसके अतिरिक्त, इन्वेंटरीज़ में यह वृद्धि एक घरेलू उत्पादक द्वारा उत्पादन बंद कर दिए जाने के बावजूद हुई है।

v) घरेलू बिक्री: अधोलिखित तालिका में घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री और कुल निर्यात दर्शाया गया है:

वर्ष	तिमाही	घरेलू बिक्री(मी.टन)	निर्यात(मी.टन)
2008-09	चौथी तिमाही	32613	14183
2009-10	पहली तिमाही	35530	16216
	दूसरी तिमाही	41289	12471
	तीसरी तिमाही	39427	625
	चौथी तिमाही	40696	8114
2010-11	पहली तिमाही	39817	15749
	दूसरी तिमाही	51007	9146
	तीसरी तिमाही	38941	6630
	चौथी तिमाही	44553	10231
2011-12	पहली तिमाही	38149	9563
	दूसरी तिमाही	44670	8312

(i) घरेलू बिक्री वर्ष (2009-10) की दूसरी तिमाही में 41289 मी.टन की हुई थी जो वर्ष (2010-11) की दूसरी तिमाही में बढ़कर 51007 मी.टन हो गई परन्तु वर्ष (2011) की दूसरी तिमाही में घटकर 44670 मी.टन हो गई। वार्षिकीकृत आधार पर उत्पादन में वर्ष 2010-11 के स्तर से वर्ष 2011-12 में कमी आई। घरेलू उद्योग की बिक्री वर्ष (2010-11) की चौथी तिमाही तक बढ़ी है परन्तु 2011-12 की पहली तिमाही के दौरान इसमें गिरावट आई है। वर्ष 2010-11 की चौथी तिमाही तक बिक्री की मात्रा में वृद्धि का कारण यह बताया गया कि भारतीय उत्पदकों में से एक, जो याचिकाकर्ता भी है, ईओयू से डीटीए को अंतरित हो गया और उसने भारतीय बाजार में बिक्री करना शुरू कर दिया जिससे बिक्री में बढ़ोतरी हुई। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चूंकि इसकी एक इकाई ईओयू से डीटीए में अंतरित हो गई जिससे यह स्वभावतः घरेलू बाजार में बिक्री करने लगी।

(ii) तथापि, निर्यातों में जो वर्ष (2009-10) की दूसरी तिमाही में 12471 मी.टन थे, घटकर वर्ष (2010-11) की दूसरी तिमाही में 9146 मी.टन और वर्ष (2011-12) में पुनः घटकर 8312 मी.टन हो गए। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री में भी घट्ज 2010-11 की चौथी तिमाही से वर्ष 2011-12 की दूसरी तिमाही तक लगातार गिरावट आई जो लगभग 19% थी जिससे और अधिक क्षति हुई।

(iii) यह देखा जा सकता है कि संबंधित उत्पाद की मांग में काफी हृद तक गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि यह इस कारण से हुआ कि अनुप्रवाही उत्पाद डायोक्टायल थैलेट का आयात शुरू हो गया क्योंकि इसकी कीमतें घट रहीं थीं और अनुप्रवाही उद्योग में भारत में इसका उत्पादन करने के बजाय इसका आयात करना अधिक किफायती समझा। इससे थैलिक एनहाइड्राइड की मांग में गिरावट आई। घरेलू उद्योग मांग में गिरावट की समस्या से पहले ही जूझ रहा था और तब आयातों में वृद्धि ने पहले से ही रही क्षति को और अधिक बढ़ा दिया। घरेलू उद्योग को अपना उत्पाद, घरेलू मांग होने के बावजूद, निर्यात करने के लिए बाध्य होना पड़ा। ये निर्यात रुचिकर नहीं थे परन्तु घरेलू उद्योग की मजबूरी थी जो देश में उत्पाद के आयातों की सतत वृद्धि के कारण करने पड़े। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि हाल की अवधि में निर्यातों में भी गिरावट आनी शुरू हो गई जिससे क्षति में और अधिक वृद्धि हुई।

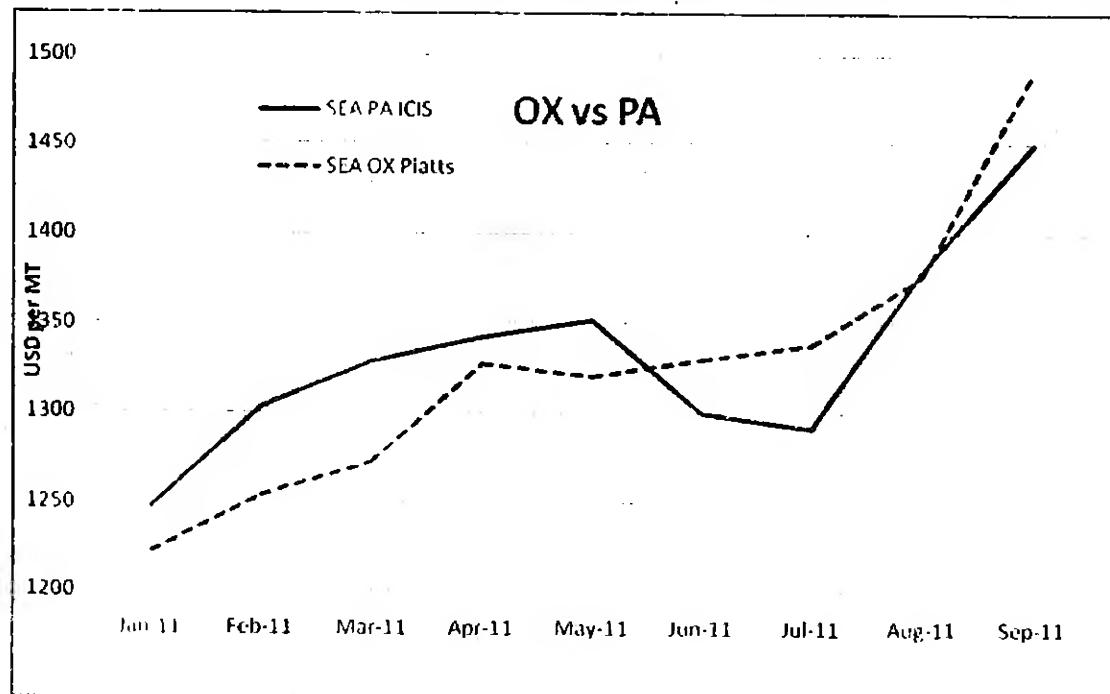
vi) रोजगार: क्षति अवधि के दौरान रोजगार और उत्पादकता के स्तर में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया। इसमें सामान्य वृद्धि दर्शाई गई। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि ये

प्राचल अन्य कई प्राचलों पर निर्भर हैं और इनसे घरेलू उद्योग पर आयातों का प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है।

vii) लाभ एवं हानि(नकद लाभ): घरेलू उद्योग की लाभदायिकता में इतनी तेजी से गिरावट आई कि घरेलू उद्योग अब वित्तीय घाटे से गुजर रहा है। यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है:-

	रु० लाख में
वित्तीय वर्ष	लाभदायकता
2009-10	2583
2010-11(चौथी तिमाही)	-378
2011-12(पहली तिमाही)	-384
2011-12(दूसरीतिमाही)	-2111

यह देखा जा सकता है कि कच्चे माल की कीमतों में तीव्र वृद्धि से घरेलू उद्योग की लाभ क्षमता में कमी आई जिससे उनको भारी नुकसान हुआ। थैलिक एनहाइड्राइड का उत्पादन आर्थो-जाइलिन का ऑक्सीकरण करके किया जाता है। पैरा-जाइलिन की कीमतों में गिरावट के कारण उत्पदकों ने आर्थो-जाइलिन का उत्पादन करने के बजाय पैरा-जाइलिन का उत्पदन करना शुरू कर दिया जिससे आर्थो-जाइलिन की आपूर्ति सीमित हो गई। इस कारण आर्थो-जाइलिन की कीमतें बढ़ गईं। आर्थो-जाइलिन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में फरवरी, 2011 से अप्रैल, 2011 के दौरान तीव्र बढ़ोत्तरी हुई और तत्पश्चात् भी बढ़ती रहीं जबकि उस दौरान थैलिक एनहाइड्राइड की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं आया बल्कि मई, 2011 के बाद इसकी कीमतों में कच्चे माल की लागत में बढ़ोत्तरी होने के बावजूद, गिरावट आई और बढ़ती हुई कीमतों का यह अन्तराल अभी हाल की अवधि तक जारी रहा। इन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग द्वारा भारी वित्तीय क्षति उठानी पड़ी क्योंकि उन्हें कच्चे माल की लागत भी नहीं मिल पाई। यह अधोलिखित ग्राफ से स्पष्ट है।



यह भी पाया गया कि थैलिक एनहाइड्राइड की आयात कीमतें/लैण्डेड कीमते घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से काफी कम हैं(गोपनीय) जो नीचे की तालिका से स्पष्ट है:

थैलिक एनहाइड्राइड और आकजीलीन की घरेलू कीमत - रूपये प्रतिकिंगा(सूचीबद्ध)		आयात कीमत रूपये प्रतिकिंगा.	लैण्डेड कीमत रूपये प्रतिकिंगा.	
	थैलिक एनहाइड्राइड	आ-क्सीलीन	थैलिक एनहाइड्राइड	
2010-11 प्रथम तिमाही	100	100	50.24	54.55
2010-11 दूसरी तिमाही	85	87	49.18	53.40
2010-11 तीसरी तिमाही	94	97	50.86	55.22
2010-11 चौथी तिमाही	104	113	58.20	63.19
2011-12 प्रथम तिमाही	111	121	59.72	64.84
2011-12 दूसरी तिमाही	110	128	61.41	66.63

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि थैलिक एनहाइड्राइड की आयात कीमतें/लैंडिंग कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम हैं (गोपनीय)। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को थैलिक एनहाइड्राइड की घरेलू कीमतों में मजबूरन इस कारण से कमी करनी पड़ी कि मुख्य कच्चे माल आर्थो-जाइलिन की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही थीं जिससे थैलिक एनहाइड्राइड की बिक्री कीमत में कमी करने से घरेलू उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ता। परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादकों का क्षमता उपयोग जो वर्ष 2010-11 की दूसरी तिमाही के दौरान 87% था वर्ष 2011-12 की दूसरी तिमाही में घटकर 76% रह गया। क्योंकि उत्पाद में लाभ का मार्जिन कम होने के कारण थैलिक एनहाइड्राइड का उत्पादन अर्थक्षम नहीं रहा। उत्पादन में घाटा और बढ़ती हुई इन्वेंटरी ने क्षति को और बढ़ा दिया।

viii) क्षति के अन्य तथ्य

इस संबंध में निम्नलिखित तथ्य संगत हैं:-

1. **उत्पाद की मांग में संभव गिरावट:** भारत में थैलिक एनहाइड्राइड की मांग में कोई संकुचन नहीं है। मांग में संभव कमी के कारण घरेलू उद्योग को कोई भौतिक क्षति नहीं हुई। इस उत्पाद की भारत में मांग में वर्षों से वृद्धि हुई है।
2. **खपत की पद्धति में परिवर्तन:** विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। खपत की पद्धति में परिवर्तनों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई।
3. **व्यापार प्रतिबंधक प्रक्रियाएं और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा:** कोई ऐसी व्यापार प्रतिबंधक प्रक्रिया नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।
4. **निर्यात निष्पादन:** याचिकाकर्ताओं ने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। वास्तव में, एक याचिकाकर्ता कंपनी अर्थात् मैसर्स आईजी पेट्रोकेमिकल्स जो निर्यातोन्मुख कंपनी थी, अब मौजूदा क्षति अवधि के अन्तर्गत परिवर्तित होकर डीटीए यूनिट बन गई है। निर्यात की मात्रा में भी कमी आई है। तथापि, घरेलू उद्योग को दावाकृत क्षति घरेलू प्रचालनों के कारण हुई। याचिकाकर्ताओं ने घरेलू प्रचालनों की लागत और क्षति के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई है। घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए निर्यातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
5. **तकनीकी विकास:** उत्पाद के उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए तकनीकी विकास क्षति का कोई निर्धारक तथ्य नहीं है।
6. **जनहित:** घरेलू उद्योग के संघटकों पर उत्पादन बंद करने के लिए पहले से ही दबाव डाला गया। कानून में रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए संयत्र बंद होने की कोई शर्त नहीं है। आयातों की लैंडिंग कीमत (क) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और (ख) घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम

है। आयातों से घरेलू कीमतों में अत्यधिक कमी हो रही है। कीमतों में कटौती से मूल्य ह्रास हो रहा है। यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत बिक्री लागत से काफी कम है। बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों बिक्री लागत से बहुत अधिक कम करनी पड़ी जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। कभी-कभार तो घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों कच्चे माल के स्तर तक कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लाभ और निवेश लाभ में कमी होने, रक्षोपाय शुल्क आरोपित न किए जाने के कारण घरेलू उद्योग के पास अपना कारोबार बंद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया।

रक्षोपाय शुल्क लगाना जनहित में होगा क्योंकि इससे न केवल घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति कम होगी बल्कि घरेलू उद्योग में होने वाली और अधिक गिरावट को भी रोकने में सहायता मिलेगी। जहां तक रक्षोपाय शुल्क का उपभोक्ताओं/प्रयोगकर्ताओं पर प्रभाव का संबंध है, यह पाया गया कि थैलिक एनहाइड्राइड के प्राथमिकतः तीन सेगमेंट उपयोग करते हैं

प्लास्टिसाइजर्स के उत्पादन में – लगभग 60 से 70%।

पेट में – लगभग 20 से 30%।

पिग्मेंट्स में – 5 से 10%।

अभी हाल ही की अवधि में डीओपी में महत्वपूर्ण वृद्धि होने के कारण डोओपी सेगमेंट थैलिक एनहाइड्राइड की मांग में कमी आई है। डीओपी की मांग में गिरावट से अभी हाल ही की अवधि में थैलिक एनहाइड्राइड की मांग में समग्र गिरावट आई है। मांग में गिरावट के बावजूद थैलिक एनहाइड्राइड के आयातों में काफी वृद्धि हुई है।

घरेलू उद्योग ने अनुप्रवाही उत्पादों पर 10% रक्षोपाय शुल्क के प्रभाव की गणना की है। यह पाया गया कि रक्षोपाय शुल्क में 10% वृद्धि को यदि पूरी तरह से संभावित अंतिम उत्पाद (यह कल्पना करते हुए कि घरेलू उद्योग कीमतों में 10% की वृद्धि करेगा) पर लगाया जाए तो वह निम्नवत होगा:

पाइप्स 1.2%

पिग्मेंट्स 0.33% और पेट्स पर 0.46%

घरेलू उद्योग के उपर्युक्त दावे का मौखिक सुनवाई के समय उपस्थित उपभोक्ता एसोसिएशनों ने कोई विरोध नहीं किया। ना ही किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किसी फाइल में इसके विपरीत कोई अन्य दावा नहीं किया गया। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि यदि कीमतों में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो भी घरेलू उद्योग पर उसका प्रभाव विपरीत नहीं पड़ेगा। इस आरोपण से संभाव्य अंतिम उत्पादों की कीमतों में अधिक वृद्धि नहीं होगी।

इसलिए रक्षोपाय शुल्क लगाना जनहित में होगा और इससे विशेषकर अंतिम उपभोक्ता के हित अच्छी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे।

ट. समायोजन योजना: यह याचिका केवल एक वर्ष के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए है। इसलिए इन नियमों के अन्तर्गत आयात प्रतिस्पर्धा के लिए सकारात्मक समायोजन के लिए किए गए प्रयासों और किए जाने वाले प्रयासों या दोनों के विवरण का उद्योग की सुविधा के लिए सकारात्मक समायोजनयुक्त पर्याप्त क्रमिक उदारीकरण के द्वारे के साथ समायोजन करना अनिवार्य नहीं है।

ठ. संवर्धित आयात और गंभीर क्षति या गंभीर की स्थिति के बीच आकस्मिक संपर्क: यह उत्पाद आयात के साथ प्रतिस्पर्धा/तुलना में भारी मात्रा में बेचा जाता है। आयातों की लैंडिंग कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना में काफी कम है। घरेलू उद्योग बिक्री के अवसर खो रहा है। परिणामस्वरूप न्यूनतम कीमत के आयातों की सतत उपस्थिति के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ, निवेश पर लाभ और नकद प्रवाह में कमी आ रही है। विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम कीमत और चीन के बाजारों में आयात बंद होने के कारण आयात, घरेलू उद्योग द्वारा न्यूनतम कीमतें प्रस्तुत किए जाने के बावजूद बढ़ रहे हैं। कई बार घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कच्चे माल स्तर तक कम करने के लिए मजबूर किया गया। संवर्धित आयातों के कारण बाजार में आयातों का हिस्सा बढ़ा और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी आई। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आई गिरावट के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन एवं क्षमता उपयोग पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को क्षति संवर्धित आयातों के कारण ही हुई।

ड. विकासशील राष्ट्र: विकासशील राष्ट्रों से आयातों के प्रतिशत की भी जांच की गई। पाकिस्तान, चीन और थाइलैंड को छोड़कर जिनका वर्ष 2010-11 और 2011-12 (पहली तिमाही और दूसरी तिमाही) के दौरान भारत को होने वाले कुल आयातों का क्रमशः 3.34%, 3.43% और 11.83% हिस्सा था, इसके अलावा अन्य विकासशील राष्ट्रों से भारत को होने वाले कुल आयातों का हिस्सा क्रमशः 3% और 9% से कम रहा। इसलिए पाकिस्तान, चीन और थाइलैंड को छोड़कर अन्य विकासशील राष्ट्रों में उत्पादित विचाराधीन उत्पाद के आयात पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के परन्तुक में दी गई शर्तों के अनुसार रक्षोपाय शुल्क लगाना उपयुक्त नहीं है। एक हितबद्ध पक्षकार अर्थात् इंडियन प्लास्टीसाइजर्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अपने परामर्शदाता मैं ० ईएलपी एडवेकेट्स के जरिए यह जानना चाहा है कि विकाशील देशों से आयातों की गणना किस तरह की गई। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि थैलिक एनहाइड्राइड का पाकिस्तान, चीन और थाइलैंड के अलावा अन्य विकासशील राष्ट्रों से आयात का

हिस्सा भारत को वर्ष 2010-11 और 2011-12(पहली तिमाही और दूसरी तिमाही) के दौरान होने वाले कुल आयात का 4.63% है(स्रोत: डीजीसीआईएस आयात आंकड़े और आईबीआईएस आंकड़े)।

12. हितबद्ध पक्षकारों के विचारों पर टिप्पणियाँ

हितबद्ध पक्षकारों ने इस मामले की सार्वजनिक सुनवाई के बाद अपने लिखित आत्म-निवेदनों में जो आशंकाएं जताई हैं उनका पक्षकारबार संक्षेप में विवरण निम्नलिखित है:

क. गाडिव पैट्रोकैमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

i. इस आरोप के संबंध में कि आयात की मात्रा में स्पष्ट वृद्धि का रुझान नहीं है बल्कि इसमें घट-बढ़ की मिश्रित प्रवृत्ति रही है, यह स्पष्ट किया जाता है कि आयातों में स्पष्ट वृद्धि प्रदर्शित हुई है। आयातों का विश्लेषण करते समय महानिदेशक को यह मूल्यांकन करना होता है कि आयातों में कोई परिवर्तन अस्थायी प्रवृत्ति का है या यह परिवर्तन दीर्घ अवधि का है। अर्जन्टीना फुटवियर (ईसी) मामले में, जिसमें पैनल ने अपने निष्कर्ष में इस संबंध में यह विचार किया कि क्या आयातों की प्रवृत्ति का हस्तक्षेपकारी विश्लेषण अनिवार्य था:

“यह प्रश्न कि क्या आयातों में गिरावट ‘अस्थायी’ है, यह आकलन करने के लिए संगत है कि क्या अनुच्छेद 2.1 में अपेक्षित ‘संवर्धित आयातों’ को पूरा किया गया है। इस संबंध में अनुच्छेद 4.2(क) यह अपेक्षा करता है कि आयातों की दर और वृद्धि की राशि का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। (39) हमारे विचार से इससे यह अपेक्षा होती है कि जांच की अवधि के दौरान हुए आयातों की हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। हम नोट करते हैं कि शब्द ‘दर’ में गति और दिशा दोनों ही आ जाते हैं और इस प्रकार हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तियों (वृद्धि या गिरावट) पर पूर्णतया विचार किया जाना चाहिए। जहां ये प्रवृत्तियां संपूर्ण जांच अवधि में मिली-जुली हैं वहां यह निर्धारित करने के लिए वे निर्णायक होती हैं कि क्या अनुच्छेद 2.1 के आशय के अन्तर्गत आयातों में वृद्धि हुई है। व्यावहारिक रूप में, हमारा विचार है कि आयातों में ऐसी मिली-जुली प्रवृत्तियों के महत्व का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका यह मूल्यांकन करना है कि क्या आयातों में गिरावट अस्थायी है या यह दीर्घ अवधि का परिवर्तन प्रदर्शित करती है।

इस मामले में आयातों में वर्ष 2010 में न केवल महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है बल्कि अभी हाल ही की अवधि में वृद्धि जारी रही।

ii. आयातों की प्रवृत्तियों घरेलू खपत के बजाय घरेलू उत्पादन के संबंध में विश्लेषण करने के बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि आयातों की प्रवृत्तियों का परीक्षण घरेलू उत्पादन और खपत दोनों के संबंध में किया गया। इसके अतिरिक्त, कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत केवल

घरेलू उत्पादन के संबंध में ही आयातों का विश्लेषण करना अपेक्षित होता है। संगत प्रावधान निम्नलिखित हैं:

सीमाशुल्क (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं आकलन) नियमावली, 1997 का नियम 2(ग) – “संवर्धित मात्रा” में आयातों में वृद्धि शामिल होती है चाहे वह समग्र रूप में हो या घरेलू उत्पादन के संगत हो।

इस संबंध में कि इजरायल से आयातों में वृद्धि नहीं हुई है, यह स्पष्ट किया जाता है कि रक्षोपाय जांच में अलग-अलग देशों से आयातों की प्रणाली संगत नहीं है।

iii. घरेलू उद्योग की बिक्री में प्रगति की प्रवृत्ति के आरोप के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री चौथी तिमाही तक बढ़ी परन्तु हाल की अवधि के दौरान इसमें कमी आई। वृद्धि का कारण मांग में बढ़ोत्तरी थी जबकि उत्तरवर्ती अवधि में बिक्री की मात्रा में गिरावट का कारण आयातों में वृद्धि है। घरेलू उद्योग की बिक्री में एक निश्चित अवधि तक बढ़ोत्तरी होने के पश्चात इतनी तेजी से गिरावट आने का आयातों में वृद्धि के अलावा अन्य कोई कारण नहीं हो सकता है।

iv. जब कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो तो उत्पाद की बिक्री कीमत में भी अनुपातिक रूप से वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में घरेलू उद्योग कच्चे माल आर्थोजाइलिन की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद भी अपनी कीमतों में वृद्धि करने में अक्षम रहे क्योंकि सस्ते आयात मौजूद थे। विचाराधीन उत्पाद की मांग होने के बावजूद घरेलू बिक्री में गिरावट आई। घरेलू उद्योग को इस उत्पद के निचले स्तर के प्रयोगकर्ताओं की रुचि में आए परिवर्तन के कारण मांग में गिरावट की समस्या का सामना करना पड़ा क्योंकि अब वे थैलिक एनहाइड्राइड के बजाय डीओपी का आयात करने लगे थे। तथापि, सीमित बाजार को आयातों द्वारा अनुपातिक ढंग से न्यूनतम कीमतें प्रस्तुत करके कब्जा लिया गया, इससे भारतीय बाजार में उनका आधिपत्य हो गया और घरेलू उद्योग को क्षति हुई।

v. जहां तक घरेलू उद्योग की लाभदायिकता का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि आयातों की लैंडेड कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और यहां तक कि घरेलू उद्योग के उत्पादन लागत से भी कम हैं। आयातों से घरेलू कीमतों में सतत कमी हो रही है। बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों में बिक्री लागत से बहुत अधिक न्यूनतर करनी पड़ीं जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। कभी-कभार तो घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कच्चे माल के स्तर तक कम करनी पड़ी। इससे निकट भविष्य में उनके बंद होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा यदि कोई निवारात्मक उपाय नहीं किया जाता है।

vi. संबंधित आयातों और उससे हुई क्षति के विश्लेषण को अप्रैल-मई, 2011 के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं किया गया [यूएस – लाइनपाइप केसा]। यह कि रक्षोपाय संबंधी करार में इस तथ्य की कोई अपेक्षा नहीं है कि रक्षोपाय जांच में जांच की अवधि कितनी लंबी होनी चाहिए और ना ही इस तथ्य का उल्लेख है कि विश्लेषणों के उद्देश्य के लिए अवधि को कितना कम किया जाना चाहिए।

vii. जहां तक मांग में गिरावट और क्षति का संबंध है (i) घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति मांग में गिरावट की तुलना में अधिक है (ii) घरेलू उद्योग मांग में गिरावट की समस्या का सामना पहले से ही कर रहा है और फिर आयातों में वृद्धि ने पहले से हो रही क्षति को और अधिक बढ़ा दिया। मांग में गिरावट का घरेलू उद्योग और आयातों दोनों पर समान प्रभाव पड़ना चाहिए। तथापि, यह पाया गया कि जब घरेलू उद्योग मांग में गिरावट की समस्या का ज्वलंत रूप से सामना कर रहा था तो आयातों में वृद्धि हो रही थी। यह स्वाभाविक है कि यदि प्रमुख कंपनियों में से कोई कंपनी डीटीए से ईओयू को अंतरित होती है तो घरेलू बिक्री में वृद्धि होगी।

viii. इसके अतिरिक्त, आयातों की लैंडिंग कीमत (क) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और (ख) घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से काफी कम है। आयातों से घरेलू कीमतों में बहुत अधिक कमी हो रही है। कीमतों में कमी होने के परिणामस्वरूप कीमत ह्रास और पतन हुआ।

ix. कुल आयातों में इजरायल का हिस्सा 13% है जो बहुत अधिक है। यह एक सामान्य रक्षोपाय है कि किसी एक देश के हिस्से का कुल खपत में हिस्सा कुल क्षति विश्लेषण के लिए असंगत होता है। इस संबंध में सामान्य रक्षोपाय नियमों के नियम 13 के प्रावधान लागू होते हैं।

x. व्यापार की यह एक सामान्य परम्परा होती है कि जब कच्चे माल की कीमतें बढ़ती हैं तो उत्पाद की बिक्री कीमत भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। परन्तु इस मामले में याचिकाकर्ता आर्थोजाइलिन की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद भी अपनी कीमतों में भारी आयातों की मौजूदगी के कारण वृद्धि करने में अक्षम रहे।

xi. यह तर्क निराधार है कि अप्रत्याशित विकास गाट के अंतर्गत भारत द्वारा सन्निहित वचनबद्धताओं के रूप में ही हो सकता है।

ख. इंजिरायल की सरकार

i) इस आरोप के संबंध में कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 80% से अधिक है, यह उल्लेख किया जाता है कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम हुआ और उत्पाद, उत्पादन प्रक्रिया और बाजार की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए बाजार हिस्से में हुई गिरावट से महत्वपूर्ण क्षति हो सकती है। घरेलू उद्योग इन्वेंट्रीज को लंबे समय तक नहीं रोक सकते और न ही वे अपने उत्पादन में कभी-कभार कमी कर सकते हैं। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के समक्ष न्यून कीमतों के आयात का मुकाबला करने के लिए कीमतों में कमी करना ही एक साधन रहा। मार्जिन के न्यूनतम स्तर, जिस पर घरेलू उद्योग कार्य करता है, यदि कीमतों में कटौती होती है तो, उससे भारी क्षति होने की संभावना बन जाती है।

ii) यह स्पष्ट करना भी संगत है कि इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं है कि घरेलू उद्योग को वैशिक मंदी के कारण घाटा हुआ। इस तरह यह दावा एक आम कथन प्रतीत होता है जिसके समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है।

iii) जहां तक समायोजन प्लान का संबंध है, यह पाया गया कि न तो डब्ल्यूटीओ करार में और न ही भारतीय विधि में समायोजन प्लान का अधिदेश है। कोरिया डेयरी मामले का उदाहरण दिया गया जिसमें पैनल ने इस विचार को नामंजूर कर दिया कि अनुच्छेद 5.1 समायोजन प्लान पर विचार करने की बाध्यता आरोपित करता है। संगत सार निम्नलिखित है:

“हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अनुच्छेद 5.1 में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है जिसमें प्राथिकारियों द्वारा समायोजन प्लान पर विचार करना अपेक्षित हो।..... पैनल ने ऐसी कोई विशिष्ट अपेक्षाएं नहीं पाई जिस कारण रक्षोपाय करार के पाठ पर विचार करने का अनुरोध किया जाए। हालांकि इसके दो प्रावधानों में उद्योग समायोजन के संदर्भ हैं फिर भी रक्षोपाय करार के पाठ में ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि कोई उपाय करने से पहले विशिष्ट समायोजन प्लान पर विचार किया जाना चाहिए। हम विश्वास करते हैं कि समायोजन का प्रश्न, गंभीर क्षति का निवारण करने या उसका उपचार करने के साथ प्राथिकारियों द्वारा तर्कयुक्त दिए गए स्पष्टीकरण के उपाय के रूप में इसे लागू करना चाहिए। फिर भी हम नोट करते हैं कि रक्षोपाय के अनुप्रयोग के संदर्भ के अंतर्गत समायोजन योजना की जांच करना एक सशक्त साक्ष्य होगा कि प्राथिकारियों ने इस पर विचार किया कि यह उपाय गंभीर क्षति को कम करने या उसका उपचार करने और समायोजन को सुलभ बनाने के उद्देश्य से किया गया।”

ग. कोरिया गणराज्यः

i) घरेलू उत्पादकों के बीच संवर्धित प्रतिस्पर्धा कंथित क्षति का कारण नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग संपूर्ण अवधि के दौरान प्रतिस्पर्धा करते रहे और इसलिए मौजूदा अवधि में गिरावट आंतरिक प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं आ सकती। इसके अतिरिक्त, आयातों की लैंडेड कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थीं। आयात न्यूनतम कीमत वाले उत्पाद होने के कारण आयातों का ही घरेलू उद्योग की बिक्री पर विपरीत प्रभाव पड़ा। वस्तु उत्पाद का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यूनतम कीमत का स्रोत उत्पादकों को अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर करता है।

ii) यह तर्क वस्तुतः गलत है कि घरेलू उद्योग का उत्पादन इसकी क्षमता के अनुपात में ज्यादा बढ़ा। घरेलू उद्योग की क्षमता जनवरी-दिसंबर, 2010 से वही बढ़ी रही जबकि जनवरी, 2011 से मार्च, 2011 और तत्पश्चात् वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही में घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई।

iii) इस तर्क के संबंध में कि भारत में उपरिक्षमता उद्योग को क्षति पहुंचा रही है, यह उल्लेख किया जाता है कि कुछ विरोधकर्ता पक्षकारों ने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग की क्षमता पर्याप्त नहीं है और कुछ हितबद्ध पक्षकारों का तर्क था कि घरेलू उद्योग की क्षमता अधिक है। वास्तव में घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। भारत में पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद घरेलू उद्योग भारतीय बाजारों में उत्पादन या बिक्री करने में सक्षम नहीं है क्योंकि सस्ते आयात उपलब्ध हैं। इससे घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी आई है और आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ऐसी अत्यधिक क्षमता से अवरुद्ध नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो से।

घ. ताइवान की सरकार

(i) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा बढ़ा है और थैलिक एनहाइड्राइड की मांग क्षमता से अधिक है, यह कहा जा सकता है कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा रक्षोपाय शुल्क लगाने के कारण वर्ष 2009-10 में बढ़ा था। दिसंबर, 2009 में रक्षोपाय शुल्क लगाने की अवधि समाप्त होने पर आयातों में महत्वपूर्ण गिरावट आई। तथापि, रक्षोपाय शुल्क आरोपण की अवधि समाप्त होने पर भारतीय बाजार में आयातों ने अत्यधिक तीव्र गति से प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की भारत में पर्याप्त क्षमता है जो भारत में होने वाली मांग को पूरा करने में सक्षम है।

ड. भारतीय पैट एसोसिएशन

(i) इस तर्क के संबंध में कि वर्ष 2010-11 में आयात के आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है, यह स्पष्ट किया जाता है कि महानिदेशक रक्षोपाय ने डीजीसीआईएस द्वारा इस वर्ष के अधिकांश भाग के लिए उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर विश्वास किया है न कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान कराए गए अंतिम तिमाही के आंकड़ों पर। तथापि, आयातों में वृद्धि की स्पष्ट प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है चाहे किसी भी स्रोत पर विचार किया जाए। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक निष्कर्षों में जिन आंकड़ों पर विचार किया गया था उनमें उच्च स्तर की बढ़ोतरी प्रदर्शित हुई है जैसाकि घरेलू उद्योग ने स्थापित किया है। आंकड़ों में इस तरह की विभिन्नताओं द्वारा कोई पूर्वावधारणा नहीं बनाई गई।

(ii) इस आरोप के संबंध में कि वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2010-11 में उत्पादन में वृद्धि हुई है, यह स्पष्ट किया जाता है कि जांच की अवधि मई, 2011 तक है और इसलिए जांचावधि की समाप्ति तक के किसी भी समय पर व्याप्त किसी भी प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जा सकता है। घरेलू उद्योग के उत्पादन में, प्रारंभिक निष्कर्षों में यथातल्लिखित, वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष (2011-12) की पहली तिमाही, अप्रैल-मई में गिरावट आई है।

(iii) जहां तक इस आरोप का संबंध है कि क्षमता उपयोग में काफी गिरावट आई क्योंकि आवेदकों का औसत बाजार हिस्सा वर्ष 2009-10 में 85% था जो कम होकर वर्ष 2010-11 में 74% हो गया है, जो प्रारंभिक निष्कर्ष के पेज 5 पर उपलब्ध कराए गए बाजार हिस्से के आंकड़ों से भिन्न है, यह स्पष्ट किया जाता है कि घरेलू बाजार में आयातों का हिस्सा जो वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही में 11% था वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही (अप्रैल-मई) में बढ़कर 20% हो गया। घरेलू उत्पादकों का घरेलू खपत में बाजार हिस्सा काफी कम हुआ। आवेदकों का वर्ष 2009-10 में औसत बाजार हिस्सा 85% था जो वर्ष 2010-11 में घटकर 74% हो गया अर्थात् इसमें लगभग 11% की गिरावट आई। प्रारंभिक निष्कर्ष के पृष्ठ 5 पर उल्लिखित आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए तर्क हैं जोकि विभिन्न पैरामीटरों के विश्लेषण हैं।

च. मैसर्स कैएलजे प्लास्टीसाइजर्स

(i) इस तर्क के संबंध में कि उत्पादकों ने अवास्तविक कीमतें प्रस्तुत कीं जो अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से काफी अधिक हैं जिसके कारण स्थानीय उपभोक्ताओं को सामग्री का आयात करना पड़ा, यह स्पष्ट किया जाता है कि घरेलू कीमतों की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें कम होने के कारण आयातों में बढ़ोतरी हुई और घरेलू उद्योग ने संरक्षण का अनुरोध किया। घरेलू उद्योग को भारी क्षति हो रही है और वे वर्तमान कीमतों पर भी अपनी कीमतों की क्षति की भरपाई करने में अक्षम हैं। इससे न्यूनतम कीमतों के आयात का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। अगर

घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में और अधिक कमी करता तो घरेलू उद्योग को और वित्तीय घटा सहन करना पड़ता।

(ii) इस आरोप के संबंध में कि अधिकांश आयात शुल्क मुक्त हैं और शुल्क मुक्त आयातों की भारी मांग है और उन्हें आयात आंकड़ों से अलग कर दिया जाना चाहिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि घरेलू उद्योग भी शुल्क मुक्त आयात कर रहा है। यह सिद्ध नहीं होता है कि सभी आयात शुल्क मुक्त थे। यदि ऐसा मामला रहा हो तो इसकी मात्रा में रक्षोपाय शुल्क लगाने के बाद कमी नहीं आनी चाहिए थी। यूंकि शुल्क मुक्त आयातों को रक्षोपाय शुल्क से छूट प्राप्त थी, इसलिए रक्षोपाय शुल्क लगाने के पश्चात् आयातों की मात्रा में कमी नहीं आनी चाहिए थी। स्पष्टतः कुछ अन्य कारण हैं और सभी आयात शुल्क मुक्त नहीं हैं।

(iii) यह आरोप कि महानिदेशक रक्षोपाय ने शुल्ककेरल विकासशील राष्ट्रों पर ही लगाया है डब्ल्यूटीओ करार के विपरीत है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस संबंध में कानून के प्रावधानों का पूर्णतया अनुपालन किया गया और विकासशील राष्ट्रों पर शुल्क सही ही लगाया गया।

छ. इंडियन प्लास्टीसाइजर्स ऐन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन

(i) इस आरोप के संबंध में कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की सही स्थिति का चित्रण नहीं कर रहे हैं और कुछ उत्पादकों को शामिल करके और कुछ को अपनी सुविधानुसार हटाकर क्षति का अनुचित लाभ लेना चाहते हैं, यह उल्लेख किया जाता है कि एसआई ग्रुप जिसे इस रक्षोपाय जांच में शामिल नहीं किया गया है, का कुल घरेलू उत्पादन केरल 4% है और उक्त घरेलू उत्पादक को शामिल करने अथवा शामिल न करने से घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति में कोई परिवर्तन बही आता।

(ii) इस तर्क के संबंध में कि आयात की कीमतों में वृद्धि थैलिक एनहाइड्राइड की घरेलू कीमतों में वृद्धि से ज्यादा है, यह स्पष्ट किया जाता है कि आयात कीमतों में वृद्धि घरेलू उद्योग की कीमतों में वृद्धि से कम है। बिक्री लागत में वृद्धि आयात कीमतों में वृद्धि से अधिक होने से यह स्पष्ट होता है कि आयात कीमतें घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में उस अनुपात में बिक्री लागत में वृद्धि के अनुपात से बढ़ोतरी करने से घरेलू उद्योग को रोक रहीं थीं।

(iii) इस आरोप के संबंध में कि जांचावधि के पश्चात् आयातों में कमी अई है, यह स्पष्ट किया जाता है कि आयातों में गिरावट रक्षोपाय जांच शुरू किए जाने और घरेलू उद्योग द्वारा कीमतों में और अधिक कमी किए जाने का स्पष्ट परिणाम है। सक्षम प्राधिकारी जांच प्रारंभ होने के पश्चात्, के आंकड़ों को शामिल करने के लिए वाध्य नहीं है। जांच शुरू होने के पश्चात्

के आकड़ों को हर हाल में जाँच द्वारा प्रभावित होना चाहिए और वे बाजार की सही स्थिति प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं।

13. अनंतिम उपाय: प्रारंभिक निष्कर्ष में यह पाया गया था कि थैलिक एनहाइड्राइड के संवर्धित आयातों से थैलिक एनहाइड्राइड के घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति हुई और गम्भीर क्षति की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह भी पाया गया कि नाजुक परिस्थितियाँ मौजूद थी, जहां रक्षोपाय साधन का प्रयोग करने में जरा सी विलब उपयोग को अपूरणीय क्षति कर सकती थी। वर्ष 2010-11 के दौरान और वर्ष 2011-12 की पहली दो तिमाहियों के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा ऊपर के पैराग्राफों में यथाउल्लिखित कई संवेदनशील क्षति पैरामीटरों के रूप में गम्भीर क्षति होने के कारण, यह धारित किया जाता है कि अपूरणीय क्षति की संभावना को कम करने के उद्देश्य से इस मामले में अनंतिम उपाय किए जाने की सस्तुति सही ही की गई थी।

14. निष्कर्ष एवं सिफारिश

(i) उपर्युक्त निष्कर्षों के मद्देनजर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भारत में थैलिक एनहाइड्राइड के संवर्धित आयातों से थैलिक एनहाइड्राइड के घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति हुई है और इससे गम्भीर क्षति होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है और सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 12 में दी गई शर्तों के अनुरूप भारत में थैलिक एनहाइड्राइड के आयातों पर एक वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क आरोपित करना जनहित में होगा। घरेलू उत्पादकों द्वारा थैलिक एनहाइड्राइड की औसत लागत, लगाई गई पूंजी पर तर्क संगत लाभ मिलने की अनुमति देते हुए, पर विवार करते हुए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के 29173500 के अन्तर्गत आने वाले थैलिक एनहाइड्राइड के आयातों पर अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क लगाने की तारीख अर्थात् 17 जनवरी, 2012 से एक वर्ष की अवधि के लिए 10% यथामूल्य दर, जोकि घरेलू उद्योग के हित की रक्षा करने के लिए न्यूनतम अपेक्षित दर है, से रक्षोपाय शुल्क लगाने की एतद्वारा संस्तुति की जाती है।

(ii) चूंकि पाकिस्तान, चीन और थाइलैण्ड को छोड़कर अन्य विकासशील राष्ट्रों से होने वाले आयात व्यक्तिगत रूप में 3% और सामूहिक रूप से 9% से अधिक नहीं हैं, इसलिए पाकिस्तान, चीन और थाइलैण्ड को छोड़कर अन्य विकासशील राष्ट्रों में उत्पादित विचाराधीन उत्पाद के आयात पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख में दिए गए परन्तुक के अनुसार रक्षोपाय शुल्क लगाना अनावश्यक है।

[फा. सं. डी 22011/8/2011/पार्ट सी/221]

इन्द्राणी दत्त मजूमदार, महानिदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2012

Subject : Safeguard investigation concerning imports of Phthalic Anhydride (PAN)-Final Findings.

G.S.R. 263(E).—D-22011/8/2011 dated 29 March, 2012 having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 thereof;

1. Procedure

1 An application was filed under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 [hereinafter referred to as "Safeguard Rules"] by (1) M/s. Thirumalai Chemicals Ltd, Ranipet Tamilnadu, (2) M/s. IG Petrochemicals Ltd Raigad Maharashtra, and (3) M/s. Mysore Petrochemicals Ltd, Raichur Karnataka, seeking imposition of Safeguard Duty on imports of Phthalic Anhydride into India alleging that increased imports of Phthalic Anhydride was causing and/or threatening to cause serious injury to the domestic producers of Phthalic Anhydride in India. The Notice of Initiation of Safeguard investigation concerning imports of Phthalic Anhydride into India was issued on 10th August 2011 and was published in the Gazette of India Extraordinary on the same day. A copy of the Notice was also sent to all known interested parties as under:

Domestic Producers

- a. M/s Thirumalai Chemicals Ltd, Ranipet Tamilnadu
- b. M/s IG Petrochemicals Ltd, Raigad Maharashtra
- c. M/s. Mysore Petrochemicals Ltd, Raichur Karnataka

Importers

- A. Klj Plasticizers Ltd, Klj House, 63 Rama Marg, Najafgarh Road, New Delhi.
- B. Pcl Oil & Solvents Ltd. M-105 2nd Floor, Connaught Place, New Delhi.
- C. Silvassa Plast, Klj House, 63 Rama Marg, Najafgarh Road, New Delhi.
- D. Mechemco Industries, 170/6 Shiv Smruti, 27th Road Sion West, Mumbai, Maharashtra.
- E. Micro Inks Ltd. 512/513, Midas, 5th Floor, Saharplaza Complex, J.B. Nagar, M.V.R.D., Andheri (E), Mumbai, Maharashtra..
- F. Heubach Colour Pvt. Ltd. Plot No 9002-9010, Gidc Estate, Ankleshwar.
- G. Sanman Trade Impex Pvt. Ltd. 1410, Maker Chamber V, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra.
- H. A-One Chem Trade Pvt. Ltd. 302, Shanti House, Nr. Madhushudanhouse, Opp: Navranpura Telephone Exchange, Off C.G. Road, Ahmedabad.

I. Sanjay Chemicals (India) Pvt. Ltd. 507, Matru Chhaya, 378/380, Narshinatha Street, Mumbai, Maharashtra.

J. Mazda Colours Limited, Nkm International, 178, Backbay Reclamation, Maharashtra.

K. Lona Industries Limited, Alta Bhavan, 532 Senapati Bapat Marg, Dadar, Mumbai, Maharashtra.

L. Aarti Industries Limited, Udyog Kshetra, 2nd Floor, Mulund Goregaon Link Road, Mulund (W), Mumbai, Maharashtra.

M. Rachna Plasticizers, Plot No. 116&117, Piparia Indl. Estate, U.T. Of D' & Nh, Silvassa.

N. Phthalo Colours & Chemicals (I) Ltd. Nanavati Mahalya, 18, Homi Mody Street Fort Mumbai, Maharashtra.

O. Ramniklal S. Gosala & Co. National House, 608, B.J. Marg, Jacob Circle, Mumbai, Maharashtra.

P. Petrochem Middle East (India) Pvt Ltd, 201, Business Square, B. Wing, Andheri Kuria Road, Mumbai, Maharashtra.

Q. Amjey Chemicals, 5-A, Old Nagardas Road, 101, Adinath Tower, Andheri (E), Mumbai, Maharashtra.

R. Hazel Mercantile Limited, 181, Ashoka Shopping Centre, 2nd Floor, G.T. Hospital Complex, Mumbai, Maharashtra.

Exporters

A. Aekyung Petrochemical 106-3, Guro-Dong, Guro-Ku, Seoul. South Korea

B. Lg Petrochemical, 23-4, Youido-Dong, Yongdungpo-Gu, Seoul 150-040, South Korea

C. Union Petrochemical (Upc Group), Linyuan Plant: 3, Kung-Yeh 2nd Rd, Lin-Yuan, Kaohsiung Country 832, Taiwan, R.O.C.

D. Oci Company Limited, 50 Sogong-Dong Jung-Gu Seoul 100-718 South Korea.

E. Nan Ya Plastics, No.201, Tung Hwa North Rd. Taipei, Taiwan.

F. Gadiv Petrochemical Industries Ltd. Hahistadrut St, P.O.B 32 Haifa, 31000. Israel

Exporting Nations:

- The Republic of Korea, through their Embassy in New Delhi
- Taiwan, through their Embassy in New Delhi.
- Iran, through their Embassy in New Delhi.

- d. Israel, through their Embassy in New Delhi.
- 2. Questionnaires were also sent, on the same day, to all known domestic producers and importers and exporters and they were asked to submit their response within 30 days.
- 3. Requests to consider them as *interested parties* were received from the following parties and all the requests were accepted:

Domestic Industry:

- i. Indian Chemical Council.

Exporting Nations:

- i. Director of Trade Defense, Indonesia.

Exporters

- i. LG Chem Ltd, Korea

Importers

- i. Indian Plasticizers Manufacturers association.
- ii. Polyester Resin Manufacturers association.
- iii. Indian Paint association.

- 4. Requests for an extension of time to submit their replies were made by the following parties:
 - i. Weiss Porat & Co. on behalf of Gadiv Petrochemicals, Israel (30 days from August 21, 2011).
 - ii. Indian Plasticizers Manufacturers association-4 weeks.
 - iii. Polyester Resin Manufacturers association-4 weeks.
 - iv. Luthra & Luthra on behalf of Indian Paint association-2 weeks till 23 Sep 2011.
 - v. WTC for Aekyung Petrochemical Co Ltd, Korea- till 30 Sep 2011.

5 After taking into account the time limits for completing the investigation within the prescribed period, requests for extension of time to submit reply as per Rule 6(4) of Safeguard Rules were allowed, as prayed for.

6 The information presented by the applicant was verified by onsite visits to the plants of the domestic producers to the extent considered necessary. The non confidential version of verification report is kept in the public file.

7 All the views expressed by the interested parties have been taken into account in making appropriate determination. The non confidential information received or acquired has been kept in the public file.

8 After expeditious conduct of investigation, preliminary findings were issued on 23 September, 2011 recommending imposition of provisional safeguard duty @ 10% ad valorem. The provisional duty was levied @ 10 % with effect from 17 January 2012 for a period of 180 days, vide Notification no 1/2012-Customs(SG) dated 17 January 2012.

9 A public hearing was held on 18th October, 2011, notice for which was sent on 5th October, 2011. All interested parties who participated in the public hearing were requested to file a written submission of the views presented orally in terms of sub rule (6) of rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997. Copy of written submissions filed by one interested party was made available to all the other interested parties. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other interested parties. All the views expressed by the interested parties either in the written submissions or in the rejoinders were examined and have been taken into account in making appropriate determination.

10. All the views expressed by the interested parties and other domestic producers either in the written submissions or in the rejoinders and response to the domestic industry submissions were examined and have been taken into account in making appropriate determination. As there are large number of interested parties who have filed their submissions, their contentions and the issues arising there-from are dealt with at appropriate places without referring to specific name of the interested party for the sake of brevity.

2. Brief history: An investigation was initiated by the DG (safeguards) earlier on the application filed under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 [hereinafter referred to as "Safeguard Rules"] by (1) M/s. Thirumalai Chemicals Ltd, Ranipet Tamilnadu, (2) M/s. IG Petrochemicals Ltd Raigad Maharashtra, (3) M/s. Mysore Petrochemicals Ltd, Raichur Karnataka, and (4) M/s SI Group India Ltd., Navi Mumbai Maharashtra, seeking imposition of Safeguard Duty on imports of Phthalic Anhydride into India alleging that increased imports of Phthalic Anhydride was causing and/or threatening to cause serious injury to the domestic producers of Phthalic Anhydride in India. Having satisfied that the requirements of Rule 5, safeguard investigation against imports of Phthalic Anhydride was initiated vide notice of initiation dated 28th November 2008 published in the Gazette of India, Extraordinary on the same day. After expeditious conduct of investigation preliminary findings were issued on 1st January 2009. Central Government levied provisional safeguard duty at the rate of 25% with effect from 29th January 2009 vide customs notification No.9/2009-Cus dated 29th January 2009 based on the recommendation of DG Safeguard. Director General (Safeguard) issued Final Findings G.S.R. 366(E), dated the 28th May, 2009, recommending definitive Safeguard duty for a period of three years, i.e. from 29-01-2009 to 28-01-2012. The Central Government however imposed definitive Safeguard duty for one year only, @ 25% from 29.01.2009 to 30.06.2009 and @15% from 01.07.2009 to 31.12.2009.

3. Views of Domestic industry

a. There is a previous history of dumping leading to recommendation for the imposition of definite anti dumping duty which was subsequently imposed vide Notification No.148/2000 on import of PAN.

b. Further, on the recommendation of D G safeguards provisional and final safeguard duty was imposed vide notification No.9/2009 and ntn. no. 75/2009 respectively.

- c. D G Anti Dumping has initiated anti dumping investigation vide notification dated 29th April 2011 against dumping of subject goods.
- d. In various past cases D G safeguards have proceeded with the safeguard investigation when a parallel anti Dumping investigation has been initiated or anti Dumping duty has been levied on the said product e.g. NTCF and Caustic Soda.
- e. Reply of European Union to the issues raised by China on dual remedy said that in all the three cases of Safeguards, Anti Dumping and Anti subsidy the requisite conditions for initiation are met.
- f. The recent period chosen by the D G Anti Dumping & D G safeguards are Jan –Dec 2010 & Jan-June 2011 respectively which are different from each other.
- g. They are not seeking dual remedy but only relief against the additional injury caused.
- h. There is no bar in the Indian law with regard to imposition of safeguard at this stage. Rather, the WTO Agreement on Safeguards is considered, whereby the Agreement permits imposition of duty for 180 days before the expiry of two years.
- i. April-May 2011 data does not isolate the analysis of increased imports and injury and the demarcation of the period of investigation is on discretion of the Investigation Authority (US-Line Pipe Case).
- j. The petitioners constitute domestic industry as per Customs Tariff Act'75 as they constitute the major proportion in the total Indian production of PAN as per the table below.

S.No.	Year	Petitioner	Other Indian producers	All Indian producers
1	2007-08	86.05%	13.95%	100%
2	2008-09	89.98%	10.02%	100%
3	2009-10	89.37%	10.63%	100%
4	Jan-Dec 2010	87.24%	12.76%	100%
5	Q 4 (2010-11)	86.49%	13.51%	100%
6	Q 1 (Apr-June2011)	86.23%	13.77%	100%

- k. The production by Asian paints is mainly for the captive consumption and domestic sales forms only a minuscule part of its business.
- l. Chemical Manufacturing Company, a division of Thirumalai Chemicals Ltd. imported a small quantity for PAN(less than 0.1% its production and Sale less than 0.2% of the Indian Import of PAN) for export and not for domestic trade.
- m. The imports do not disentitle a domestic producer from being domestic industry under the safeguards law.
- n. The imports of PAN have increased within the meaning of safeguard rules and the decisions of Argentina footwear case and Wheat Gluten case.

- o. There is a sudden, sharp and significant increase in imports throughout the injury period with a decline in the year 2009-10 due to imposition of safeguards duty in that period.
- p. However, when the effective date of safeguard duty came to an end, the imports are surging at a significant rate.
- q. Also the imports in relation to the production and consumption have increase throughout the period as well as in the recent period.
 - a. Setting up of new plants by Chinese producers
 - b. Sluggish demand in China for product under consideration.
 - c. Slowdown in the end markets of Europe and America
 - d. Anti-dumping investigations against imports from Korea and Taiwan in Pakistan and China.
 - e. Growing demand of the product under consideration in India.
 - f. Due to the above listed factors, the exporters from Korea and Taiwan were compelled to search for the growing market for their product and India being the most viable choice were targeted, leading to increased imports in India.
- r. Increased imports have led to reduction of market share of the domestic industry which has adversely impacted their production and capacity utilization.
- s. The sales of the domestic industry increased till Q 4 but declined during the recent period whereas the imports have surged. Domestic industry is being forced to exports its production despite significant domestic demand on account of continuous increased imports of the product in the country.
- t. As the market share of domestic industry is decreasing vis a vis imports it is facing the problem of accumulated inventories.
- u. In order to sustain in the market, the domestic industry has to reduce its prices far lower than the cost of sales thereby suffering significant losses. At the same time the profitability and consequently cash profits and return on investment have started declining in the most recent period which had actually improved previously after imposition of safeguard duty.
- v. Threat of serious injury is being established by following factors.
 - I. The price difference between domestic and imported product is quite significant;
 - II. The foreign producers are holding significant unutilized capacities. Information contained in this petition is referred to and relied upon. Resultantly, the foreign producers are looking for additional markets to the extent possible;
 - III. The major Chinese market for Phthalic Anhydride has clogged for the export oriented producers of Korea and Taiwan, whereas the Indian market is quite strong.
 - IV. Anti-dumping duty on imports from Korea and Taiwan has been imposed by China and Pakistan in their respective countries for a period of 5 years. This has lead to restriction on imports of Phthalic Anhydride from Korea and Taiwan to

China and Pakistan. Due to such restriction, the producers/ exporters started looking for new markets for their products and India with its growing demand offered a better opportunity for them to export which has lead to increase in imports from such countries and also pose a threat of further increase in imports.

- w. The prices of PAN remained same or at times declined inspite of increase in raw material cost which indicates that the end user has been supplied PAN at competitive prices. Previously also the domestic industry has been maintaining the prices in line with changes on prices of raw material even after imposition of safeguard duty.
- x. Further, safeguard duty will be only to the extent to neutralize the injurious impact.
- y. Since there is negligible impact on the eventual end product and considering that the survival of the domestic industry is must, the imposition of safeguard shall be in public interest.
- z. The petitioners contend that during many safeguard investigations, duty was recommended without elaborate adjustment plan.

4 Views of Exporting Nations

Republic of Korea:

a. There is simultaneous investigation in this case viz Antidumping and Safeguards. Same economic factors from the overlapping period may lead to overlapping remedies resulting in excessive protection.

b. The petition annualized the period of two months (April to May 2011) for the whole year of 2011 which exaggerated the trends of import volume. The two months period is too short to show a trend for the whole year Indian Govt should have updated its import data to include June to August 2011.

c. There is no unforeseen development in this case. Injury in this case was foreseen and predicted when the DI expanded its capacity during the previous safeguarded period, exceeding the domestic demand. The petitioners should have enlarged their focus on export performance during 2009 instead of concentrating more on domestic market with the support of safeguard measures.

d. There is relatively stable capacity utilization. Petitioners not only maintained the utilization level despite increase in capacity, but also made a breakthrough to reach higher utilization level. There is no injury.

e. As per injury statement, the export volume of the petitioners was 75382 MT in 2007-08 which decreased sharply to 15757 MT in 2010. The statistics provided by the petitioners show that the allegation of injury based on the decrease in production and capacity utilization should be attributed to the other factors such as poor export performance and not to the imports of PAN.

f. Capacity expansion is the main cause of injury. Even though, Mysore Petro closed the plant, over 160000 MT of capacity of IG Petrochemical and the other petitioners' capacity in total already satisfy the demand of the entire domestic market without any imports.

This indicates that the injury cause exists already among petitioners who are equipped with overcapacity and who have limited their ability to export by converting themselves to DTA.

g. In the graph on page 16 of the preliminary finding, the authority wanted to explain the recent reversion of orthoxylene costs and phthalic anhydride prices; however, the same curves in the graph provide evidence that a profitable and favourable spread had existed before June 2011. Apparently, the graph shows more profitable period than that at loss.

h. Preliminary Findings fail to provide explanation ensuring that injury caused was due to increase in imports and not due to the effects of other factors.

Govt of Israel

a. The data in the preliminary findings does not seem to demonstrate a significant increase of imports nor a dramatic decrease in domestic production. There was indeed a decrease in sales in Q1 2011 but this was not due to the imports but rather to a general decline in the consumption of the product.

b. The factors mentioned in the preliminary findings concerning "serious injury" caused to the domestic producers seem to be lacking in light of the requirements of the WTO Agreement on Safeguards. Furthermore, the application does not mention any adjustment plan.

c. The preliminary findings do not determine a period of investigation to necessitate and justify a safeguard measure.

d. The application of the safeguard duty affected the market behavior in 2009 and the immediate period following that date and therefore cannot form a basis for the reapplication of a safeguard measure.

e. Israel has been mentioned in the initiation notice as one of the main sources of imports of PAN to India. However, a closer look at the import figures demonstrates that the total import from Israel represents roughly 1.5% of the total consumption in India. Moreover, it is difficult to claim for injuries caused by import in cases where the local Indian producers hold about 80% of the market share.

f. We should note that the imports from Israel have constantly decreased during the last years.

g. One of the major causes for the difficulties encountered by the Indian domestic producers of PAN is the global recession and the decline in demand and not the competing imports. The domestic industry seems to be seeking any possible trade remedy to overcome the worldwide competition by imposing protective measures.

h. Indian PAN industry has recently requested the imposition of an anti-dumping measure and on April 29th 2011 an investigation was initiated. A double remedy for the same "injury" cannot be applied

i. The injury caused by the alleged dumping cannot be separated from the injuries allegedly caused by the increase in the imports. Directorate General of Safeguards has not considered the impact of the alleged dumped imports investigated in the parallel Anti-dumping Investigation.

j. According to Article 7.5 of the Agreement on Safeguards, a temporary as well as a final safeguard duty, shall not be applied again to the import of PAN for a period of two years from December 31, 2009 (date of termination of previous safeguard duty).

k. In light of the circumstances described above we believe that this investigation should be terminated immediately and no duty shall be applied.

5. Views of Exporters

Gadiv Petrochemicals:

- i. Simultaneous anti-dumping and safeguard investigations may not be conducted in this case for the same product with respect to same countries.
- ii. That the Applicants in the Safeguard Application, together with one additional company, have filed an anti- dumping application seeking the imposition of an anti-dumping duty on Phthalic Anhydride.
- iii. In view of admission that "the dumping and the low priced imports" are causing injury by the Applicants , Honorable DGS should suspend the present investigation, as long as the anti-dumping investigation is being conducted.
- iv. Further, the injury caused by the alleged dumping cannot be separated and singled out from the injuries allegedly caused by the increase in the imports.
- v. The Domestic Industry filed a Writ petition seeking a declaration that the safeguard duty imposed on PAN should be made valid for 4 years. However, the Hon'ble High Court refused to grant interim relief.
- vi. Immediately after the filing of this Application the Domestic Industry withdrew the aforementioned Writ Petition. Having approached the Hon'ble High Court for the same relief they should not have filed a fresh application for the same relief which is barred by res- judicata.
- vii. The increase in the import after the expiry of the Safeguard duty on December 31, 2009 proves that the domestic industry did not adjust itself to the import as required by Article 7, section 2 of Agreement on Safeguards.
- viii. The DGS erroneously decided the period of investigation from Q4, 2008- 2009, ignoring the period before the imposition of the previous safeguard measure which was mandated to neutralize any artificial increase attributed to the influence of the safeguard duty imposed during the year 2009.
- ix. The market share of the import (16-i 8%) during the most recent period (2010 + Q 4 2010- 2011) is significantly lower than the market share during 2008- 2009, before the imposition of the safeguard measure which lead to the imposition of the safeguard measure.
- x. WTO Panel in *Argentina - Footwear* case cautions against manipulations of the investigation period in order to achieve the "desired" outcome.
- xi. Moreover, such increase after the expiration of the safeguard measure cannot be regarded as being a result of "unforeseen developments" as required by Article XIX GATT.
- xii. Conduct by the applicants clearly demonstrates that they were aware of the fact that following the expiry of the duty, the imports of PAN were expected to

increase and therefore, the alleged increase in the imports cannot be regarded as "sudden" and "unforeseen".

xiii. In this case the import volumes do not show a clear upward trend. Rather we see many intervening trends of decline in the imports.

xiv. The DGS erroneously based her findings, inter alia, on the trends of the import in relation to the domestic production instead of to the domestic consumption. The decline in the export increased the percentage of the import in relation to the production.

xv. Preliminary findings allegedly show that there has been an increase in imports from Korea and Taiwan from the year 2008-2009 to 2010-2011 but figures relating to the third country implicated in this investigation - namely, Israel are absent. Actually there is a decline in export volumes over the period of investigation.

xvi. The fact that such producer was able to shift from EOU to DTA and to increase its sales in the domestic market, contradicts any conclusion of serious damage due to import.

xvii. DGS ignores the significant increase of 11% during the period 2009-2010 & 2010-11 in the sales of the domestic industry during the period of investigation. Even the domestic sales of the first quarter of 2011-2012 (38,149 MT) are higher by 7% than the corresponding quarter of 2009-2010 (35,530 MT).

xviii. The changes in the domestic production and the capacity utilization presented by the Applicants should be fully related to the ongoing decline in the export of the domestic industry, and not to the import.

xix. The findings in this case, which show growth in sales, increase in production, increase in sales prices, growth in employment and growth in productivity of the Indian PAN industry certainly do not pair with a finding of "significant overall impairment in the position of a domestic industry",

xx. The DGS ignored the fact that the sale prices of the Applicants, increased during the last two years, and especially during the most recent period,(Q 4 2010- 2011, Q 1 2011- 2012).

xxi. The DGS ignored the fact that Gadiv's export prices to the Indian market, as well as the average prices of the whole export of PAN to India, were higher than the domestic prices in South-East Asia (including India), and therefore the import prices did not undercut the prices of the domestic industry.

xxii. The DGS totally ignored the Applicant's financial statements attached to the Application that their financial status in the recent period is good, and they did not suffer any injury that may be related to the alleged growth in import

xxiii. The increase of the production costs (increase in the costs of Ortho-xylene) of the Applicants and its influences on the profitability of the Applicants cannot be related to the import.

xxiv. The decrease of delta during the months May- July 2011, is only a temporary phenomenon, should be related to the increase in the prices of Ortho-xylene and the decline in the domestic prices of PAN due to the decline in the domestic consumption during Apr- May 2011.

xxv. The import did not prevent the domestic producers from increasing their prices

xxvi. The DGS's assumption that the domestic industry might be closed if a Safeguard duty will not be imposed is totally absurd as Applicants are holding 75%- 80% of the domestic market and they have high profits

xxvii. The DGS seems to assume that the previous safeguard measure had duration of 180 days or less and that therefore the time interval of 2 years does not need to be respected. DGS states that the definite safeguard duty was imposed for one year, from 29.1.09 to 31.12.09 which is more than 180 days. Therefore, India cannot impose another safeguard measure on this product before 31.12.11.

xxviii. Safeguard measure is an emergency measure that can be used only in extraordinary circumstances of emergency and not as a reaction to "unfair trade" by any of India's trade partners. Here this emergency measure has already been tried once in 2009, and the current position of the Indian PAN industry clearly does not justify doing so again.

6. Views of Importers/User Industry

Indian Paints Association:

- i. The preliminary findings are against the principle of natural justice. PF were finalized on the basis of submissions made by only three interested parties and five interested parties including us were left out. Exercise of such power by any quasi-judicial body which includes DG Safeguards has to be consistent with principles of natural justice.
- ii. The import data provided by DG safeguards in the PF is at variance with the data furnished by the petitioner in the petition. Further the interested parties/respondents have not been provided with the import data for April-Jun 2011 in Annexure 2 of the petition. Moreover, the imports made under advance license scheme should be excluded from the overall imports.
- iii. As per initiation notification issued by DGAD in the antidumping investigation against import of PAN, two out of the three petitioners have imported PAN from Korea RP during Jan-Dec 10. Therefore, these two companies namely M/s IG Petrochemicals and M/s Thirumalai Petrochemicals, being importer of PAN cannot be part of domestic industry. Further, when the domestic industry is itself importing such goods during POI for consumption in the domestic market, any claim of injury to the domestic Industry cannot be sustained as the injury to domestic industry is self inflicted, they being contributor in imports.
- iv. DG Safeguards has concluded in PF that production has been falling. However, production has increased in 2010-11 as compared to 2007-08.
- v. DG, Safeguards, vide page 13 of the preliminary findings has concluded that capacity utilization has declined significantly as Applicants had an average market share of 85% in 2009-10 which fell to 74% during 2010-11. This conclusion is at variance with its own data on market share as provided on page 5 of the preliminary findings.
- vi. The development in the market of USA and China were foreseeable. DG Safeguards has cited the same unforeseen development as mentioned in the earlier safeguard investigation on PAN. Therefore, in respect of this investigation these developments were no longer unforeseen because these had already occurred three years ago.

- vii. There is no injury to the domestic industry as there is positive surge in all the vital economic parameters viz production, installed capacity, domestic sales, profitability, market expansion etc.
- viii. Market share of domestic industry has increased while the market share of imports is at the same level where it was in 2007-08.
- ix. Domestic Industry is seeking double protection in the form of simultaneous Antidumping and Safeguard Investigations. Import volumes from the subject countries in the Antidumping investigation is similar to the import volumes in the Safeguard Investigation which implies that the same import volumes are being investigated twice for causing two different types of injury to the same DI at the same time.
- x. There is absence of any causal link in the case.

Indian Plasticizers Manufacturers Association (IPMA) and Polyester Resin Manufacturers' Association (PRMA) :

- i. DG Safeguards has erred by not providing Interested Parties the opportunity to comment, thereby violating the principles of natural justice and principles governing investigations. We had requested, vide letter dated 27 Aug 11 to consider us an interested party and sought four week time to submit reply which was granted. However, despite this the PF were issued on 23 Sep 11.
- ii. POI in this case is out dated and not recent. POI in this case begins from Jan 2009 and ends in May 2011. Hence POI comprises of data which is upto 28 months old and does not qualify to be recent. Period of over two years does not justify or establish the essential requirement of a sudden, sharp and significant rise in imports.
- iii. Data provided by the petitioners does not provide an accurate assessment of the injury claimed on account of increase in imports. It is unfair and improper to annualize imports made in specific quarters to analyse the injury and threat of injury and annualizing the imports for merely 2 months leads to a mere conjecture and not sufficient evidence to initiate the case.
- iv. Import and other data like production etc. submitted by the petitioners is highly unreliable and is in fact inconsistent with the data provided with the petition filed in the parallel antidumping petition. In the absence of an adequate and justified explanation, the data be dismissed as unreliable.
- v. Domestic sales of petitioners have consistently increased whereas the market share of imports has in fact declined to 26% in April-May 2011 as compared to 37% in Q1 of 2010-11.
- vi. Capacity utilization does not show a substantial decline and the average capacity utilization has been 77% whereas other factors have affected the production and capacity utilization of the petitioners.

- vii. Production of the petitioners has increased by 8% in Q4 of 11-12 as compared to Q4 08-09 whereas the sales of the petitioners have increased by 23% in corresponding period.
- viii. Perusal of the Balance sheet of M/s IG Petrochemicals and M/s Thirumalai Petrochemicals shows significant profits during financial year 2009-10 & 2010-11. In fact, even in the first quarter of financial year 2011-12, the operating profits of IG Petro are 9.30 crores and in the case of Thirumalai, it is 9.76 crores. M/s Thirumalai have suffered losses only in 2008-09 in the last 10 years due to the global economic meltdown.
- ix. A majority of the imports made by the user-industry are made duty free under advance license scheme, in order to meet their export obligations. Such imports are not to be counted for safeguard purpose.
- x. Domestic industry enjoyed much higher levels of protection earlier, as the customs duty was much higher @ 30%. The same has been reduced to 7.5% currently. Hence, the DI has resorted to seeking undue trade remedial protection.
- xi. The petitioners have not provided any information as to whether the commitments made by them in the form of adjustment plan submitted with the earlier petition on this product, have been complied with/adopted or whether the same factors are causing injury to the petitioners.
- xii. Designated authority is mandated to require the petitioners to submit a detailed adjustment plan in order to impose a safeguard duty and the failure of the same is violative of the obligations under the WTO Agreement on Safeguards.
- xiii. There is absence of critical circumstances in this case. Rise in the import prices is greater than the rise in domestic prices of the subject goods. Clearly, the injury suffered by the petitioners is self-inflicted and the serious injury claimed by the petitioners cannot be attributed to imports.
- xiv. POI under the parallel Anti-dumping investigation is Jan 2010 to Dec 2010 whereas POI for the present safeguard investigation is Q4 08-09 to May 2011. Hence, POI under parallel anti-dumping investigation is subsumed within the POI for the safeguard investigation which is unfair.
- xv. In this case, the injury to the petitioners is clearly attributable to other factors and not to an increase in imports. Hence, causal link does not exist between increased imports and serious injury.
- xvi. Imposition of safeguard duty shall be contrary to public interest in this case. Imposition of safeguard duty would gravely escalate the price of the subject goods and have a direct adverse effect on the costs of the plasticizer manufacturers and other dependant downstream industries. It would make the end user industry completely unviable and would suffer immense injury that may even lead to their closure.

KLJ Plasticizers Ltd. :

- i. The petitioners namely M/s IG Petrochemicals and M/s Thirumalai Petrichemicals Ltd have most modern plants and there is no further improvement in the technology anywhere in the world for which the domestic industries are claiming injury.
- ii. Raw material is available in plenty in the country and it does not require any power to run the plant because of its exothermic reaction. Moreover the DI generate extra steam out of which they produce power not only for their plant but for sale outside also. This is advantageous to them.
- iii. The domestic industry is having sufficient exports and it shows that they are capable of world class competition.
- iv. The domestic industry have always made good profits as per their balance sheet for the last ten years except for the year 2008-09 which was a global meltdown year.
- v. Higher imports are engineered by domestic industry. They have been offering unrealistic prices which are higher than prevailing international prices forcing local consumers to import material so that they can show spurt in imports.
- vi. Most of the imports during this period have been done by duty free licence holders, which should be excluded from the import figures.
- vii. The IG Petrochemical is going for expansion after which they will become single largest plant in the world and Thirumalai Petrochemical is putting up another plant in Gujarat. If there is injury then what is the necessity of these expansions.
- viii. Plasticizer industry, the largest consumer of PAN, is likely to suffer if safeguard duty is imposed on PAN because there is no margin in this industry even in good times. Further, the Plasticizer Industry is to compete with the world class integrated plants which have own oxo-alcohol or Phthalic Anhydride or both. If any safeguard duty is imposed on PAN, it will be boon for the foreign producers because they will find market for plasticizers instead of PAN. This will lead to large scale import of plasticizers and not in the interests of the domestic manufacturers of plasticizers.
- ix. Phthalate Plasticizers industry is also subject to many FTAs which allows import of DOP at the concessional rate of duty from Malaysia, Singapore and Thailand.

7. Rejoinder by Domestic industry**I. Government of Taiwan**

- i. The Imports increased at significant rate capturing the market share of the domestic industry once the period of imposition of safeguard duty expired.
- ii. The domestic industry in India has enough capacity to meet the entire demand in India.

II. Government of Korea

- i. The DGCIS data shows a rising trend of export of PAN from Korea and Taiwan to India in the wake of coagulation of demand in China and Pakistan, an unforeseen development resulting in increase in imports causing serious injury and threat of serious injury to the domestic industry.
- ii. Competition inter se domestic producers is not the cause of injury as the domestic producers have been competing during the entire period and therefore deterioration in the current period could not have been due to internal competition.
- iii. The capacity of the domestic industry remained constant since Jan-Dec 2010 whereas the production of the domestic industry declined in Jan, 11 to March, 11 and thereafter in Q1 of 2011-12.
- iv. Landed price of imports were much lower than selling price of the domestic industry. It was the imports that forced the domestic industry to keep unremunerative prices.

III. Government of Israel

- i. The pattern of import from individual countries is of no relevance in a safeguard case.
- ii. The domestic industry cannot withhold inventories for a long period or reduce the production off and on. It had to respond to low priced imports by reducing the prices thus leading to significant injury.
- iii. While global recession is one of the causes of increased imports, admittedly Indian market is not suffering from recession. Therefore, Indian producers need not suffer due to global recession.
- iv. The imports not only increased at a significant rate in 2010 but also in the next 6 months. The effect of expiry cannot be for such long period.
- v. Neither the WTO Agreement nor Indian law mandates adjustment plan. The petitioners refer and rely on Korea — Dairy case, wherein the panel rejected the view that Article 5.1 imposes an obligation to consider adjustment plans.
- vi. The domestic industry is working on an adjustment plan and the same shall be provided in due course.

IV. Gadiv Petrochemicals Industries Ltd

- i. The Applicants chose to withdraw the Petition before the Hon'ble High Court, and to refrain from requesting the extension of the Safeguard duty. Instead, they submitted a new Application for Safeguard duty in addition to the pending Anti dumping petition.

- ii. While analyzing the imports, the DG is required to evaluate whether any downturn in imports is simply temporary, or instead reflects a longer-term change as per findings in Argentina — Footwear (EC) case.
- iii. Shifting of EOU to DTA has no relevance in the present investigation. Such shifting is a long term process and has not caused injury to the domestic industry.
- iv. The petitioners were unable to increase their prices with the increase in prices of Orthoxylene(raw material) because of the presence of cheap imports.
- v. The financial data in the annual report is the consolidated data of all the products produced by the particular petitioner and not for Phthalic Anhydride alone.
- vi. In most recent period, demand of PAN in DOP segment declined because of significant increase in DOP itself.

V. Indian Paint Association

- i. Out of 168 safeguard initiations reported to WTO during 29.03.1995 and 12.11.2008 in 15 cases provisional safeguard measures have been recommended/ imposed within 30 days of initiation of the safeguard investigation.
- ii. In critical circumstances any delay in imposition of Provisional Safeguard duty may cause irreparable damage. The interim safeguard duty was imposed without receipt of responses in the cases of Phthalic Anhydride, Aluminium FRP & Foil, Dimethoate technical, Soda Ash etc.
- iii. In past, third countries imposed safeguard duty without receipt of information from interested parties.
- iv. In the petition the domestic industry has considered data from IBIS whereas the Director General (Safeguards) in the Preliminary Findings has considered data from DGCI&S and Directorate of Valuation and the entire source shows an increasing trend.
- v. Missing data by the petitioners is mere clerical error and no prejudice has been established on this account.
- vi. The definition of the 'domestic industry' in Anti-Dumping law and Safeguard law is different. When safeguard law provides for the specific definition of "domestic industry", there is no need to borrow the definition from other law.
- vii. The imports in advance license are impacting the domestic industry and therefore cannot be excluded.
- viii. The opposing parties have very conveniently selected a period for comparison as per their requirement. The period of investigation in the present investigation is till May 2011 and therefore any trend has to be analyzed till the end of period of investigation.

- ix. Applicants had an average market share of 85% in 2009-10 which fell to 74% during 2010-11, i.e. a decline of about 11%.
- x. Producers in China are setting up new plants for manufacturing Phthalic Anhydride which has led to increase in supply of the product in China thereby reducing the market opportunity to the third countries foreign producers to export in China.
- xi. Consideration of same factor at the time of previous investigations does not imply that the factor cannot exist now or cannot be relevant now and nothing prevents the authorities in imposing safeguard duty again based on same factor.
- xii. The petitioners have annualized the 3 months figures to facilitate fair comparison with the previous year's imports and other injury parameters which are on annualized basis.
- xiii. Domestic industry never claimed to have 85% of market share. Indian producers as a whole had a market share of 87%, which declined to 77% in recent period.
- xiv. The very purpose of analyzing the longer period data is to examine intervening trends and not just end to end point comparison.
- xv. The opposing party has itself stated the reason for closure of Mysore plant in its submissions at page 10 which is an extract from the annual report.
- xvi. Any change in catalyst would not amount to shut down of the plant for indefinite period rather it was due to accumulation of stocks
- xvii. No back up information or IBIS data has been provided by the opposing party to substantiate the argument. Information presented to the DG clearly show surge in imports.
- xviii. The SI Group which is not included in the safeguard investigation accounts for mere 4% of the total domestic production which would not materially change the overall state of domestic industry.
- xix. While the DG is required to consider most recent data, clearly, the DG is not required to include the data post initiation of investigations.
- xx. The period of investigation is and the applicants are not same therefore the data provided in the two investigations ought to differ. However, data in respect of individual companies does not have any variations.
- xxi. The profits in annual reports are wholly irrelevant. Only profits in the product concerned alone is relevant.
- xxii. Throughout current period, the custom duty was 7.5%. Therefore it is irrelevant and baseless to state that reduction in customs duty has caused injury to the domestic industry.

VI. M/s.KLJ Plasticizers

- i. Inspite of world class plant, easy access to raw materials availability and energy cost, conversion cost being most optimum, the domestic industry is unable to recover its costs.
- ii. It is not established that all the imports were duty free. If all the imports were duty free, its volumes would not have declined after imposition of safeguard duty.
- iii. Non imposition of safeguard duty would jeopardize the expansion plan as it assumes no surge in imports.

8. Rejoinder by EXPORTERS**Gadiv Petrochemical:**

- i. In their current submission, the Applicants fail to mention the important fact that they filed a Writ Petition before the Hon'ble High Court of Bombay.
- ii. The Applicant's silence on the petition and withdrawal of the petition immediately after the filing of the current petition amount to forum shopping and should be considered seriously by DGSG.
- iii. DGSG held in the decisions e.g, Caustic Soda, that the imposition of additional Safeguard duty, after the imposition of a Dumping duty, may be considered only if and when the influences of such Dumping duty on the import and the domestic industry had been clearly tested.
- iv. Period of Safeguard investigation overlaps with Anti-Dumping investigation which is 2007- 2008, 2008- 2009, 2009- 2010, Jan- Dec 2010 (regarding the injury) and Jan- Dec 2010 (regarding the dumping).
- v. The injuries argued in the Safeguard Application and the Dumping Petition, are identical, i.e, price-undercutting, decline in profitability, decline in market- share, deterioration of capacity utilization.
- vi. The periods and injuries analyzed in both investigations are identical, and may lead to the imposition of double duties.
- vii. The WTO's Panels and Appellate Body have held in cases e.g Argentina- Definitive Safeguard Measures on Imports of Preserved Peaches & United States- Definitive Safeguards measures on imports of certain steel products, that to establish increase in imports, a comprehensive analysis throughout several years must be performed, and such analysis should not be limited to the most recent past.
- viii. Even if the import volumes in a specific quarter (or month) are relatively high, it cannot be said that the imports throughout the entire year will necessarily be as high.
- ix. The actual annual volumes of the imports, in relation to the production and the consumption, reflect a decrease of the imports compared with the years before the imposition of the safeguard duty following the previous application of the D1

- x. To dodge submission of Adjustment Plan, the Applicant's argued that they requested safeguard duty only for one year. However, as per their Written Submissions they are demanding a Safeguard duty "for the longest possible period".
- xi. Regardless of the duration of the Safeguard duty period Applicants should have submitted an Adjustment plan according to the decisions in cases of Korea-Definitive Safeguard On Imports Of Certain Dairy Products and Chile-Price Band System and Safeguard Measures Relating to Certain Agriculture Products.
- xii. Adjustment Plan filed by the Applicants with their previous Safeguard Application was found to be totally fictitious. No provisional duty may be imposed as long as such Adjustment Plan is not submitted.
- xiii. The period of investigation according to the Hon'ble DGS's decision is "Q 4 2008- 2009 onwards, and not up to September 2009 as erroneously argued by the Applicants in section 27 to their submissions.
- xiv. The data regarding the domestic sales reflects that the sales in the first quarter of each year are relatively higher than the rest of the quarters and cannot establish a conclusion of decrease in the domestic sales.
- xv. The Applicants admitted that the domestic demand for PAN decreased during Q 1 2011-2012, due to the decrease in the production of the downstream product Dioctyl Phthalate in India and decreased demand caused them injury.
- xvi. Preliminary Findings, reflects a clear trend of decrease in the domestic demand from Q 1 2010- 2011. The domestic consumption in Q 2 2010- 2011 decreased to 59,618 MT (from 63,432 MT in Q1), and then decreased to 57,023 MT during Q 3, and then decreased to 56,210 MT during Q4. The trend of decrease worsened in Q 1 2011-2012 (April- May), as the consumption dropped to 26,646 MT.
- xvii. The Applicants claimed additional injuries such as decrease in profitability, and domestic sales, "in the most recent period"(April- May 2011) i.e exactly the same period of the alleged increase of the prices of Ortho-xylene and the severe decline in the demand
- xviii. The Applicant IGI Petrochemicals Ltd admitted in its Annual Report -2009-2010, states that production during Q 3 2009- 2010, was lower due to "stoppage of one of the plants on account of Catalyst change" and a fire. This decrease, despite the Safeguard measure being in place when imports were lower, proves that there is no connection between the decrease in the domestic production and the imports.
- xix. According to the Appellate Body's decision concerning US-Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel Products from Japan, the injurious effects of the import should be separated and distinguished from all the other factors which affected the local industry.
- xx. In view of the above, the honorable DGS should reject the Application to impose a safeguard measure, or, at least refrain from imposing it on imports from Gadi, should suspend the present investigation and recommend revocation of the Provisional Duty.

9. Rejoinder by IMPORTERS/USER INDUSTRY

Indian Paints Association:

- i. Arguments of DI that there is surplus production worldwide as there is a slowdown in the end markets of Europe and America and demand sluggish in China leading to diversion of their products to India are incorrect as per their financial report for Q1 2011-12.
- ii. The injury period in the Safeguard and the Anti dumping investigation overlap contravening the Safeguard Agreement and Rules as non segregation of injury would result in breaking of the causal link and “double protection”. Neither the DI nor DG Safeguards has provided an explanation ha provided any explanation for that.
- iii. In NTCF & Caustic Soda case cited by DI , POI both investigation period was different enabling the Authority to identify and attribute the injury suffered by DI to “low priced imports” in the anti dumping investigation and “surge” in imports in the Safeguard investigation.
- iv. Moreover, in both the cases cited by DI, either an anti dumping or a Safeguard duty was already in existence when the other investigation was initiated.
- v. DI argued that POI in the current Safeguard investigation is Jan-June 2011. However DG Safeguards vide para (c) of page 11 of the Preliminary findings has concluded that the POI in the present Safeguard investigation is from Jan 2009 onwards.
- vi. In preliminary findings, DG Safeguards concluded that import figure for 2010-11 is 61,965 MT whereas import figure for 2011-12 (annualized) stands at 55,128 MT, a decline of 13%.
- vii. Non availability of import data for June 2011 to the respondents violates the principle of natural justice.
- viii. When Petitioner companies are themselves attributing injury on ‘dumping’ in their annual reports while before DG Safeguards they claim due to “surge in imports”, DG Safeguards may refer it to DGAD.
- ix. The communication between EU and China being relied on by DI and DG Safeguards provide for no bar on a simultaneous initiation of a Safeguard investigation however it does not provide for levy of simultaneous duties without segregation of injury.
- x. As per initiation notification of the anti dumping investigation Thirumalai Chemicals and IG Petrochemicals being importers of Phthalic Anhydride, should not be included in the category of domestic industry in view of the recent judgment by the Hon'ble High Court of Calcutta in the matter of *Century Plyboards (I) Ltd. & Ors. v. The Additional Secretary & Designated Authority & Ors.* which has clearly held that a company who has imported the PUC cannot be part of the domestic industry.

- xi. There has been a 1% increase in imports in relation to consumption in 2010-11 as compared to 2007-08. Given the stable level of imports, it has not displaced sales of the domestic industry in overall demand.
- xii. Market for Phthalic Anhydride in India has expanded as there is an increase of 38% in total demand in 2010-11 as compared to 2007-08 and so is the installed capacity from 2,32,000 MT in 2007-08 to 2,68,000 MT in 2010-11.
- xiii. The overall increase in domestic sales is 50% in 2010-11 as compared to 2007-08 which is more than the demand and the increase in imports for the same period.
- xiv. The domestic sale price has increased from INR 61/Kg in 2007-08 to INR 66/Kg in 2010-11, an increase of 8% in 2010-11 as compared to 2007-08 and thus claim on price suppression or depression cannot be sustained.~
- xv. Petitioner argues that the price of ortho-xylene has increased with no corresponding increase in the price of Phthalic Anhydride leading to injury to the DI while Q1 FY 2012 Financial Results Highlights shows that volatility in raw material prices has had no effect on selling price of DI and that DI is not constrained to export. Further, DI has been able to increase its domestic selling price.
- xvi. Thirumalai Chemicals has suffered huge losses on their operations subsidiary companies based in Malaysia and Singapore as stated into the Annual report of the company and not on account of increase in import of Phthalic Anhydride.
- xvii. Further, the market share of DI has increased from 64% in 2007-08 to 70% in 2010-11.
- xviii. Neither the DI nor DG Safeguards has provided any explanation vis-à-vis discrepancy in import data as highlighted by IPA in its previous submissions.
- xix. In view of the gross violation of PNJ, loopholes in the conduct of the investigation and deficiency in the petition of the domestic industry, the current investigation should be terminated.

10 Indian Plasticizers Manufacturers Association (IPMA) and Polyester Resin Manufacturers' Association (PRMA):

- i. Prior to the present investigation, the domestic industry has not even made any allegations or statements of regarding dumping.
- ii. Further, the safeguard duty has been levied on sudden surge in imports into India as a whole, and not from any specific countries.
- iii. The Period of Investigation under the parallel Anti-dumping Investigation is subsumed within the Period of Investigation for the present.
- iv. The same Petitioners have themselves claimed dumping from the majority sources, i.e Korea, Taiwan and Israel to be causing injury.
- v. The Hon'ble Director General of Safeguards ought to reclude from proceeding further with the matter and refer the case to the Hon'ble Designated Authority.

- vi. There is no additional injury as claimed by the Petitioners as the imports have significantly declined in the period subsequent to the December-2010.
- vii. The Petitioners concealed the fact of approaching High Court of Bombay seeking the interim relief for extending safeguard duty for a period of 3 years as recommended.
- viii. The Period of Investigation comprises of data which is up to 28 months old distorting the injury analysis and are not the recent trends.
- ix. Petitioners selectively included and excluded producers to mislead (M/s S 1 Group has been excluded) which unduly benefits their claim of injury
- x. The Petitioners excluded M/s Asian Paints Ltd which manufactured 10,496 MT i.e. 44 % of the subject goods for non-captive purposes. Notwithstanding, the fact that Asian Paints is primarily consuming captively, their market view is independent.
- xi. The quantities imported by M/s IG Petrochemicals and Thirumalai Chemicals Ltd is significant and without justification, the injury claimed is self-inflicted.
- xii. The Domestic Sales of present Petitioners have consistently increased, whereas the Market share of imports has in fact declined in April-May 2011 to 26% as compared to 37% in Q1 of 2010-11.
- xiii. Average capacity utilization since the expansion in Q1-09-10, has been 77% whereas other factors have affected the production and capacity utilization of the Petitioners.
- xiv. Production of the Petitioners has increased by 8% as in Q4 – 11-12 as compared to Q4 – 08-09 whereas the sales of the Petitioners have increased by 23%. Further, as Domestic Sales to Production ratio of the Petitioners has significantly increased from 66% in Q4-08-09 to 75% in Q4 of 2011-12. Hence, the injury, if any is attributable to losses in the export markets and not otherwise.
- xv. The Balance Sheet of M/s IG Petrochemicals and M/s Thirumalai Chemicals shows significant profits during Financial Year 2009-10 & 2010-11. In fact, even in the first quarter of Financial Year 2011-12, the operating profits of IG Petro are 9.30 crores and in the case of Thirumalai it is 9.76 crores.
- xvi. The export of PAN from India to China attracts anti dumping duty. Hence, the decline in profits is clearly attributable to other factors and cannot be attributed to imports into India.
- xvii. The Annual Reports of the Petitioners amply clarify that the Petitioners rely upon domestic raw material which is abundantly available and ensures profitable sales.
- xviii. As imports made under advance license are utilised by the industrial end-users for export purposes, the said imports cannot cause any injury to the domestic industry.

ix. It is the change in the policy of the Government that has affected the industry and not the surge in imports.

xx. Post the reduction of customs duty from @ 30% to @ 7.5%, the Domestic Industry has resorted to seeking undue trade remedial protection.

xxi. DGSG has not considered the impact of the alleged dumped imports investigated in the parallel Anti-dumping Investigation concerning imports of Phthalic Anhydride from Korea, Israel and Taiwan.

xxii. The imposition of safeguard duty would escalate the price of PAN and adversely affect the plasticizer manufacturers and other dependant downstream industries making them unviable leading even to closure of the plants.

xxiii. Tariff protection of @ 2.5% in customs duty and abundant domestic supply of Ortho-xylene make Domestic Industry is clearly well placed in terms of supply and costs of raw materials.

xxiv. Petitioners have subsequent to the initiation of the present investigation already increased the prices and continue doing so to the disadvantage of the End-users.

xxv. The provision of an Adjustment Plan is a mandatory requirement under Rule 5(2) of Safeguard Rules to draw a rational connection between the measure and the objective of preventing or remedying serious injury and facilitating adjustment.

xxvi. As per the judgment in case of Assistant Commissioner, Commercial Tax Department v Shukla and Brothers the DGSG was liable to accept the submissions of the Association, prior to issue of the notification and expiry of extended time.

xxvii. The Import data submitted by Petitioners is inconsistent with the data filed in the anti-dumping petition, the findings in the earlier Safeguard Investigation as well as the said Preliminary Findings issued by the DG SG in the present case. In absence of an adequate and justified explanation, the data should be dismissed as unreliable.

xxviii. The DGSG has failed to disclose as to how the imports from developing countries has been worked out. The alleged injury, if any, to the Petitioners is from Korea RP, Taiwan and Israel for which a separate anti-dumping petition has been filed. Import analysis also focuses on these countries i.e. Korea RP and Taiwan.

11. Findings of the DG:

I have carefully gone through the case records, the replies filed by the domestic producers, user/importers, exporters and exporting nations. Submissions made by the various parties and the issues arising there-from are dealt with at appropriate places in the findings below.

a) The product under investigation: The product under investigation is Phthalic Anhydride (PAN) falling under heading 29173500 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (CTA). Phthalic Anhydride (PAN) is a principle commercial form of Phthalic acid. It is white crystalline solid, used to manufacture synthetic resins, which act as binders in paint products. The primary use of PAN is a chemical intermediate in the productions of plastics from vinyl chloride. Phthalate esters, which function as plasticizers are derived from PAN. PAN has

another major use in the production of polyester resins and other minor uses in the production of alkyd resins used in paints and lacquers; certain dyes, insect repellents and polyester polyols for polyurethanes. The chemical formula of PAN is C₈H₄O₃. It is produced by the catalytic oxidation of Ortho-xylene (OX) with air or by the catalytic oxidation of naphthalene. Domestic producers use the OX route. The process entails passing OX through a reactor, which is an arrangement of tubes of clay or porcelain rings coated with a catalyst. The oxidation process of OX coupled with post reactor polishing and flaking yields PAN in the form of white or pale yellow crystals. No interested party raised any issue with regard to the product under investigation. Therefore, it is confirmed that the product under investigation is "Phthalic Anhydride" falling under heading No 2917.3500 of schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. Further, no differences in the production process, characteristics or end-uses between imported PAN and domestically produced PAN were raised by any of the interested parties during the course of this investigation. Therefore, it is also held that domestically produced PAN falls under the ambit of like or directly competitive in all respects to the imported product under investigation and that the domestically produced PAN is a like article to the imported PAN within the meaning of Rule 2(e) of Safeguard Duty Rules, 1997.

b) Domestic Industry: There are five domestic producers in India who manufacture PAN. Three domestic producers namely - 1) Thirumalai chemicals Limited, Ranipet, Tamilnadu 2) IG Petrochemicals Ltd, Taloja, Maharashtra, 3) Mysore Petrochemicals Ltd, Raichur, Kamataka have joined the petition. The two producers namely, M/s Asian Paints Ltd and M/s S I Group India Ltd, have not joined the petition. Share of the three applicants varied from 86% to 87% during the period Q4 of 2008-09 to Q2 of 2011-12. Thus, the collective output of the applicant producers constituted a major share of the total production of PAN in India. Further no claim has been made by the interested parties against the applicants being the domestic industry. Therefore, it is held that the three applicant domestic producers constitute and represent the domestic industry(DI) within the meaning of required and defined under Sec 8B(6)(b)(iii) of the Safeguard Duty Rules 1997.

c) Period of Investigation (POI): The Customs Tariff Act, 1975, the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997, the Agreement on Safeguard and the relevant Article XIX of GATT do not specifically define what the Period of Investigation should be. From several case laws on safeguard measures, it is clear that neither the domestic laws on Safeguard nor Agreement on Safeguard and Art. XIX of GATT provides specific guidelines on the period of investigation except the fact that the relevant investigation period should be sufficiently long to allow conclusion to be drawn on increased import and serious injury. In the notice of initiation and preliminary findings, import data upto May 2011 had been considered. Now, the import data has been updated till Sep 2011. The period of investigation has been limited to the month of Sep 2011, as preliminary findings were issued on 23 September 2011. Further, a reasonably longer period has been considered to even out the effect of temporary fluctuations and seasonal effects, if any.

d) Source of data: The import data up to June, 2011 has been taken from DGCIS. Import data from July 2011 to Sep 2011 has been taken from IBIS. The data on various economic parameters submitted by the domestic industry in their petition till Q1 of 2011-12 has been verified by this directorate to the extent possible and the verified data has been taken into consideration for injury analysis. Only the data for Q2 of 2011-12 in respect of various economic parameters has been taken as furnished by the applicant.

e) Increased Imports: Phthalic Anhydride is imported into India from a number of countries, and primarily from Republic of Korea, Israel, Iran and Taiwan. The imports of Phthalic

Anhydride have shown an increasing trend in absolute terms as well as compared to the domestic production causing injury and serious threat of injury. The quantum of imports of Phthalic Anhydride during Q4 of 2008-09 to Q2 of 2011-12 remained as under:

Financial Year	Quarter	Total Imports (MT)	Domestic Production (MT)
2008-09	Q4	6103	49607
2009-10	Q1	7240	47985
	Q2	5163	58259
	Q3	8526	40437
	Q4	7169	52853
2010-11	Q1	23615	55503
	Q2	8611	58168
	Q3	18082	52319
	Q4	10933	51271
2011-12	Q1	9752	50124
	Q2	10436	51220

There is a surge in import both in absolute and relative terms. Imports have increased from 12403 MT in Q1 & Q2 of 2009-10 to 20188 MT in Q1 & Q2 of 2011-12 showing an increase of 63% in absolute terms. Further, in the most recent period, the imports in Q2 of 2011-12 have increased to 10436 MT from 9752 MT in Q1 of 2011-12 i.e. an increase of 7%. In relative terms also, though the share of import with respect to domestic production has shown decline in Q1-Q2 of 2011-12 from Q1-Q2 of 2010-11, but in the recent period it increased i.e. from 19.45 % in Q1 of 2011-12 to 20.37 % in Q2 of 2011-12.

It is thus seen that the volume of imports has surged both in absolute terms as also in relation to production. It is held that imports of Phthalic Anhydride have increased in absolute and relative terms and that the increase in imports has a rising trend which is significant enough to constitute "increased imports" within the meaning of Section 8B of the Act.

f) Unforeseen Developments: Slowdown in the end markets of Europe and America from 2009 onwards, and worsening scenario in the recent past due to the crises in Spain, Italy, Portugal, Greece, and Ireland has resulted in surplus production worldwide in comparison to available capacity because of the reason that plants have to operate at sufficient run rates in order to achieve economies of scale for effective production, hence, firms find it a difficult choice to cut rates. This has resulted in heavy surpluses for the industry which are being channeled into India – noticing India's growth prospects amidst a looming global recession. Anti-dumping duty on imports from Korea and Taiwan has been imposed by China and Pakistan in their respective countries for a period of 5 years. This has led to restriction on imports of Phthalic Anhydride from Korea and Taiwan to China and Pakistan. Due to such restriction, the export oriented producers and exporters mainly of Korea and Taiwan have started looking for new and existing market. The growing demand of Phthalic Anhydride in India and good market opportunity attracted the producers cum exporters of Korea and Taiwan to export in India which led to tremendous increase in Imports.

Export from Korea:

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12(first quarter)	2011-12(second Quarter)
Exports to India from Korea (MT)	14274	11167	30306	2763	5,749
Total PA Exports (MT)	37465	28098	61241	9752	10436
As a % of Total PA Exports	38%	40%	49%	28%	55%

Export from Taiwan:

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12(first quarter)	2011-12(second quarter)
Exports to India from Taiwan (MT)	4555	2099	12725	2581	1,813
Total PA Exports (MT)	37465	28098	61241	9752	10436
As a % of Total PA Exports	12%	7%	21%	26%	17%

(Source: DGCIS Data up to Jun, 2011 & rest taken from Petition)

As a result, it is seen that export of PAN from Korea to India increased from 14274 MTS in 2008-09 to 30306 MTS in 2010-11. This constituted about 49% of the total export of PAN to India in 2010-11 which has slightly come down to 28% in Q1 2011-12 but has again sharply increased to 55% in Q2 of 2011-12. Similarly from Taiwan, export of PAN increased from 4555 MTs in 2008-09 to 12725 MTS in 2010-11. This constitutes about 21% of the total export of PAN to India in 2010-11 which has risen further to 26% in Q1 2011-12 and thereafter has slightly come down to 17% in Q2 of 2011-12. This shows that rise in import of PAN from Korea and Taiwan is an unforeseen development resulting in increase in imports causing serious injury and threat of serious injury to the domestic industry.

g) Serious Injury and Threat of Serious Injury: : "Serious injury" means an injury causing overall impairment in the position of a domestic industry; and "threat of serious injury" means a clear and imminent danger of serious injury.

(i) The Article 4.2(a) of the Agreement on Safeguard and Annexure to Rule 8 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 technically requires that certain listed factors as well as other relevant factors must be evaluated to determine serious injury or threat of serious injury. However, these provisions do not specify what such an evaluation must demonstrate. Any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining". In one case, for example, there may be significant decline in sales, employment and productivity which will show "significant overall impairment" in the position of the industry, and therefore will justify a finding of serious injury. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate "significant

¹ Section 8B(6)(d) of the Customs Tariff Act, 1975.

overall impairment" of the industry. Thus, in addition to a technical examination of all the listed factors and any other relevant factors, it is essential that the overall *position* of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.²

ii) Accordingly, in analyzing serious injury or threat of serious injury all factors, which are mentioned in the rules as well as other factors which are relevant for determination of serious injury or threat of serious injury, have been considered. No single factor has been considered as dispositive. All relevant factors within the context of the relevant business cycle and conditions of competition which are relevant to the affected industry have been considered. The determination of serious injury or threat of serious injury is based on evaluation of the overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

h) **Injury:** It is held that the increased imports of Phthalic Anhydride have caused and are threatening to cause serious injury to the domestic producers of Phthalic Anhydride as indicated by the following factors:

i) **Market Share:** The share of imports in the domestic market with relation to production has gone up from 11% in Q4 of 2008-09 to 17% in Q2 of 2011-12. Similarly, the share of imports in the domestic market with relation to consumption has also risen from 16% in Q4 of 2008-09 to 19% in Q2 of 2011-12. It is also noticed that the market share of domestic producers in domestic consumption & production has fallen significantly. Applicants had an average market share of 86% in Q1-Q2 of 2009-10 which fell to 80% during Q1-Q2 of 2011-12, i.e. a decline of about 6%. The detailed chart showing increase in import's market share vis-à-vis production and consumption of the domestic industry is given below:

	2008-09	2009-10				2010-11				2011-12	
		Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Imports (MT)	6103	7240	5163	8526	7169	23615	8611	18082	10933	9752	10436
Domestic Production (MT)	49607	47985	58259	40437	52853	55503	58168	52319	51271	50124	51220
Total Qty Available (MT)	55710	55225	63422	48963	60022	79118	66779	70401	62204	59876	61656
Share of Imports (%)	11	13	8	17	12	30	13	26	18	16	17
Share of Domestic Production (%)	89	87	92	83	88	70	87	74	82	84	83
Domestic Sales by Industry (MT)	32613	35530	41289	39427	40696	39817	51007	38941	44553	38149	44670
Consumption in India (MT)	38716	42770	46452	47953	47865	63432	59618	57023	55486	47901	55106
Market Share of Imports (%)	16	17	11	18	15	37	14	32	20	20	19
Market Share of Domestic Industry (%)	84	83	89	82	85	63	86	68	80	80	81

ii) **Production:** The statistics relating to production pertaining to the domestic industry is shown above. The domestic production has been falling steadily from 58259 MT in Quarter 2 (2009-10), then 58168 MT in Quarter 2 (2010-11) and finally to 51220 MT in Q2 (2011-12). On annualized basis, production has declined in 2011-12 from 2010-11 level.

iii) **Capacity Utilisation:** Capacity utilization of the domestic industry has declined significantly in the most recent period, from 87% in Q2 of 2010-11 to 76% in Q2 of 2011-12. The plant of Mysore Petrochemicals is at present under shutdown for an indefinite period w.e.f 20.06.2011 due to accumulation of high stocks. The statistics relating to capacity utilization pertaining to the domestic industry is shown below.

² Based on Para 139 of Argentina footwear Case Appellate Body Report Of WTO

YEAR	QUARTER	PRODUCTION (MT)	INSTALLED CAPACITY(MT)	CAPACITY UTILISATION(%)	Inventory (MT)
2008-09	Q4	49607	59528	83	5365
2009-10	Q1	47985	67028	72	1604
	Q2	58259	67028	87	6101
	Q3	40437	67028	60	487
	Q4	52853	67028	79	4530
2010-11	Q1	55503	67028	83	4468
	Q2	58168	67028	87	2484
	Q3	52319	67028	78	9232
	Q4	51271	67028	76	5718
2011-12	Q1	50124	67028	75	8131
	Q2	51220	67028	76	8405

iv) **Inventories:** As the market share of the domestic industry is decreasing and that of imports are increasing, the domestic industry was unable to increase its sales volume and had to face the problems of accumulated inventories. The levels of inventories have increased significantly throughout the injury period. The table above depicts the inventory build up from 4530 MT in 2009-10 to 5718 MT in 2010-11 and further to 8131 MT in Q1 (2011-12) and to 8405 MT in Q2 (2011-12), almost doubling in 2011-12 from the 2009-10 level, reflecting the plight of the domestic industry. Further, the increase in inventories is despite suspension of production by one of domestic producers.

v) **Domestic sale:** The table below contains sales by domestic industry and total export.

Year	Quarter	Domestic Sale (MT)	Export (MT)
2008-09	Q4	32613	14183
2009-10	Q1	35530	16216
	Q2	41289	12471
	Q3	39427	6625
	Q4	40696	8114
2010-11	Q1	39817	15749
	Q2	51007	9146
	Q3	38941	6630
	Q4	44553	10231
2011-12	Q1	38149	9563
	Q2	44670	8312

(i) The Domestic sale grew from 41289 MT in Quarter 2 (2009-10) to 51007 MT in Quarter 2 (2010-11) but declined thereafter to 44670 MT in Q2 (2011-12). On annualized basis, production has declined in 2011-12 from 2010-11 level. Sales of the domestic industry increased till Quarter 4(2010-11) but declined during Q1 (2011-12). The reason of increase in sales volume till Q4, 2010-11 has been explained in the fact that one of the Indian producers who is also the petitioner has shifted from EOU to DTA and started selling in the Indian market which has led to increase in sales. The domestic industry claimed that since its EOU unit has become a DTA unit, it is natural that it is selling in the domestic market.

(ii) However, exports steadily declined from 12471 MT in Quarter 2 (2009-10), then to 9146 MT in Quarter 2 (2010-11) and finally to 8312 MT in Q2 (2011-12). Further, the export sales of

the DI have also shown continuously declining trend since Q4 of 2010-11 to Q2 of 2011-12 by about 19% which has accentuated the injury more.

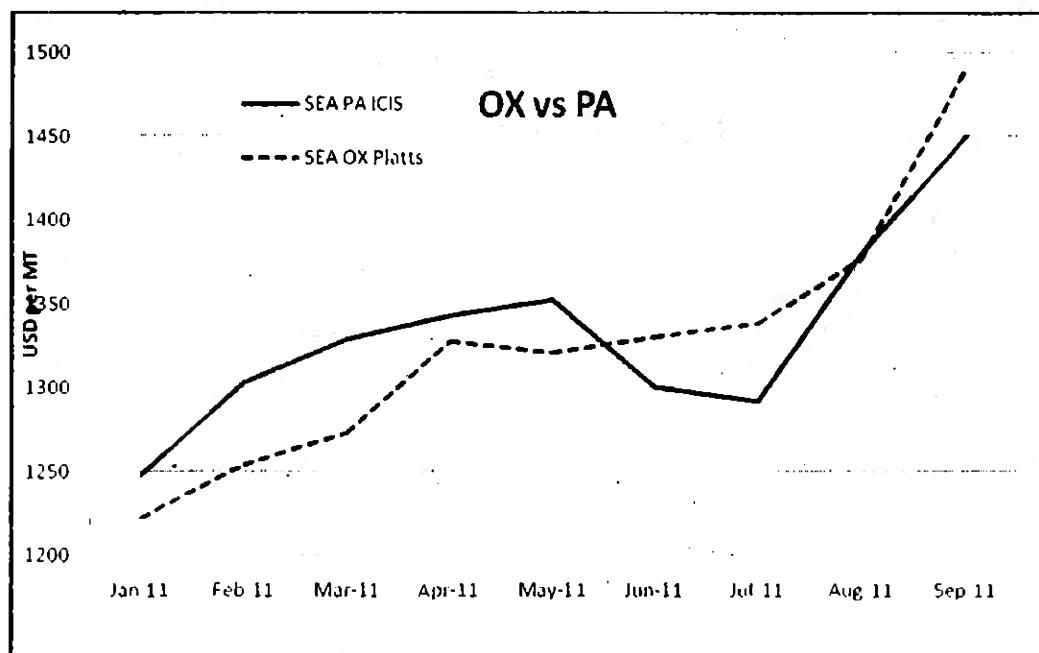
(iii) It is seen that to some extent demand of the product concerned has declined. Domestic industry claimed that this is due to the fact that producers of the downstream product Dioctyl Phthalate has started importing the downstream as its prices were coming down and found it more economical to import than producing in India. This has led to decline in demand of the PAN. The domestic industry is already faced with the problems of decline in demand, and then the increase in imports aggravated the injury already suffered. Domestic industry is being forced to export its production, despite significant domestic demand. Such exports are not a matter of choice, but a compulsion for the domestic industry, driven out of continuous increased imports of the product in the Country. Moreover, as is evident from the table above, even the exports have started declining in recent period aggravating the injury further.

vi) **Employment:** There is no significant change in the level of employment and in productivity over the injury period. It has shown normal growth over the period. Petitioner submits that these parameters are dependent on a number of other parameters and not reflective of impact of imports on the domestic industry.

vii) **Profit & Loss(Cash Profit):** The profitability of the domestic industry has steeply deteriorated to such a situation that the domestic industry is now suffering financial losses. This is evident from the table below:-

	Rs In Lakhs
Financial Year	Profitability
2009-10	2583
2010-11 (Q1)	-378
2011-12 (Q1)	-384
2011-12 (Q2)	-2111

It is held that sharp increase in the price of raw materials squeezed the profit margin of the domestic industry resulting in huge losses. Phthalic Anhydride (PAN) is primarily produced from oxidation of Ortho-xylene. Due to increase in prices of para-xylene, the producers shifted to the production from ortho-xylene to para-xylene which led to limited supply of ortho-xylene. Due to which the prices of ortho-xylene increased. The international prices of Ortho-Xylene have shown a steep rise between Feb,2011 to April,2011 and thereafter have been steadily rising whereas the price of PAN remained same or at times, from May,2011 onwards, declined in spite of increase in raw material cost and the trend of rising price gap continues in the recent period. These circumstances have resulted in huge financial losses suffered by the domestic industry as they are not able to recover even the raw material cost. This is evident from the graph below:



It has also been found that the import prices/landed prices of PAN are considerably lower than the selling prices of the domestic industry (confidential) which is evident from the table below:

Domestic Price Rs. Per Kg of PAN & O-Xylene(Indexed)			Import price Rs Per Kg	Landed Price Rs per kg
	PAN	O-Xylene	PAN	PAN
2010-11Q1	100	100	50.24	54.55
2010-11Q2	85	87	49.18	53.40
2010-11Q3	94	97	50.86	55.22
2010-11Q4	104	113	58.20	63.19
2011-12Q1	111	121	59.72	64.84
2011-12Q2	110	128	61.41	66.63

This is inevitable due to the fact that the domestic industry is under constraint to further reduce the domestic price of PAN for the reason that the prices of principal raw material ortho-xylene are at a very high level leading to the domestic industry under heavy strain to effect any reduction in the selling price of PAN. Consequentially, capacity utilization of the domestic producers had been 76% in Q2 of 2011-12 as compared to 87% during Q2 of 2010-11 as the production of PAN is not viable due to lack of profit margin in the product. Loss of production and inventory built-up has aggravated the injury.

viii) Other Factors of Injury:

Followings are relevant in this regard –

1. Possible decline in demand of the product: There is no contraction in demand of Phthalic Anhydride in India. Possible decline in the demand has not caused material injury to the domestic industry. Demand of the product in India has shown significant increase over the years.

2. Changes in the patterns of consumption: The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Changes in the pattern of consumption could not have contributed to the injury to the domestic industry.

3. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers: There is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

4. Export performance: Petitioners have exported the product under consideration. In fact, one of the petitioner companies, M/s. I.G. Petrochemicals was an EOU and has got itself converted into DTA unit within the current injury period. Volumes have declined in exports as well. However, the claimed injury to the domestic industry is on account of domestic operations. Petitioners have provided costing and injury information for domestic operation. Claimed injury to domestic industry cannot be attributed to exports.

5. Developments in technology: Technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.

i) **Public Interest:** The constituents of the domestic industry have already been forced to suspend the production. The law does not require plant shutdowns as a condition for imposition of safeguard duty. The landed price of imports is lower than the (a) selling price of the domestic industry and (b) cost of production of the domestic industry. The imports are significantly undercutting the domestic prices. The price undercutting is resulting in price suppression and depression. It would be seen that the selling price of the domestic industry is far lower than the cost of sales. In order to sustain in the market, the domestic industry has to reduce its prices far lower than the cost of sales thereby suffering huge losses. At times the domestic industry is forced to reduce its prices to the raw material levels. With the rate of decline in profits and return on investments, with non levy of safeguard duty, the domestic industry would be left with no option but to close down its business.

The imposition of safeguard duty would be in public interest as it will not only prevent injury to the domestic industry but also would help in checking further decline of the domestic industry. As regards the impact of safeguard duty on consumers/users, it is observed that PAN is primarily consumed in three segments, namely

In production of Plasticizers – about 60-70%.

In paints – about 20-30%

In pigments – 5-10%.

In most recent period, demand of PAN in DOP segment declined because of significant increase in DOP itself. Decline in demand for DOP led to overall decline in demand for PAN in the most recent period. Despite this decline in demand, imports of PAN have increased significantly.

The domestic industry has quantified the impact of 10% safeguard duty on eventual downstream products. It is found that the 10% increase on account of safeguard duty, if fully passed onto the eventual end product (assuming that the domestic industry increases the prices by 10%) would be as follows –

pipes 1.2%,

pigments 0.33% and

on paints 0.46%.

The above claim of domestic industry has not been disputed by the consumer associations present at the time of oral hearing. Nor the written submissions filed by any interested party contain any other quantified claim to the contrary. It should therefore be concluded that even if the prices increase by 10%, the impact of the same on the domestic industry would not be significantly adverse. The imposition will not result in significant increase in the prices of eventual end products.

Therefore the imposition of safeguard duty would be in public interest and especially the interests of end users are well protected.

j) **Adjustment Plan:** The petition is for imposition of safeguard duty only for one year. Therefore the details on efforts being taken and planned to be taken or both to make a positive adjustment to import competition with details of progressive liberalization adequate to facilitate positive adjustment of the industry is not mandatory under the rules.

k). **Causal Link between Increased Import and Serious Injury or Threat of Serious Injury:** The product is largely sold in comparison/competition with imports. The landed price of imports is significantly lower than the selling prices of the domestic industry. The domestic industry is losing sales opportunities. Consequently, production, capacity utilization, profits, return on investment and cash flow is declining due to continued presence of low price imports. Given the low prices offered by the foreign producers and clogging of the Chinese market, the imports are surging further despite low prices offered by the domestic industry. At times the domestic industry was forced to reduce its prices at raw material levels. Increased imports have led to increase in market share of imports and reduction in market share of the domestic industry. Decline in market share of the domestic industry has adversely impacted the production and capacity utilization of the domestic industry. It is thus evident that injury to the domestic industry has been caused by the increased imports.

l) **Developing Nations:** The percentages of imports from developing nations have also been examined. Except Pakistan, China and Thailand who constitute 3.34%, 3.43% and 11.83% respectively of total imports in India during FY 2010-11 and FY 2011-12 (Q1 and Q2), other developing nations individually and collectively have less than 3% and 9% share respectively of total imports in India. Therefore, the import of product under consideration originating from developing nations except Pakistan, China and Thailand may not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975. One of the interested party namely Indian Plasticizers Manufacturers Association through their consultant M/s ELP Advocates, have sought to know as to how the imports from developing countries have been worked out. It is clarified in this regard that the share of imports of PAN from developing countries taken together except Pakistan, China and Thailand comes to only 4.63% of total imports in India during FY 2010-11 and FY 2011-12 (Q1 and Q2) (Source-DGCIS import data and IBIS data).

12. Comments on views of Interested Parties:

The apprehensions raised by the interested parties through their written submissions post public hearing in the case, are dealt with in brief, party wise, for the sake of brevity.

A. Gadiv Petrochemicals Industries Ltd.

i) As regards the allegation that the import volumes do not show a clear upward trend, but rather a mixed trend of increases and declines, this is emphasized that the imports clearly

show a surge. While analyzing the imports, the DG(S) is required to evaluate whether any downturn in imports is simply temporary, or instead reflects a longer term change. In Argentina-Footwear(EC) case, wherein the Panel, in a finding, considered, in this connection, that an analysis of intervening trends of imports was indispensable:

“The question of whether any decline in imports is ‘temporary’ is relevant in assessing whether the ‘increased imports’ requirement of Article 2.1 has been met. In this context, we recall Article 4.2(a) ‘s requirement that the rate and amount of the increase in imports be evaluated.(39) In our view this constitutes a requirement that the intervening trends of imports over the period of investigation be analysed. We note that the term ‘rate’ connotes both speed and direction, and thus intervening trends (up or down) must be fully taken into consideration. Where these trends are mixed over a period of investigation, this may be decisive in determining whether an increase in imports in the sense of Article 2.1 has occurred. In practical terms, we consider that the best way to assess the significance of any such mixed trends in imports is by evaluating whether any downturn in imports is simply temporary, or instead reflects a longer term change.’

In the instant case, the imports have not only increased at a significant rate in 2010 but also in the most recent period.

ii) As regards analyzing trends of imports in relation to the domestic production instead of the domestic consumption, it is clarified that the trends of imports have been examined both in relation to domestic production and consumption. Further, the legal provisions require analysis of imports in relation to domestic production only. The relevant provisions are as follows:

Rule 2(c) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 - “Increased quantity” includes increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production;

Further, as regards contention that the imports from Israel have not increased, it is pointed that the pattern of imports from individual countries is of no relevance in a safeguard investigation.

iii) As regards allegation of upward trend in sales of DI, it is stressed that the sales of DI increased till Q4 but have declined during the recent period. The reason for increase is increase in demand, whereas the reason for decline in the sales volumes in subsequent period is surge in imports. There is no reason why domestic sales of the domestic industry should have declined so significantly after increasing upto a certain period except increased imports.

iv) When the raw material prices increase, the selling price of the product should also increase proportionately. But in this case, the DI were unable to increase their prices with the increase in prices of Orthoxylene i.e. raw material because of the presence of cheap imports. Despite demand of the product under consideration, domestic sales declined. The domestic industry has to also face the problem of decline in demand due to shift in down the line users of the product who resorted to importing DOP instead of PAN. However, the limited market is disproportionately being taken over by imports, by offering low prices thereby capturing the Indian market and causing injury to the DI.

v) As regards profitability of the DI, it is mentioned that Landed price of imports is lower than the selling price of the DI and even cost of production of DI. The imports are significantly undercutting the domestic prices. In order to sustain in the market, the DI has to reduce its prices

far lower than the cost of sales thereby suffering huge losses. At times, the DI is forced to reduce its prices to the raw materials level. This poses an imminent danger of their closure in near future in case preventive measures are not taken.

vi) The analysis of increased imports and injury thereof has not been isolated on the basis of Apr-May 2011 data [US — Line Pipe case]. That the Agreement on safeguards contains no requirements as to how long the period of investigation in a safeguards investigation should be, nor how the period should be broken down for purposes of analysis.

vii) So far as decline in demand and injury is concerned (i) the loss suffered by the domestic industry is more than the decline in demand, (ii) the domestic industry is already faced with the problems of decline in demand, and then the increased imports have aggravated the injury already suffered. The decline in demand should have impacted both the domestic industry and imports equally. It is however found that whereas the domestic industry is facing the brunt of decline in demand, the imports are surging further. It is natural that the domestic sales would increase, if one of the major company shifts to DTA from EOU.

viii) Besides, the Landed price of imports is lower than the (a) selling price of the domestic industry and (b) cost of production of the domestic industry. The imports are significantly undercutting the domestic prices. The price undercutting is resulting in price suppression and depression.

ix) Israel share in total imports is 13% which is a significant share. As it is general safeguard measure, individual country's share in the total consumption is irrelevant in the total injury analysis. The provisions of Rule 13 of the General Safeguard Rules is relied upon in this regard.

x) The normal tendency of the business is when the raw material prices increase, the selling price of the product should also increase proportionately. But in the instant case, the petitioners were unable to increase their prices with the increase in prices of Orthoxylene because of the presence of huge imports.

xi) The argument that unforeseen development can only be in the form of obligation incurred by India under GATT is without legal basis.

B. Government of Israel

i) As regards allegation that DI holds more than 80% market share, it is observed that the market share of the domestic industry has declined and given the nature of the product, production process and market, any drop in the market share can lead to significant injury. The DI cannot withhold inventories for a long period, nor can reduce the production off and on. Thus the only option to the DI to respond to low priced imports is to reduce the prices. Given low level of margins on which the domestic industry performs, any price reduction leads to significant injury to them.

ii) It is also relevant to point out that there is no evidence provided to establish that the product is suffering because of global recession. Thus, the claim is a mere statement unsupported by any evidence.

iii) As regards adjustment plan, it is observed that neither the WTO Agreement nor Indian Law mandates adjustment plan. Korea-Dairy case is cited wherein the panel rejected the view that Article 5.1 imposes an obligation to consider adjustment plans. The relevant extract is as follows:

"We wish to make it clear that we do not interpret Article 5.1 as requiring the consideration of an adjustment plan by the authorities ... The Panel finds no specific requirement that an adjustment plan as such must be requested and considered in the text of the Agreement on Safeguards. Although there are references to industry adjustment in two of its provisions, nothing in the text of the Agreement on Safeguards suggests that consideration of a specific adjustment plan is required before a measure can be adopted. Rather, we believe that the question of adjustment, along with the question of preventing or remedying serious injury, must be a part of the authorities' reasoned explanation of the measure it has chosen to apply. Nonetheless, we note that examination of an adjustment plan, within the context of the application of a safeguard measure, would be strong evidence that the authorities considered whether the measure was commensurate with the objective of preventing or remedying serious injury and facilitating adjustment."

C. Republic of Korea:

- i) Increased competition between domestic producers is not the cause of injury as alleged; the reason being the domestic producers have been competing during the entire period and therefore deterioration in the current period could not have been due to internal competition. Further, landed price of imports were lower than the selling price of the domestic industry. Thus imports being the lowest priced product, it is the imports that have led to adverse selling price of the domestic producers. It is the settled principle in a commodity product like the present that it is the lowest priced source that forces the other producers to reduce their price.
- ii) The argument that production of DI increased in proportion to capacity is factually incorrect. The capacity of the DI remained constant since Jan-Dec 2010 whereas the production of the domestic Industry declined in Jan 11 to March 11 and thereafter in Q1 of 2011-12.
- iii) As regards the argument that overcapacity in India is causing injury to the Industry, it is stated that some opposing party has argued that the DI does not have sufficient capacity and some interested party has argued that the DI has excess capacity. The DI has infact enough capacity to meet the demand in India. Inspite of the enough capacity in India, the DI is unable to produce or sell in the Indian market due to availability of cheap imports. This has resulted in decline in market share of domestic industry and increase in market share of imports. The DI is not saddled with such excessive capacity that the same could have caused injury to the DI.

D. Government of Taiwan

- (i) As regards argument that market share of domestic industry has increased and demand of PAN is higher than capacity, it is observed that market share of the DI increased till 2009-10 as a result of imposition of the saseguard duty. The imports declined significantly with the expiry of period of imposition of safeguard duty in Dec 2009. However, once the period of imposition of safeguard duty expired the imports started entering the Indian market at a significant rate capturing the market share of the domestic industry. Further, the DI in India has enough capacity to meet the entire demand in India.

E. Indian Paint Association

- (i) As regards the argument that there is variance in the import figures for 2010-11, it is clarified that Director General Safeguards has relied upon the figures provided by DGCIS for the major part of this year and only for last quarter the figures provided by the petitioners have been

taken. However, the imports are showing an increasing trend no matter what source is considered. Further, the data relied upon in the Preliminary Findings shows higher degree of surge than what the domestic industry had established. No prejudice has been caused by such difference in the data.

(ii) As regards the allegation that production has increased in 2010-11 as compared to 2008-09, it is clarified that the period of investigation is till May 2011 and therefore any trend has to be analyzed till the end of POI. The production of the DI has declined in April-May of Q1(2011-12) as compared to 2008-09 as has been stated in Preliminary Findings.

(iii) As regards the allegation that capacity utilization has declined significantly as Applicants had an average market share of 85% in 2009-10 which fell to 74% during 2010-11, which is at variance with the data on market share provided on page 5 of the PF, this is clarified that share of imports in the domestic market has gone up from 11% in Q4 of 2008-09 to 20% in Q1 (April-May) of 2011-12. Market share of domestic producers in domestic consumption has fallen significantly. Applicants had an average market share of 85% in 2009-10 which fell to 74% during 2010-11 i.e. a decline of about 11%. Figures mentioned in the page 5 of PF is the argument raised by the DI which is analysis of different economic parameter.

E. M/s KLJ Plasticizers

(i) As regards the argument that the producers are offering unrealistic prices which are higher than the prevailing international prices forcing local consumers to import material, it is clarified that due to the reason that international prices are lower than the domestic price, the imports have surged and the DI has requested for protection. The DI is suffering huge losses and are unable to recover even their cost at current prices. This clearly demonstrates the impact of low priced imports. If the DI were to further reduce the prices, the DI would suffer further financial losses.

(ii) Regarding allegation that majority of the imports are duty free and there is big demand for duty free imports and they should be excluded from the import figures, it is clarified that the DI is also catering to the duty free market. It is not established that all the imports were duty free. If this would have been the case, its volumes would not have declined after imposition of safeguard duty earlier. Since duty free imports are exempted from safeguard duty as well, the volume of imports should not have declined after imposition of safeguard duty. Clearly, there are other reasons and not all the imports are duty free.

(iii) Regarding allegation that DG Safeguards has levied duty against developing nations also which is against WTO Agreement, this is stated that the provisions of law in this regard have duly been followed and consequently duty on developing nations has been rightly imposed.

G. Indian Plasticizers Manufacturers Association

(i) As regards the allegation that the petitioners are not portraying the true state of affairs of the DI and conveniently excluding or including domestic producer that unduly befits their claim of injury, this is stated that SI group which is not included in the safeguard investigation accounts for mere 4% of the total domestic production and inclusion or exclusion of the said domestic producer would not materially change the overall picture of the state of DI.

(ii) As regards the argument that the rise in the import prices is greater than the rise in domestic prices of PAN, it is clarified that the rise in import price is less than rise in domestic industry prices. Rise in cost of sales is greater than rise in import prices clearly showing that the import prices were preventing the domestic industry from increasing the prices of the product under consideration in proportion to increase in cost of sales thus causing price suppression.

(iii) As regards the allegation that imports post period of investigation show decline, it is to clarify that decline in imports is direct consequence of the initiation of safeguard investigation and further price drop undertaken by DI. The competent authority is not bound to include the data post initiation of investigation. In any case, post initiation of investigation data will be influenced by the investigation itself and may not be reflective of the true market situation.

13. Provisional Measures: In the Preliminary Findings, it was held that increased imports of PAN have caused and threatened to cause further serious injury to domestic producers of PAN. It was also observed that critical circumstances existed, where any delay in application for safeguard measures would cause irreparable damage to the industry. Considering the serious injury suffered by domestic industry during the year 2010-11 and first two quarters of 2011-12 in a number of critical injury parameters as explained in the paragraphs above, it is held that the provisional measures were rightly recommended in this case in order to thwart the possibility of irreparable damage.

14. Conclusion and recommendation:

(i) In view of the findings above, it is concluded that increased imports of PAN into India have caused and threatened to cause serious injury to the domestic producers of PAN and it will be in the public interest to impose safeguard duty on imports of PAN into India, in terms of Rule 12 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules 1997, for a period of one year. Considering the average cost of production of PAN by the domestic producers, after allowing a reasonable return on capital employed, safeguard duty at the rate of 10% ad-valorem, for one year w.e.f. the date of imposition of provisional safeguard duty (i.e. 17 January 2012), which is considered to be the minimum required to protect the interest of domestic industry, is hereby recommended to be imposed on imports of Phthalic Anhydride falling under CTN 29173500 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975.

(ii) As the imports from developing nations except Pakistan, China and Thailand do not exceed 3% individually and 9% collectively, the import of product under consideration originating from developing nations except Pakistan, China and Thailand may not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.

[F. No. D-22011/8/2011/Part C/221]

INDRANI DUTT MAJUMDER, Director General